सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

11 मार्च, 2016

षोडश विधान सभा **शुक्रवार,तिथि 11 मार्च,2016**

द्वितीय सत्र **21फाल्गुन,1937(शक)**

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया **)**

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

प्रश्नोत्तर-काल

तारांकित प्रश्न सं0-1033(श्री जय वर्धन यादव)

श्री तेज प्रताप यादव **:** महोदय, 1. स्वीकारात्मक नहीं है ।

वस्तुस्थिति यह है कि जमुई ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत है । जिसका भवन ठीक है एवं चहारदिवारी का निर्माण नहीं हो सका है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है । स्वास्थ्य उपकेन्द्र में चिकित्सक का पद नहीं होता है । मात्र ए0एन0एम0 पदस्थापित होते हैं । बुधवार, शुक्रवार एवं विशेष टीकाकरण के अवसर पर ए0एन0एम0 के द्वारा कार्य किया जाता है ।

3. चहारदिवारी निर्माण करने की योजना तत्काल नहीं है । स्वास्थ्य उपकेन्द्र में चिकित्सक का पदस्थापन नहीं किया जाता है । 7 हजार ए0एन0एम0 की नियुक्ति हेतु अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है । अनुशंसा प्राप्त होने पर 2 ए0एन0एम0 की पदस्थापना कर दी जायेगी ।

श्री जय वर्धन यादव **:** महोदय, जैसा कि मैं पूरी जिम्मेवारी से बता रहा हूँ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कि पिछले एक हफ्ते पहले भी वहां गया था, जो स्वास्थ्य उपकेन्द्र है, उसकी जो बिल्डिंग है, वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और उसमें छत पर पौधा वगैरह निकल आया है । यह स्थिति है और हमेशा ताला बन्द रहता है । टीकाकरण के अवसर पर भी कोई नर्स नहीं आते हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात कराना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने अभी आपको बताया है, चहारदिवारी के संबंध में आपने कहा है कि वहां नहीं है और वहां कोई नियमित डॉक्टर का पदस्थापन भी नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य उपकेन्द्र में नहीं होता है और बुधवार और शुक्रवार को वहां ए0एन0एम0 जाते हैं और टीकाकरण का कार्य करते हैं । अगर आपको बुधवार, शुक्रवार के अलावे किसी दिन जाईयेगा तो स्वाभाविक है कि वह बन्द मिलेगा ।

श्री जय वर्धन यादव : महोदय, यह पटना जिला के सबसे कोने में पड़ता है जमुई गांव, जिसका उल्लेख हमने किया है और प्रखण्ड मुख्यालय से भी इसकी दूरी लगभग 12-15 कि0मी0 है तो उस स्थिति में वहां कम से कम एक ए0एन0एम0 की ही व्यवस्था वहां हो जाय तो बड़ी कृपा होगी ।

अध्यक्ष : ठीक है, मंत्री जी इसको देख लेंगे ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय सदस्य लिखकर दे दें, माननीय मंत्री जी इसको देखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1034 (श्री अशोक कुमार)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, वर्तमान में समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सतमलपुर में 1, मधुटोला में 1, शादीपुर टेंगराहा में 1, ताल ऐघरा में 2, रंजीतपुर में 1, गुदारघाट में 1, सोभन में 4 कुल 11 जले दोषपूर्ण 16, 25, 40 के0वी0ए0 के ट्रांसफर्मर है, जिन्हें 63 के0वी0ए0 ट्रांसफर्मर से बदलने का लक्ष्य अप्रील, 2016 तक निर्धारित है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1035 (श्री सरफराज आलम)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नौशाद आलम जी को अधिकृत किया है । प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य ।

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. रेफरल अस्पताल में सी0टी0 स्केन एवं ट्रॉमा सेन्टर का प्रावधान नहीं है । पी0पी0मोड में एक्स-रे सुविधा हेतु मशीन स्थापित की गई है, जिसे शीघ्र चालू करा दिया जायेगा । रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध होने पर अल्ट्रासाउण्ड सुविधा शुरू करने की कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-1036 (श्रीमती कुंती देवी)

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, 1. क्षेत्रीय उप निदेशक,गया को जॉच का आदेश दे दिया गया है।

2. उपर्युक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्रीमती कुंती देवी : महोदय, एक डॉक्टर भी ड्यूटी नहीं करते हैं । हमारे यहां बहुत विकट समस्या है ।

अध्यक्ष : उसी का माननीय मंत्री जी ने जॉच का आदेश दिया है क्षेत्रीय उप निदेशक को ।

श्रीमती कुंती देवी : जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-1037 (श्री संजीव चौरसिया)

श्री तेज प्रताप यादव : 1. स्वीकारात्मक नहीं है ।

उक्त क्षेत्र की आबादी को लगभग 5 कि0मी0 के दायरे में राजवंशीनगर अस्पताल, गार्डिनर रोड अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल एवं पी0एम0सी0एच0,पटना के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है । रेफरल अस्पताल बनाये जाने की योजना तत्काल नहीं है ।

श्री संजीव चौरसिया : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो वक्तव्य दिये हैं कि 5 कि0मी0 के रेंज में है । वास्तव में शास्त्रीनगर और गर्दनीबाग को छोड़कर पूरा निकटा दियारा से लेकर जो गरीबों की आबादी है, अगर नगर के दृष्टि से देखेंगे तो निकटा दियरा का बड़ा क्षेत्र है, बड़ी दूरी होती है उनको वहां से आने में कोई भी अस्पताल दीघा, मैनपुरा, पाटलीपुत्रा, राजीवनगर यह पूरा का पूरा क्षेत्र है, जो दानापुर से लेकर रामजीचक से लेकर पूरी की पूरी जो आबादी है, वहां गरीबों की, अतिपिछड़ों की, महादलितों की, बिन्द टोली की, सबकी तो वहां निश्चित रूप से बहुत ही आवश्यक है । जो पी0एच0सी0 भी उपलब्ध है, किसी में डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है, कम से कम चार-चार पी0एच0सी0 होना चाहिए, दो या तीन पी0एच0सी भी नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें कि आबादी के अनुपात पर लगभग सवा लाख के आबादी पर एक रेफरल अस्पताल खोलने की जो नीति थी, उसमें मंत्री जी की क्या योजना है ?

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, उसमें कोई योजना नहीं है । हमने बता दिया है कि राजवंशीनगर अस्पताल, गार्डिनर रोड अस्पताल, गर्दनीाबाग अस्पताल, दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में हमारे मरीज आकर चेकअप कराते हैं । इधर सरकार के तरफ से कोई योजना नहीं है ।

श्री संजीव चौरसिया : अधिनियम के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी की दृष्टि से रेफरल अस्पताल खोलने की योजना रहती है । इसलिए माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि जो रेफरल अस्पताल खोलने की नीति है, वह आबादी के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर ? जिस क्षेत्र का डिसटेंस का आपने आधार दिया तो आबादी के आधार पर होता है तो बड़ी आबादी है, इसलिए इस चीज को बताने का कष्ट करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने बता दिया है कि उस इलाके के लोगों को चिकित्सा सुविधा अलग-अलग अस्पतालों से दी जा रही है और इस इलाके में अभी कोई रेफरल अस्पताल खोलने की सरकार की कोई योजना नहीं है । सरकार ने बता दिया ।

श्री संजीव चौरसिया : महोदय, बड़ा विषय यह है कि दूरी काफी रहने के कारण और घनी आबादी है, जैसा मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया कि अगर आबादी की दृष्टि से बात करते हैं तो गर्दनीबाग का एक जोन है, शास्त्रीनगर का एक जोन है, उधर का पूरा जो पैच है, वह बड़ी आबादी है और पुरानी आबादी है और वहां अभी तक कोई अलग अस्पताल की बात नहीं की गई है, सरकार को इसपर विचार निश्चित रूप से करनी चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को आप लिखकर दे दीजियेगा, उसको देखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-1038(श्री (मो0) तौसीफ आलम)

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय,1. स्वीकारात्मक है ।

2. स्वीकारात्मक है ।

3. बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त हो गया है । महिला चिकित्सक का पदस्थापन शीघ्र करा दिया जायेगा ।

श्री (मो0) तौसीफ आलम : महोदय, एक समय-सीमा दे दिया जाय ।

अध्यक्ष : वे तो शीघ्र कर रहे हैं, अनुशंसा प्राप्त हो गई है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1039 (श्री अमित कुमार)

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, 1. आंशिक स्वीकारात्मक है ।

बेलगंज में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है । बल्कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं ।

2. स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन की मरम्मती का प्राक्कलन बनाने का निर्देश दिया गया है । राशि की उपलब्धता होने पर मरम्मती करायी जायेगी ।

श्री अमित कुमार : धन्यवाद ।

टर्न-2/अंजनी/दि0 11.03.2016

तारांकित प्रश्न सं0-1040(श्री महेश्वर प्रसाद यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

मुजफफरपुर जिला के गायघाट एवं कटरा प्रखंड में विद्युत आपूर्त्ति फ्रेंचाइजी मेसर्स एस्मेल विद्युत वितरण लिमिटेड, मुजफ्फरपुर द्वारा की जा रही है । फ्रंचाइजी इलाकों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत प्रारंभ करने हेतु फ्रेंचाइजी के साथ एकरारनामा शर्त्तों के अनुरूप कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है एवं ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य को शुरू करने का लक्ष्य मई, 2016 निर्धारित है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1041(श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गग्त पंचायत घुरलख स्थित राजकीय नलकूप का उर्जान्वयन कराना है । कार्य प्रगति पर है, अप्रील 2016 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1042(श्री सुरेन्द्र कुमार)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, 1- औराई एक विद्युत प्रशाखा है जो ढोली अवर प्रमंडल के अंतर्गत कार्यरत है । कटरा प्रखंड भी एक विद्युत आपूर्त्ति प्रशाखा है, जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रीब्युशन फ्रेंचाईजी के अंतर्गत कार्यरत है ।

2- औराई विद्युत आपूर्त्ति प्रशाखा में कुल 18,637 उपभोक्ता हैं, जिससे विद्युत विपत्र का भुगतान प्राप्ति हेतु दस रूरल रेभन्यू फ्रेंचाईजी नियुक्त हैं, इसके अतिरिक्त उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एवं सहज सुविधा केन्द्र पर भी विद्युत विपत्र के भुगतान प्राप्त किये जाते हैं ।

कटरा विद्युत आपूर्त्ति प्रशाखा में कुल 13,000 उपभोक्ता हैं, जिनके विद्युत विपत्र का भुगतान प्राप्ति हेतु कटरा ब्लॉक में कलेक्शन काउंटर स्थापित है । साथ-ही उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एवं सहज वसुधा केन्द्र पर भी विद्युत विपत्र के भुगतान प्राप्त किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त उक्त दोनों प्रशाखाओं के उपभोक्ताओं को ऑन-लाईन भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1043(श्रीमती कुंती देवी)

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

महिला चिकित्सक पदस्थापित नहीं है ।

2- बिहार लोक सेवा आयोग से महिला चिकित्सकों का अनुशंसा प्राप्त है । पदास्थापन अगले दो माह में करा दिया जायेगा ।

श्रीमती कुंती देवी : महोदय, महिला चिकित्सक का बहुत दिक्कत है ।

अध्यक्ष : सरकार दो माह में करा दे रही है ।

श्री राजीव नंदन : महोदय,मेरा भी प्रश्न है......

अध्यक्ष : तब तो आपका भी काम हो गया क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दो महीने में करा देंगे । आपका तो काम हो गया ।

श्री राजीव नंदन : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर पदास्थापित हैं, वे प्रतिनियुक्ति में जिला मुख्यालय में चले जाते हैं तो इसमें नीतिगत फैसला लेने की बात है ।

अध्यक्ष : सूचना दे दीजियेगा माननीय मंत्री जी को ।

तारांकित प्रश्न सं0-1044(श्री अमरनाथ गामी)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1045(श्री सत्यदेव सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक है ।

अरवल और जहानाबाद जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्ववर्त्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के अंतर्गत दक्षिण भारतीय कम्पनी मेसर्स चड़लवाड़ा इन्फ्राटेक, हैदराबाद को दिया गया है ।

2- कम्पनी के कार्य की गति काफी धीमी होने के कारण तथा लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किये जाने के कारण कम्पनी को नोटिश निर्गत किया जा चुका है । साथ-ही निविदा में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई के रूप में Liquidated Damage की वसूली की जा रही है ।

उक्त जिलों के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य निर्धारित समय-सीमा नवम्बर,2016 तक पूर्ण करने का निर्देश संवेदक को दिया गया है । कार्य में सुधार नहीं होने की स्थिति में संवेदक के विरूद्ध संविदा में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी तो सब कुछ बता दिये ।

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अगले बार भी मैंने प्रश्न किया था और जवाब आया था यही लेकिन जिस ठीकेदार ने काम लिया है और मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि कार्य की गति धीमी है तो क्यों नहीं उसका टेंडर रद्द करके दूसरा टेंडर आमंत्रित किया जाता हैं ताकि वे जल्दी कार्य शुरू कर दे ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैंने कहा कि उसके खिलाफ जो लिक्युडिटी का पैसा है, उसके जप्त की भी कार्रवाई की जा रही है । इन्स्ट्रक्सन भी दिया गया है, अगर उसके

बाद भी सुधार नहीं होगा तो नवम्बर तक का टाईम उसका फ्रेम है तो निश्चित रूप से कानून के मुताबिक कानूनी कार्रवाई करके एजेंसी को दंडित किया जायेगा ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि वे प्रयासरत हैं और सी0एम0डी0 बोर्ड में तीन बार मिटिंग कर चुके हैं, मैं भी वहां शामिल था और माननीय सदस्य भी रहे थे । लेकिन महोदय, वार्निंग के बाद भी बिल्कुल डेड उसका काम है और कितने दिनों में माननीय मंत्री जी इसको खत्म करके नये एजेंसी का बहाल करके कार्य शुरू करेंगे ?

अध्यक्ष : धन्यवाद देते हैं तो लेकिन क्यों लगाते हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैंने कहा कि नवम्बर तक उसको टाईम दिया गया है और दंड भी दिया गया है । अगर टाईम फ्रेम में नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण पूरे राज्य में हो रहा है । राज्य के बाहर की कम्पनियाँ लगी हुई है, जिनके मोनेटरिंग सिस्टम हेतु एक कार्यपालक अभियंता लगाये गये हैं लेकिन वह मोनेटरिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है । राज्य के बाहर की कम्पनियां माननीय सदस्यों के अनुरोध को ध्यान में नहीं लेती है और पूरे राज्य में वे कहते हैं कि बाहर की कम्पनी है तो वह स्वतंत्र है, इस राज्य के प्रशासन और कार्य के बाहर हैं । माननीय सदस्यों की राय नहीं ली जाती, कम्पनी कहती है कि हमारा एम0डी0 जो कहेगा, वही काम होगा तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसमें सुधार की स्थिति और जहां-जहां कम्पनियां समय-सीमा के अन्दर काम नहीं कर रही है, वहां विद्युतीकरण योजना सफलीभूत नहीं हो पा रही है । बिल बढ़ाकर अनावश्यक रूप से आता है तो इन सब चीजों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : ऐसी बात नहीं है । सवाल है कि आर0ई0सी0 जो है भारत सरकार का और्गेनाइजेशन है तो वह भी मोनेटरिंग करता है, थर्ड पार्टी से भी इन्सपेक्सन होता है और भुगतान सीधे भारत सरकार से होता है । फिर भी अगर माननीय सदस्य स्पेसिफिक किसी जगह की बात कहेंगे तो निश्चित रूप से उसपर कार्रवाई की जायेगी । लेकिन कलक्टर की अध्यक्षता में कमिटी भी है और निर्देश दिया जायेगा कि माननीय सदस्य के मीटिंग में ठीक से मोनेटरिंग करने का काम हो ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, कलक्टर की अध्यक्षता में कमिटी बनी हुई है, हमारा आग्रह सरकार से होगा कि बैठक में जिले के माननीय सदस्य को भी शामिल किया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, नेता विरोधी दल को मैं जानकारी दूं कि आपके ही सरकार के द्वारा यह निर्देश है कि एम0पी0 जो हैं, वे सेंट्रल रिसपोंर्स स्कीम के चेयरमेन होंगे और विभिन्न जिलों में सीनियरटी के आधार पर होंगे और उसमें एम0एल0ए0 भी मेम्बर हैं तो आप एम0पी0 को भी कहिए कि इसकी मोनेटरिंग करें, हमें कहां कोई एतराज है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1046(श्री नंद किशोर यादव)

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

मारूफगंज स्थित यमुना अस्पताल का भवन बना है किन्तु फर्श एवं शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है तथा बिजली कार्य बचा है । भवन निर्माण विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा है । भवन निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि निर्माण कार्य तीन माह में पूर्ण कर दें ताकि अस्पताल को चालू किया जा सके ।

अध्यक्ष : तीन महीना में तो हो ही जायेगा । हम उम्मीद करते हैं कि प्रभारी मंत्री के इस स्पष्ट जवाब से पूर्व स्वाथ्य मंत्री निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, मुझे लगता है कि विभाग ने पूरी जानकारी शायद मंत्री महोदय को नहीं दी है । यह अस्पताल बने हुए तीन साल से उपर हो गया और जहां तक मुझे शुरू में जानकारी थी कि निगरानी विभाग ने इसपर जांच प्रारंभ किया था । निगरानी के अधिकारी जो जांच कर रहे थे, उन्होंने जांच रिपोर्ट भी दे दी, उसके बाद भी निगरानी का क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूॅ कि निगरानी का क्लीयरेंस कबतक प्राप्त कर लेंगे और प्राप्त करने के बाद कितने दिनों में अस्पताल को चालू करेंगे ?

टर्न-3/शंभु/11.03.16

अध्यक्ष : उन्होंने तो सब मिलाकर के 3 महीने का समय दे दिया है कि 3 महीने में बनवा के करा देंगे । मंत्री ने स्पष्ट कहा है।

तारांकित प्रश्न सं0-1047(श्री मनोहर प्रसाद सिंह)

श्री तेज प्रताप यादव : 1- उत्तर स्वीकारात्मक नहीं है। कुमारीपुर स्वास्थ्य उपकेन्द्र में 2 ए0एन0एम0 पदस्थापित हैं, जो वहीं कार्यरत हैं। सिविल सर्जन, कटिहार को यह निदेश भी दिया गया है कि उक्त ए0एन0एम0 अपने उप स्वास्थ्य केन्द्र में ही कार्य करें।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : मंत्री महोदय को जो सूचना दी गयी है वह सूचना सही नहीं है।

अध्यक्ष : तो आप सही सूचना दे दीजिए।

तारांकित प्रश्न सं0-1048(श्री रवींद्र सिंह)

श्री राजीव रंजन सिंह : महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है।

2- स्वीकारात्मक है।

3- स्वीकारात्मक है।

4- प्रश्नाधीन योजना की प्रशसनिक स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, अरवल ने अपने पत्रांक-660, दिनांक 01.08.2015 द्वारा क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, मगध प्रमंडल, गया को भेजा है। क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, मगध प्रमंडल गया द्वारा कतिपय पृच्छा की गयी कि जिसके संबंध में जिला पदाधिकारी, अरवल द्वारा प्रतिवेदन सं0:107, दिनांक 25.02. 2016 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यान्वयन की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

श्री रवींद्र सिंह : महोदय, करीब करीब लगता है कि बहुत दिन हो गया वह दिये हुए डी0एम0 साहब को लेकिन अभी तक कोई टाइम का निर्धारण नहीं किया गया है कि कब तक वह कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष : रवींद्र जी, अब आपको नहीं पूछना है, चूंकि वे पूछना शुरू कर देंगे तो आप नहीं पूछ पायेंगे।

श्री रवींद्र सिंह : हमने तो माननीय मंत्री महोदय से पूछा कि कब तक किया जायेगा, भेजा गया है बहुत पहले ही, जो निदेश उसमें निर्धारित है। उसके बावजूद भी वहां से स्वीकृति नहीं मिल रही है, पैसा वहां मौजूद है और वह सड़क इतना जरूरी है कि दो क्षेत्र को वह जोड़ता है कुर्था और अरवल दोनों को जोड़ने का काम करती है वह सड़क। इसलिए समय सीमा निर्धारित कर दिया जाय कि कब तक स्वीकृति मिलेगी, जबकि पहुंच चुका है बहुत पहले, माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ।

श्री राजीव रंजन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया है उसको समय सीमा के अन्दर बांधा नहीं जा सकता है। उसके सरटेन गाइडलाइन हैं भारत सरकार के, चूंकि यह इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान का पैसा है और भारत सरकार का सरटेन गाइडलाइन है। मैंने बताया उत्तर में कि जो क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, मगध प्रमंडल ने क्वेरी किया था, जो पृच्छा की थी उसका

जवाब 25 फरवरी को जिलाधिकारी ने उनको दे दिया है और उनको दे दिया है तो हम समझते हैं कि क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी उसपर शीघ्र निर्णय लेंगे।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ उन्होंने स्वीकार किया है इस बात को कि योजना, जो भारत सरकार की योजना है आइ0ए0पी0 उसके अन्तर्गत यह काम कराया जा रहा है। मंत्री महोदय ने खुद भी अपने जवाब में इस बात को स्वीकार किया है कि वह इलाका आप जानते हैं नक्सल प्रभावित इलाका है और नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए एक योजना भारत सरकार चलाती है उसके लिए राशि आवंटित की गयी है। उन्होंने खुद भी इस बात को स्वीकार किया है कि 1 अगस्त, 2015 को क्षेत्रीय पदाधिकारी, गया के पास प्रशासनिक स्वीकृति के लिए गया और उसका जवाब जाता है 25 फरवरी, 2016 को। महोदय, यह जो इतना लंबा पीरियड है, 6-7 महीने का समय है तो इसमें माननीय मंत्री महोदय जानते भी हैं पुराने अनुभवी आदमी हैं कि प्रशासनिक स्वीकृति देने का भी एक नियम है। एक समय सीमा भी तय होता है। कोई अधिकारी सालों फाइल को रोककर रखे यह होता नहीं है। इसलिए जिन अधिकारियों ने विलंब किया है प्रशासनिक स्वीकृति देने में अनावश्यक रूप से भारत सरकार के द्वारा दिये गये नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए दिये गये पैसों के प्रशासनिक स्वीकृति में प्रशासनिक विलंब किया है, उनके उपर सरकार कौन सी कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री राजीव रंजन सिंह : माननीय सदस्य भी बहुत जानकार हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ वे इसको शब्दों में न घुमाएं। 25.08.2015 को भेजा गया है तो 9,10,11 चार महीन उधर और एक महीना इधर 5 महीना का हुआ। जब क्वेरी आता है तो क्वेरी का सीधे डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट अपने लेवेल से जवाब नहीं दे सकते हैं। चूंकि जो इन्टीग्रेटेड एक्शन प्लान में योजनाओं की अनुशंसा करने की जो कमिटी है उसके बाद सरटेन विभाग को वह आवंटित होता है, अगर कोई क्वेरी आयेगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस विभाग को क्वेरी का जवाब देंगे जो विभाग डी0पी0आर0 तैयार करता है। इसलिए इसमें कोई बहुत विलंब नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस मामले में क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी और जिलाधिकारी, अरवल को पत्र लिख दिया जायेगा कि शीघ्रातिशीघ्र इसपर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करें।

श्री नन्दकिशोर यादव : क्या यह बात सही है कि जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया है तब यह जवाब भेजा जा रहा है। 25 फरवरी के पहले माननीय सदस्य ने जब

प्रश्न कर दिया तब आपकी जागृति बढ़ी है। यह 6 महीने समय अगर कम नहीं लगता है आपको तो मुझे आश्चर्य है। अगर नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए 6 महीना के बावजूद प्रशासनिक स्वीकृति और क्वेरी का जवाब नहीं जाता है और आपको यह समय अधिक नहीं लगता है तो इस सरकार का भगवान मालिक है महोदय।

तारांकित प्रश्न सं0-1049/श्री अशोक कुमार

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : समस्तीपुर जिला के वारिसनगर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खानपुर प्रखंड के 33/11 के0वी0ए0 विद्युत् शक्ति उपकेन्द्र में है। 1.6 एम0वी0ए0 पावर ट्रांसफार्मर को 5 एम0वी0ए0 पावर ट्रांसफार्मर से बदल दिया गया है। खानपुर प्रखंड में नये मुख्यालय भवन, आवासीय परिसर तथा खानपुर मार्केट में अधिष्ठापित 100 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर को बी0आर0जी0एफ0 फेज टू योजना के अन्तर्गत 200 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर से बदलने का लक्ष्य अप्रैल, 2016 निर्धारित है।

तारांकित प्रश्न सं0-1050/श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम

श्री तेज प्रताप यादव : 1- स्वीकारात्मक है। उक्त दोनों रेफरल अस्पताल में महिला चिकित्सक का पदस्थापन अगले दो माह में करा दिया जायेगा।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न सं0-1051/श्रीमती प्रेमा चौधरी

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, स्वीकारात्मक नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि सदर अस्पताल हाजीपुर के ब्लड बैंक की स्टोरेज क्षमता मात्र 900 यूनिट है। इस क्षमता के अनुसार ब्लड बैंक रखा जाता है। ब्लड बैंक का स्टोरेज मात्र 35 दिनों तक हो सकता है। यदि किसी यूनिट की 35 दिनों की अवधि नजदीक रहती है तो उस ब्लड को उपयोग हेतु चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को भेज दिया जाता है। पटना ब्लड बैंक में रखे जाने की कोई सूचना नहीं है।

श्रीमती प्रेमा चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी कि इसको अपने स्तर से फिर से जॉंच करा लिया जाय। चूंकि यह सवाल मेरे पास आया है तभी हमने क्वेश्चन भी किया। वहां पर ब्लड बैंक नहीं रखा जाता है। यह जनहित का मामला है।

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, देखवा लेंगे।

तारांकित प्रश्न सं0-1052/श्री रामदेव राय

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : आप तो नन्दकिशोर बाबू, चुनाव हारने के बाद बहुत डिप्रेशन में हैं। भाई, 1900 डाक्टरों की बहाली की सूची आ गयी है। इसलिए माननीय मंत्री अगर कह रहे हैं तो.........

श्री नन्दकिशोर यादव : डिरेल तो आप हो रहे हैं। आप रामदेव बाबू का जवाब दीजिए न, जवाब रामेदव बाबू मांग रहे हैं और जवाब इधर दे रहे हैं।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : वह तो देंगे आप रामदेव बाबू की क्यों चिंता करते हैं।

श्री नन्दकिशोर यादव : घबड़ाते हैं क्या रामदेव बाबू से ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : रामदेव बाबू हमसे-आपसे सीनियर हैं। आप बैठिए न। अरे, और किसी से नहीं लेकिन पड़ोसिया से तो डरिये। ललन बाबू हैं ही आपको भीतर तक जानते हैं। अब कोई नहीं हटे इन्हीं को हटा दिया, बली का बकरा बना दिया। फिर भी ये समझ ही नहीं रहे हैं। न मंगल पाण्डेय हटे न मोदी जी हटे.............

श्री नन्दकिशोर यादव : आपका क्या हुआ, देख रहे हैं न! देख रहे हैं न कि कहां से कहां चले गये ?

टर्न-4/अशोक/11.03.2016

प्रश्न संख्या-1052 (श्री रामदेव राय)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननय मंत्री जी, प्रश्न का उत्तर दीजिए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : उत्तर स्वीकारात्मक है । बेगुसराय जिला के बछवाड़ा, भगवानपुर एवं मंसूरचक प्रखण्डों में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य ज्योति योजना के तहत मेसर्स इस्ट इन्डिया उद्योग लिमिटेड के द्वारा विद्युतीकरण किया जा रहा है, इसे पूरा करने का लक्ष्य अगस्त, 2016 निर्धारित है ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं इस सदन में 2005 से 2010 तक सदस्य था, उस समय भी भारत सरकार का गाईडलाईन था, और हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी भी घोषणा किये थे कि बिहार में ग्रमीण विद्युतीकरण योजना का कार्यक्रम 2009-10 के दौरान ही समाप्त होगा, आज फिर 2015 भी बीत गये, 2016 में अगस्त तक जायेगा, 2016 के बाद कितने वर्षो तक जायेगा- यह मैं

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ । 2016 के बाद कितने दिनों में यह कार्य पूरा होगा ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, पहले तो होता ही नहीं था । फिर दो-तीन बार नीतियां बदली, फिर आया ग्रमीण विद्युतीकरण योजना जिसमें हुआ कि केवल बी.पी. एल. को दिया जायेगा । फिर आया राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना जिसमें हुआ कि 250 की आबादी, हमलोगों ने काफी आवाज उठायी, पत्राचार किया, कई सवाल उठाया तो 250 हुआ,...

अध्यक्ष : वह सब तो रामदेव बाबू को पता होगा ही क्योंकि 1981-82 में ये ऊर्जा मंत्री थे ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : इसलिए मैंने कहा न उनको, यह मुझको पता नहीं था, तब तो इनके प्रश्न का उत्तर देना ही बेकार है...

अध्यक्ष : इसलिए हमने आपकी जानकारी में दिया न !

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : मैंने कहा कि अप्रील, 2016 तक का टारगेट है ।

श्री रामदेव राय : लास्ट पूरक पूछ कर छोड़ देता हूँ, क्यों मंत्री जी को पछाड़ें, बुजुर्ग हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ श्रीमान् कि बिहार में बिहार विद्युत बोर्ड हमारे सरकार के अधीन काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कम्पनियां तैयार हुईं, अैर कम्पनियों पर इन लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है - क्या माननीय मंत्री जी स्वीकार करते हैं ? यदि स्वाीकर करते हैं तो जांच कमिटी बना दी जाय कि क्यों इसमें विलम्ब हुआ ? क्या कारण है इसके औचित्य का ? विद्युतीकरण योजना इतना विलम्ब रहेगा ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : यह अनावश्यक बात है महोदय, कम्पनियां बिहार सरकार की है, टोटल बिहार सरकार के नियंत्रण में है, ऐसी कोई बातें नहीं है । हमने टारगेट बताया, वक्त लगता है हर घर को कनेक्शन देने में- सात निश्चय में वह वायदे भी है, अब कई तरह की योजना बदली, फिर उसका टेण्डर वगैरह होना, राजीव गंधी विद्युतीकरण योजना 90-10 था अब दीन दयाल उपाध्याय जी की योजना हो गई, 60: 40, फिर राज्य सरकार की राशि बढ़ गई 33 प्रतिशत तो हर हाल में दो साल का लक्ष्य है कि हर घर को बिजली मिले ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं लास्ट पूछता हूँ । मुझे माननीय मंत्री जी पर विश्वास है । आप पर विश्वास करने की बात करता हूँ तो आपके खुशी होनी चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए इस बात को । मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो भी काम आप पूरा करना चाहते हें 2016 तक तो जिस क्षेत्र के माननीय विधायक

हैं, उनसे अपने पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक कराते हये गुणात्मक कार्य कराने के लिए इंतजाम करायेंगे क्या ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : अगर माननीय सदस्य को किसी गुणवत्ता में दिक्कत होगी, कहीं कठिनाई होगी तो लिखकर भेजेंगे, अविलम्ब कार्रवाई होगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1053(श्री वीरेंद्र कुमार सिंह)

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । टोल से दो कि.मी. की दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र नवीनगर है । डेंगों में स्वास्थ्य उप-केन्द्र कार्यरत हैं । पीपरा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उप-केन्द्र संयुक्त रूप से कार्यरत है, मझियावां के नजदीक गोसाईडीह में स्वास्थ्य उप-केन्द्र कार्यरत है ।

2. स्वीकारात्मक नहीं है । उक्त स्वास्थ्य उप-केन्द्रों द्वारा जनता को स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है ।

3. विभाग में ऐसी सूचना नहीं है ।

4. टोल से दो कि.मी. पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नवीनगर है, वर्तमान में ग्राम टोल में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की योजना नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : महोदय, यह सूचना बिल्कुल गलत है ।

अध्यक्ष : कौन सी सूचना ?

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : जो अधिकारी सूचना दिये हैं दो कि.मी., मेरा वह गांव है, वहां से पांच कि.मी. की दूरी पर स्वास्थ्य केन्द्र है और जिन-जिन पंचायतो का मैंने वर्णन किया हूँ, उन पंचायतों की दूरी दस से प्रन्द्रह कि.मी. है, ये सब भ्रामक सूचना देते हैं । पीपरा में काई अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र और उप-स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, इसका भी मैं चैलेंजपूर्वक बात कर रहा हूँ- ये सब भ्रामक सूचनायें माननीय मंत्री को दी जाती है, मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ, तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मेरे पैतृक गांव में भी अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री तेज प्रताप यादव : महेदय, मैं जांच करवा लूंगा और जांच करके मैं दिखलवा लेता हूँ, इनका जो होगा उसको पूरा करा दिया जायेगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, मैं आपके माध्यम यह जानना चाहते है, माननीय मंत्री जी यह बताये कि कितनी जनसंख्या पर और कितनी दूरी पर प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोला जाता है ।

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय, यह क्योश्चन नहीं है । हमने इनसे बात किया, बीच में कहां से बोल रहे हैं ?

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या-1054 ।

श्री तेज प्रताप यादव : बीच में आप कहां से बोल रहे हैं, हमने उनसे सवाल किया, आप बीच में कहां से बोल रहे हैं ?

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, मंत्री महोदय को थोड़ी जानकारी दे दीजिए...

अध्यक्ष : दे दीजिए ।

श्री नंद किशोर यादव : मंत्री महोदय, थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, प्रश्न जब सदन के अन्दर आता है तो यह सदन की सम्पत्ति है और हर माननीय सदस्य को उस पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है, इसलिए आगे से कृपया ध्यान रखिये- ये सवाल मत खड़ा करिये कि आप क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं, हर सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है, महोदय, मैं केवल सुझाव दे रहा हूँ, सुझाव दे रह हूँ न - यह गलत बात है न ! ये कहेंगे कि क्या अधिकार आपको है, गलत है, हर को अधिकार है पूछने का ।

अध्यक्ष : माननीय नंद किशोर जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, कोई भी सदस्य अधिकृत है कोई पूरक पूछने के लिए इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन अभी तारांकित प्रश्न संख्या-1054 । श्री राम नारायण मंडल ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, बिना आसन की अनुमति से कोई पूरक नहीं पूछ सकता है ।

अध्यक्ष : बिना अनुमति के नहीं पूछ सकते हैं ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्वायंट ऑफ आर्डर । माननीय नंद किशोर जी ने ठीक प्रश्न किया, लेकिन बिना अध्यक्ष की अनुमति कोई पूरक प्रश्न पूछ सकता है क्या ?

अध्यक्ष : नंद किशोर जी ने भी ठीक कहा और आप भी ठीक कह रहे हैं, बिना अनुमति के नहीं पूछ सकते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1054(श्री राम नारायण मंडल)

(मा. प्रश्नकर्त्ता सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1055(श्री जय वर्धन यादव)

श्री तेज प्रताप यादव : महोदय,

1. स्वीकारात्मक है ।
2. स्वीकारात्मक है ।
3. निधि की उपलब्धता के आधार पर भवन के निर्माण की कार्रवाई की जा सकेगी ।

श्री जय वर्धन यादव : आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आग्रह होगा, जिस गांव की मैं बात कर रहा हूॅ, जिस गांव का मैंने उल्लेख किया है, पालीगंज प्रखण्ड मुख्यालय, सम्भवतः पटना जिला का सबसे बड़ा प्रखण्ड है, वहां के सुदूर एरिया में पड़ता है और 18 से 20 कि.मी. की दूरी है प्रखण्ड मुख्यालय से, पालीगंज से, तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कि इसको वे दिखलवा लें और जल्दी से जल्दी इस पर बस कार्रवाई कर दें ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1056(श्री शकील अहमद खॉं)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : कटिहार जिला में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम्य ज्योति योजना के अन्तर्गत किया जा रह है, कदवा प्रखण्ड के जाजा गांवा में कार्य प्रगति पर है, ग्राम तेतलिया में सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है, कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य दिसम्बर, 2016 है ।

टर्न-5-11-03-2016-ज्योति

श्री शकील अहमद खॉं : मंत्री महोदय असल में इन दो पंचायतों में विद्युतीकरण एक बड़ा प्रश्न है । सीमांचल के कटिहार जिले में ही उन पंचायतों के विद्युतीकरण के काम में थोड़ी तेजी आयी है लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे बिहार के आंकड़े के हिसाब से देखेंगे तो सीमांचल के कटिहार में और कटिहार जिले के तमाम पंचायतों में , खास तौर पर कदवा जो और भी पिछड़ा है , वह पूर्वी बेल्ट है , नदी के किनारे पर बसा हुआ वह गांव है वहॉं यह काम बहुत ही कमजोर है तो बुनियादी बात यह है कि इस पूरे बिहार में हमारा जो जिला है और जिले में हमारा प्रखण्ड है उसमें काम कमजोर है उसमें गति दिलवाने का प्रयास करेंगे ।

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या - 1057 श्री लक्ष्मेश्वर राय

श्री तेज प्रताप यादव : (1) महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । मधुवनी जिलान्तर्गत लौकहा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है । वहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जहाँ महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है ।

(2) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लौकहा में महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं होने के कारण पदस्थापित नहीं किया जा सकता है । सामान्य चिकित्सक का पदस्थापन दो माह में करा दिया जायेगा । 7 हजार ए0एन0एम0 अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है, अनुशंसा प्राप्त होने पर पदस्थापन किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या - 1058 डा0 सुनील कुमार

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : (1) आंशिक स्वीकारात्मक है । नालन्दा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ के विभिन्न मुहल्लों में कुछ पोल एवं जर्जर तार पूर्व में बदले गए हैं। वर्तमान में शेष जर्जर तार तथा पोल बदलने की कार्रवाई की जा रही है ।

(2) प्रश्न में वर्णित स्थान बैगनाबाद में एक कि0मी0 एल0टी0 लाईन में चार अदद पोल , चौखण्डी में 10 स्पेनं एल0टी0 तार, महलपर में 14 स्पेन एल0टी0 तार एवं 4 पोल एवं मगध कॉलोनी में 4 स्पेन एल0टी0 तार , नाग सिनेमा के पीछे 7 स्पेन एल0टी0 तार एवं एक अदद पोल बदल दिए गए हें । कुछ स्थानों पर संकीर्ण रास्ते अतिक्रमण तथा घनी आबादी होने के कारण पोल लगाने का कार्य संभव नहीं हो पा रहा है । इन स्थानों पर केबुल एवं तार बदलने का कार्य डी0आर0डी0एफ0 योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है । इस कार्य को दिसम्बर 16 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है ।

डा0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि हमने तो सिर्फ 6 मुहल्ले का नाम दिया है । बिहारशरीफ में ऐसे तीस मुहल्लें होंगे जहाँ पर तार जर्जर है और हर दिन किसी न किसी मुहल्ले में तार टूटता है और जो मंत्री जी को इन्फौर्मेशन दिया गया है तार बदल दिए गए हैं वह बड़ा बड़ा मुहल्ला है , एक गली का तार बदल देने से पूरा महल्ला बदलता नहीं है , हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं मंत्री जी से कि क्या दो महीने के अंदर बिहारशरीफ शहर के जर्जर तार को बदलने का विचार रखते हैं ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, माननीय सदस्य की सूचना को मैं ग्रहण करता हूँ और निश्चित तौर पर तार बदलने की कार्रवाई की जायेगी यह हमलोगों का प्रोग्राम भी है । लेकिन दो ही महीना में किया जायेगा क्योंकि आगे बरसात वगैरह भी आ

रहा है इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में इस काम का प्राथमिकता के आधार पर करा लिया जायेगा ।

डा0 सुनील कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हर मुहल्ले में कहीं न कहीं डेली कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं , बिजली के तार के अलावे ट्रांसफार्मर के अपग्रेडेशन का काम भी बिहारशरीफ में पेन्डिंग हैं । कृपया जल्दी करायेंगे तो विद्युत सुचारु रुप से दिया जा सकेगा ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या, ट्रांसफार्मर कहाँ अपग्रेडेशन योजना में है ।

डा0 सुनील कुमार : बिहारशरीफ में , 100 के0वी0ए0 से 200 के0वी0ए0 और 200 के0वी0ए0 से . . .

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : कहाँ ?

डा0 सुनील कुमार : यह प्रश्न में नहीं है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : ग्रीड मे न कह रहे हैं ?

डा0 सुनील कुमार : जी , जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद सयादव : अपग्रेडेशन चल रहा है, नो प्रौब्लेम और जर्जर तार को भी बदलने की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री नंद किशोर यादव : बी0जे0पी0 का आदमी जीत गया तो वहाँ क्या काम नहीं कराईयेगा ?

श्री बिजेन्द्र पसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, इनका खुरचन पड़ोसिया होने के नात प्राप्त नहीं हो रहा है इसलिए कैसे आपकी बात हम सुनेंगे ?

डा0 सुनील कुमार : बिहार की पहचान नालन्दा विश्वविद्यालय से होती है उस नालन्दा की मैं बात कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष : उसमें तो माननीय सदस्य नंद किशोर बाबू माननीय मंत्री जी ने तो कह दिया कि " नो प्रौब्लेम "अब कहाँ बचेगा प्रौब्लेम ।

<u>प्रश्न संख्या 1059 श्रीमती गायत्री देवी</u>

श्री तेज प्रताप यादव : (1) महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । प्रथम चरण में संजीवनी से राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं जिला अस्पताल में औन लाईन रजिस्ट्रेशन कर उन्हें मरीज नंबर दिया जा रहा है । दूसरे चरण में अन्य अस्पतालों में उसीं रजिस्ट्रेशन नंबर पर रोगियों के इलाज की सुविधा शुरु की जा रही है ।

(2) स्वीकारात्मक नहीं है ।

(3) उक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, बंद पड़ा है । आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि औन लाईन करने का कबतक विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने तो बताया है कि रेफरल अस्पताल में , सबडिवीजनल अस्पताल में और डिस्ट्रीक्ट अस्पताल मे यह कार्म जारी है दूसरी जगह और इसका आउटरीच बढ़ाने की योजना बाद में ली जायेगी ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, प्रश्न दूसरा है । जब माननीय सदस्या . . . .

अध्यक्ष : उन्होंने कहा प्रश्न कर योजना ठप्प है ।

श्री नंद किशोर यादव : जब माननीय सदस्या यह सूचना दे रही हैं कि वह आज भी प्रयास की है, कल भी प्रयास की हैं कि वह ठप्प है । तो मैं जानना चाहता हूँ मंत्री जी से कि क्या कृपया इसकी जॉच कराकर संबंधित लोगों पर कार्रवाई करेंगे?

अध्यक्ष : सरकार जॉच करा देगी ।

श्री तेज प्रताप यादव : देखवा लेंगे, जॉच करवा देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या दे दीजिये , जॉच करवा देंगे ।

प्रश्न संख्या 1060 श्रीमती गुलजार देवी

श्रीमती अनिता देवी : (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) जिला पदाधिकारी पत्रांक 786 दिनॉक 01-06-15 से प्रतिवेदित किया गया है कि हरनेश्वर स्थान में पर्यटक यदा-कदा आते हैं । पत्रांक 785 दिनॉक 01-06-15 से प्रतिवेदित किया गया है कि पारसमणी स्थान में साल भर में सिर्फ प्रखंड भर के लगभग 5000 व्यक्ति आते हैं । उक्त आलोक में पर्यटन विभागीय पत्रांक 2612 दिनॉक 13-8-15 से आश्वासन संख्या 530/13 को विलोपित करने का अनुरोध किया गया है । बिहार के प्रत्येक जिले में ऐतिहासिक , धार्मिक पर्यटन स्थल है जिनका पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास आवश्यक है । बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए एक महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय पर्यटन रोड मैप बनाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है जिसके आलोक में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को चिन्हित करते हुए चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जायेगा । इस हेतु सभी जिलाधिकारियों से पत्रोंक 163 दिनॉक 21-01-2016 द्वारा जिलावार सूचनाएं मांगी गयी है ।

श्रीमती गुलजार देवी : अध्यक्ष महोदय, हम मधुवनी जिला से आते हैं । एस्टीमेट वगैरह सब बनाकर सचिव स्तर तक अपने दौड़कर दिए हैं जो विभाग में रखा हुआ है , मंत्री जी बतायें कि कब वह बनेगा , जिला से कोई भी चीज मांगने की जरुरत नहीं है। एस्टीमेट हम अपने बैठकर बनवाये हैं और सचिव के पास यह रखा हुआ है , तीन जगह मेरे क्षेत्र में है ।

श्रीमती अनिता देवी : ठीक है, हम देखवा लेते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1061 श्री राघव शरण पाण्डेय

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : (1) आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अंतर्गत बगहा शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्त्ति संरचना सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य किया जा रहा है । उन्नयन का कार्य पूरा करने का लक्ष्य मार्च,2016 है ।

(2) बगहा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत आपूर्त्ति संरचना के सुदृढ़ीकरण , उन्नयन का 4.81 करोड़ रुपये से स्वीकृत राशि का कार्य आर0ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट- बी योजना के अंतर्गत किया जा रहा है । वार्ड नंबर 29 एवं अन्य वार्डों में बचे हुए बिजली सुधार एवं विद्युतीकरण का कार्य ए0पी0डी0एस0 योजना के अंतर्गत किया जायेगा । इस योजना के विस्तृत प्रतिवेदन की स्वीकृति विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदान की गयी है । कार्य के क्रियान्वयन हेतु निविदा के माध्यम एजेन्सी की नियुक्ति की जायेगी एवं कार्य को 3 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

टर्न-6/विजय: 11.03.2016

श्री राघव शरण पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न होगा जिस कंट्रैक्टर को जिस एजेंसी को यह काम दिया गया था उसको जो टारगेट मिला थ वर्क आर्डर में उससे ज्यादा लम्बाई तक कम करने के बाद भी काम अधूरा है क्या ? मेरी जानकारी में उसने अपना काम कर लिया है फिर भी काम अधूरा है और इससे संकेत मिलता है कि डी0पी0आर0 और वर्क आर्डर में काफी खामियां हैं । उसके लिए कोई जिम्मेदारी तय की गयी है क्या ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, प्रारम्भ में जो न्यु ए0पी0डी0आर0पी0 स्कीम चलाये गये थे उसमें इलाके में अपग्रेडेशन का स्ट्रेंथनिंग का था अब जो न्यु ए0पी0डी0आर0पी0 स्कीम चलाये गये हैं वह विस्तृत है कि हर कोई छुटेगा नहीं गरीब मोहल्ले में भी दिया जाना है । तो वह काम मार्च,16 तक कंपलीट करने को एजेंसी को दिया गया है । फेज-2 योजना के अंतर्गत जैसा मैंने जिक्र किया

कि 4.81 करोड़ की लागत से वो टेडर वगैरह की प्रक्रिया हो रही है इस महीने में उसको पूरा करने का लक्ष्य है ।

श्री राघव शरण पाण्डेय: महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार दूसरे एजेंसी को भी काम दिया गया है उसमें भी काफी कमियां है और कई दलित बस्तियों का घर छुट जा रहा है । तो पूर्ण विद्युतीकारण की परिभाषा क्या है ? जहां हम कहते हैं कि इस नगर में पूर्ण रूप से विद्युतीकरण हो गया है या होगा अमुक तारीख तक । क्या हर घर में कनेक्शन दे दिया जाएगा या नहीं ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: निश्चित रूप से हर घर को कनेक्शन दिया जाएगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1062 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

(प्रश्नकर्त्ता मा0 सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1063 (डा0 विनोद प्रसाद यादव)

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, उर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: 1. स्वीकारात्मक है । गया जिला के नगर पंचायत शेरघाटी में कठार मोड़ से अनुमंडल पदाधिकारी के आवास तक 70 अदद पोल लगे हुए हैं जिसमें प्राथमिकता के आधार पर चार अति जर्जर पोलों को बदला जा चुका है । पूरे लाइन के सुदृढ़ीकरण का कार्य बी0आर0जी0एफ0 योजना के अतर्गत किया जाना है जिसमें अन्य जर्जर पोलों को भी बदल दिया जायेगा । कार्य को जून, 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1064 (श्री मेवालाल चौधरी)

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य ।

श्री तेज प्रताप यादव: महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्क है ।

2. उत्तर स्वीकारात्मक नहीं है स्वास्थ्य उप केन्द्र चाखंड में 2 ए0एन0एम0 द्वारा स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है ।

3. राशि उपलब्ध होने पर भवन बनाया जाएगा । सभी भवन बनाने की योजना नहीं है ।

श्री मेवालाल चौधरी: महोदय, ए0एन0एम0 आती है लेकिन भवन किसी प्राइवेट घर में चल रहा है जिससे असुविधा होती है और अभी हाल मे ही मकान मालिक से कुछ झगड़ा होने के कारण महोदय कुछ प्रॉबलम हो जा रहा है । हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि भवन जितना जल्द हो बना दिया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1065 (श्री राजेश कुमार)

श्री तेज प्रताप यादव: 1. आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रखंड स्तर पर होता है । बरियावा पंचायत नवीनगर प्रखंड में है जहां स्वास्थ्य उप केन्द्र किराये के मकान में कार्यरत है ।

2. नवीनगर प्रखंड में रेफरल अस्पताल कार्यरत है जहां से स्वास्थ्य सेवायें दी जा रही है ।

3. पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री राजेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो दूरी मैंने कहा था कि दूरी वहां से 12 कि0मी0 है और वहां पर दलित एवं महादलित और पिछड़े समुदाय के लोग काफी है और एक रेफरल हॉस्पीटल कुटुम्बा में है और कुटुम्बा में सृजित पद ताकि 7 है जो कि अभी वर्तमान में 4 हैं । और वहां कोई विशेषज्ञ डाक्टर नहीं है वैकल्पिक रूप में वहां भी इलाज कराया जाय । तो सदन के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि यह बहुत बड़ा इलाका रेफरल हास्टपीटल भी कवर करता है तो इसमें एक महिला डाक्टर की प्रतिनियुक्ति बहुत ही निहायत आवश्यक है चूंकि 12 कि0मी0 आना और दिन भर समय बीत जाता है उनका मजदूरी भी छूट जाता है, सौ दो सौ रूपया गरीब दलित का खर्च भी हो जाता है और बिना इलाज कराये लौट जाते हैं । तो मेरा मंत्री महोदय से आग्रह होगा कि कम से कम जबतक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होता तो रेफरल हास्पीटल जो कुटुम्बा में है उसमें पूर्ण डाक्टर की प्रतिनियुक्ति कर दी जाय ।

अध्यक्ष: मंत्री जी संज्ञान में लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1066 (श्री महेश्वर प्रसाद यादव)

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री तेज प्रताप यादव: 1. आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कभी कभी अचानक एक बार ही मरीजों की संख्या बढ़ जाने के कारण ऐसी स्थिति हो जाती है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने पर कभी कभी बेड एवं चिकित्सा कर्मी की कमी हो जाती है।

3. सरकार इस समस्या को दूर करने हेतु गंभीर है । आवश्यकतानुसार बेड की संख्या को बढ़ाते हुए आवश्यक चिकित्सा कर्मी उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, उत्तर के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और अच्छा उत्तर इन्होंने दिया है।

अध्यक्ष: अब हम आगे बढ़ते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1067 (श्रीमती पूर्णिमा यादव)

श्री तेज प्रताप यादव: महोदय, स्वीकारात्मक नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि कौआकोल में रेफरल अस्पताल का भवन निर्मित है । वर्तमान में वहां सी0आर0पी0एफ0 का शिविर है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के द्वारा आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

श्रीमती पूर्णिमा यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि जो रेफरल अस्पताल वहां कौआकोल में स्थित है वह कब तक चालू हो जाएगा क्योंकि कौआकोल जो है वह काफी बड़ा प्रखंड है । घनी आबादी वाला क्षेत्र है और वहां मरीजों के इलाज में काफी असुविधा होती है । मरीजों की सुविधा को देखते हुए जल्दी से जल्दी उसको चालू कराया जाय ।

श्री तेज प्रताप यादव: महोदय, उसको शीघ्र चालू करवा दिया जाएगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1068 (श्रीमती रेखा देवी)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है । पटना जिला के धनरूआ प्रखंड अंतर्गत धनरूआ पावर सब स्टेशन की घेराबंदी सही अवस्था में है । पावर सब स्टेशन के बाहर विभाग की खाली पड़ी जमीन की घेराबंदी नहीं की गयी है जिसका निर्माण अगले 6 माह में कराने का लक्ष्य है ।

श्रीमती रेखा देवी: महोदय दस वर्षो से घेराबंदी ध्वस्त हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक अतिक्रमण हटाया जाएगा और घेराबंदी कराया जाएगा ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, मैंने कहा कि पावर सब स्टेशन अतिक्रमित नहीं है वहां घेराबंदी है जो अतिरिक्त जमीन है वह अतिक्रमित है जैसा माननीय सदस्या कह रही हैं 6 महीने के अंदर उसकी घेराबंदी कर दी जायेगी । अतिक्रमण अगर है तो अपने आप खाली करवा दिया जाएगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1069 (श्री मुन्द्रिका सिंह यादव)

श्री चंद्रशेखर: यह ग्रामीण विकास को स्थानान्तरित है ।

यह ग्रामीण विकास विभाग को स्थानान्तरित है और प्रश्न अभी स्थगित होता है । अगली तिथि को मंत्री बतायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1070 (श्री मो0 तौसिफ आलम)

श्री तेज प्रताप यादव: 1. आंशिक स्वीकारात्मक है । महिला चिकित्सक का पद रिक्त है 6 बेड अच्छी स्थिति में है ।

2. आंशिक स्वीकारात्मक है । अन्य दो चिकित्सक कार्यरत हैं जिनके द्वारा कार्य किया जा रहा है ।

3. महिला चिकित्सकों का पदस्थापन अगले दो माह में करा दिया जाएगा।

श्री मो0 तौसिफ आलम: अध्यक्ष महोदय, डाक्टर की समस्या तो हल हो गयी महोदय । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष: श्री तौसिफ जी, आप प्रश्न में जो सुविधा चाहते हैं महिला चिकित्सक के लिए वह माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दो महीने में उपलब्ध करा देंगे । इसके अलावा कुछ चाहते हैं ?

टर्न-7/बिपिन/11.3.2016

अध्यक्ष : तौसीफ जी, आप इसके अलावे भी कुछ चाहते हैं ?

श्री मो0 तौसीफ आलम: बेड सुविधा नहीं है महोदय । वहां से जिला मुख्यालय 90कि.मी. है, और डेलिवरी पेशेंट जब होता है, 90कि.मी. जाते-जाते या तो कोई हादसा हो जाता है या दूसरे अस्पताल में जाना पड़ता है, इसलिए माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से चाहेंगे कि वहां बेड की सुविधा कर दी जाए । बेड की बहुत खराब और दयनीय स्थिति है ।

अध्यक्ष: प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हैं उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाए ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 11मार्च, 2016 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कुल दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह एवं माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 99(1) एवं (2) के तहत् दोनों कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किया जाता है ।

शून्यकाल

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिले के बैकुण्ठपुर, सिधवलिया, बरौली प्रखण्डों सहित पूरे राज्य के गरीबों को प्राप्त होने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, नि:शक्तता) पिछले 9 महीनों से बंद है, जिससे राज्य भर के करोड़ों लाभुकों में आक्रोश व्याप्त है । होली के पूर्व उक्त पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाय ।

महोदय, यह बड़ा गंभीर मसला है और हमलोग लगातार मिटिंग में डी. एम. के साथ बैठ रहे हैं और एक ही जवाब आ रहा है कि कम्प्यूटराइज्ड किया जा रहा है । महोदय, होली बीत जाएगा, उसके बाद पेंशन भी मिलेगा तो गरीबों को फायदा नहीं होगा । आग्रह है कि इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए ।

श्री राणा रणधीर: अध्यक्ष महोदय, मोतिहारी जिले के फेनहारा प्रखण्ड में फेनहारा हाई स्कूल चौक से परसौनी गांव तक की सड़क पिछले 10वर्षों से मरम्मती कार्य नहीं होने के कारण जर्जर हालत में है, यह सड़क शिवहर जिला से जोड़ता है । अत: जनहित में उक्त सड़क का निर्माण कार्य यथाशीघ्र करायी जाय ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखण्ड में पुनपुन नदी से ग्राम-मोगलानी करमा, सोनउरी तथा बारून प्रखण्ड के देवड़ही सोहदा, रिउर में कटाव से गांव के दर्जनों घर और जमीन क्षतिग्रस्त हो रहा है ।

अत: उक्त गांवों में नदी किनारे तटबंध बनाने की सरकार से मांग करता हूं।

श्री विनोद कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, उत्तरी बिहार के कोशी तथा महानंदा नदियों का तटबंध क्षतिग्रस्त हो चुका है, बाढ़ से पूर्व कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, अररिया जिला सहित 20जिलों के अन्तर्गत पड़ने वाले तटबंधों की मरम्मति अविलम्ब कराई जाए ।

श्री विजय कुमार खेमका: अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिलान्तर्गत स्वास्थ्य प्रशिक्षकों को प्रखण्ड स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जिम्मेवारी नहीं सौंपे जाने से स्वास्थ्य समिति की

पारदर्शिता बाधित है । जिले के सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य समिति द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अनियमितता बरती जा रही है । यही स्थिति राज्य के अन्य प्रखंडों में भी है।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग से अधिसूचना भी इसके लिए जारी है और विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम में पल्स पोलियो, टीकाकरण आदि अनेक कार्यक्रम हैं, जिसे स्वास्थ्य समिति लागू करती है ।

अत: जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्रीमती भागीरथी देवी: अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत प्रखण्ड गौनाहा के ग्राम मर्जदी मर्जादपुर में हड़बोड़ा नदी के ध्वस्त एप्रोच का जीर्णोद्धार कराने की मांग करती हूं ।

इस संबंध में पहले से शून्यकाल डाल रही हूं लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हो रही है महोदय । इस पर ध्यान दिया जाए महोदय ।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, अमर शहीद जगदेव प्रसाद सदर अस्पताल जहानाबाद का टी.बी. सेन्टर का भवन जर्जर हालत है । इसी में चिकित्सक एवं कर्मचारी कार्य करते हैं, फलस्वरूप किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है और लोगों की जान जा सकती है ।

अत: इस गंभीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस जर्जर भवन के निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्र कागज पर चल रहे हैं । महिलाएं और बच्चे पोषाहार एवं अन्य देय सुविधाएं से वंचित हैं । यही स्थिति पूरे राज्य की है ।

अतएव आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुव्यवस्थित रूप से चलाने की मांग करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, डी.एम.सी.एच., दरभंगा में कैंसर विभाग का भवन वर्षों पूर्व बनकर तैयार है परंतु उसमें चिकित्सा कार्य चालू नहीं किया गया है ।

अत: डी.एम.सी.एच., दरभंगा में कैंसर विभाग के लिए बने भवन में कैंसर विभाग को स्थानान्तरित कर चिकित्सा कार्य प्रारंभ करने की मांग करता हूं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, कटिहार सहित सरकार राज्य स्तर पर शहरी क्षेत्र में फुटपाथी दुकानदारों के लिए भेन्डिंग जोन चिहित् एवं विकसित कर उन्हें आवंटित करे ।

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत दरौली प्रखण्ड के ग्राम रामपुर में आग लगने से दर्जनों गरीबों का घर जल गया । प्रशासन द्वारा मामूली राहत राशि देकर गरीबों को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया है ।

स्थिति यह है कि अगजनी पीड़ित परिवार भूखमरी के शिकार हैं। गर्मी के महीना शुरू होते ही अगलगी की घटना शुरू हो जाती है । अगलगी की इस घटना का शिकार सबसे ज्यादा गरीब होता है । उनका सब कुछ जल कर राख हो जाता है और उनके पास कुछ नहीं रह पाता है ।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि पीड़ित परिवारों को अनाज, बरतन, पक्का मकान और सभी थानों में अग्निशामक गाड़ियां दिया जाए ।

महोदय, यह गंभीर मामला है ।

अध्यक्ष : इसीलिए मामले की गभ्भीरता बरकरार रहने दीजिए ।

श्री विद्यासागर केशरी: अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के पीपरा पंचायत के पीपराघाट पर परमान नदी पर पुल नहीं रहने से बांस चचरी पुल के सहारे आम नागरिक एवं छात्र-छात्राएं पठन-पाठन हेतु नदी पार कर फारबिसगंज जाते हैं । बरसात में चचरी पुल बह जाने से तीन माह लोगों का आवागमन नहीं हो पाता है ।

महोदय, एस.एस.बी. केन्द्र नजदीक है । सीमाक्षेत्र में बहुत सारी परेशानी होती है । इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इसको जल्द-से-जल्द बनाया जाए ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, राज्य में अतिक्रमण मुक्ति के नाम पर पटना सहित सभी शहरों में कई वर्षों से बसे हजारों परिवारों को बिना स्थायी आवासन की सुविधा दिये उजाड़ दिया गया । इन्हें स्थायी आवासन प्रदान की जाय ।

श्री ललन पासवान: अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अन्तर्गत प्रखंड-शिवसागर, पंचायत-महम्मतपुर के ग्राम-महम्मतपुर के मैदान में राजकीय और राष्ट्रीय स्तर के पहलवान दंगल प्रतियोगिता में प्रतिवर्ष 50 वर्षों से आते हैं, मैदान में स्टेडियम नहीं है ।

सरकार से मॉग करते हैं कि उक्त मैदान में स्टेडियम का निर्माण शीघ्र करावें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिला सहित पूरे बिहार में हजारों कमजोर वर्ग के गरीब परिवार फुटपात और स्लम बस्तियों में रहने को मजबूर हैं । सरकारी सुविधाओं से वंचित है ।

अत: सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को स्थायी घर, राशन किरासन सहित सरकारी सुविधा मुहैया करावें ।

अध्यक्ष महोदय, यह गरीब से जुड़ा मामला है । सरकार गरीबों के प्रति जो सात निश्चय की बात कर रही हैं तो शुरूआत यहां से होना चाहिए ।

टर्न-8/राजेश/11.3.16

अध्यक्षः- ध्यानाकर्षण सूचना ।

ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकारी वक्तव्य ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमारः- महोदय, यह बड़ा ही गंभीर सवाल है और कई माननीय सदस्यों ने राज्य में रहने वाले स्लम बस्तियों में अति पिछड़ा वर्ग के लोग, महादलित वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। पटना राजधानी में महोदय वे 50 वर्षों से रह रहे हैं, सरकार उनको उजाड़ने का काम कर रही है, सरकार ने एक नीति बनायी है महोदय ....(व्यवधान)

अध्यक्षः- माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद आप अपने ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़े।

श्री सुदामा प्रसाद, श्री सत्यदेव राम एवं श्री महबूब आलम, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री सुदामा प्रसादः- महोदय, पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत गौनाहा पंचायत के धमौरा गॉव में वर्ष 1970-71 में 99 दलितों एवं आदिवासियों को गैरमजरुआ जमीन का पर्चा मिला था लेकिन वहॉ के प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा रामनगर की रानी जयंती विक्रमशाह की जमाबंदी में जोड़कर गरीबों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है तथा भूपति मार्कण्डेय पाण्डेय के निधन के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हो रही है जबकि मार्कण्डेय पाण्डेय का कोई वंशज नहीं है।

अतः जनहित में गरीबों के बीच इस तरह की भूमि के आवंटन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

डा0 मदन मोहन झाः- महोदय, समय चाहिए।

श्री प्रेम कुमारः- अध्यक्ष महोदय, स्लम एरिया में गरीबों, दलितों, महादलितों, अतिपिछड़ों के घर को उजाड़ा जा रहा है, यह सरकार के इशारे पर उनको उजाड़ा जा रहा है, महोदय, यह बड़ा ही गंभीर सवाल है ....(व्यवधान)

अध्यक्षः- माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री प्रेम कुमार जी ध्यानाकर्षण सूचना भी महत्वपूर्ण है। आपने तो अपनी बात रख दी है ....(व्यवधान)

माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना ।

श्री कपिल देव कामतः- महोदय, "बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 सह पठित बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा- 31(4), 59(4) तथा 86(4) के तहत स्थानीय निकाय से संबंधित स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार का 31 मार्च, 2013 एवं 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सदन के पटल पर रखता हूँ।"

अध्यक्षः- अब सभा की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न-09/कृष्ण/11.03.2016

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निमन प्रकार किया जाता है, इसी में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :-

राष्ट्रीय जनता दल	:	59 मिनट,
जनता दल (यू)	:	52 मिनट,
भारतीय जनता पार्टी	:	39 मिनट,
इन्डियन नेशनल कांग्रेस	:	20 मिनट,
सी0पी0आई0(एम0एल0)	:	02 मिनट,
लोक जनशक्ति पार्टी	:	02 मिनट,
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	:	01 मिनट,
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	:	02 मिनट,
निर्दलीय	:	03 मिनट ।

कुल -180 मिनट ।

प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें।

श्री महेश्वर हजारी: अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 31मार्च,2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिये 34,09,36,39,000/- (चौंतीस अरब, नौ करोड़, छत्तीस लाख, उनचालिस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री सुनील कुमार, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री नीरज कुमार सिंह एवं श्री मिथलेश तिवारी से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जो व्यापक हैं, जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-वमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें । आपका 15 मिनट समय है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि
इस शीर्षक की मांग राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार विमर्श करने के लिये 10/-रूपये घटायी जाय ।

महोदय, इतनी बड़ी विडम्बना पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी कि बिहार में 35 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया, 15 वर्षों तक राजद ने राज किया और 10 वर्षों तक नीतीश जी ने राज किया और तीनों मिलकर बिहार की बदहाली के लिये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दोष देते हैं । राज किया बिहार में इस महागठबंधन ने, आज बदहाली है बिहार की, आज स्थिति खराब है बिहार की और दोष दे रहे हैं प्रधान मंत्री मोदी जी को और मंत्री जी भी अपने भाषण में वही करनेवाले हैं अध्यक्ष महोदय ।

कितने हैं बेचैन नगर के लोग,
वजीर को क्या मालूम ?
जल जमाव,मच्छर,कूड़ों से तंगहाल हैं लोग यहां के,
इनको क्या मालूम ?

अध्यक्ष महोदय, शहर के चेहरे से ही राज्य का चेहरा झलकता है, या यह कहें कि उन्नत शहरें ही राज्य के विकास का पैमाना होता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । लेकिन जो स्थिति है बिहार की और पटना राजधानी है, देश के सबसे खराब, गंदे 10 शहरों में हमारी राजधानी पटना है। इससे ज्यादा बिहार के शहर की स्थिति क्या खराब हो सकती है? भारत सरकार जो सर्वेक्षण करवाती है, 3-4 सालों से प्रतियोगिता चल रही है, कभी सबसे गंदे शहरों में पटना 2 नंबर पर रहता है, कभी सबसे गंदे शहरों में पटना 3 नंबर पर रहता है और यह पूरे देश के सर्वेक्षण में आता ही आता है, साथ में उच्च न्यायालय भी कहता है कि पटना देश का सबसे गंदा शहर है । अध्यक्ष महोदय, आज बिहार के शहरीकरण की आबादी मात्र 11.30 प्रतिशत है जबकि देश में लगभग 33 प्रतिशत शहरीकरण है । आज राज्य में शहरीकरण की आबादी की स्थिति बहुत खराब है और सरकार ने इस पर गंभीर चिन्तन भी नहीं किया । माननीय मंत्री जी कह दिये कि 10 हजार से ऊपर की जो पंचायतें होगी, उसको हम नगर निकाय, नगर पंचायत बनायेंगे । लेकिन चुनाव की घोषणा हो गयी, सभी जगह

पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव हो रहे हैं । लेकिन माननीय मंत्री अखबार में बयान छापने के लिये बोल दिये और इसको कहीं भी लागू नहीं किया गया । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि हरेक प्रमंडल में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन किया जायेगा । 2006-07 में तत्कालीन सरकार के नगर विकास मंत्री ने जब प्राधिकरण हटाया जा रहा था, कोई नई मांग नहीं है, बिहार के हर प्रमंडल में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण थी । लेकिन जब 2006-07 में प्राधिकरण को हटाया जा रहा था, उस समय तत्कालीन नगर विकास मंत्री जी ने विरोध किया था लेकिन प्रदेश के मुखिया के जिद के कारण जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकार थे, उनको समाप्त कर दिया गया और माननीय मंत्री जी आये और फिर से घोषणा किये कि हर प्रमंडल में हम क्षेत्रीय विकास प्राधिकार बनायेंगे । लेकिन इनका जो वक्तव्य है, इनका जो भाषण है, उसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कि क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण कब बनेगा, क्या बनेगा ? इनको अपनी कार्य योजना बतानी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, देश में शहरी गरीब परिवारों का राष्ट्रीय औसत 23.5 प्रतिशत है और बिहार में शहरी गरीब परिवारों का औसत 45 प्रतिशत है । जो हालत हैं, 2010-15 में सुशासन के कार्यक्रम तय हुये थे । सभी विभागों में सुशासन के कार्यक्रम तय हुये थे, नगर विकास विभाग में भी सुशासन के कार्यक्रम तय हुये थे और इस सुशासन के कार्यक्रम में एक साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी खुद नगर विकास विभाग में मंत्री के रूप में काम किये थे और इस सुशासन के कार्यक्रम की जो स्थिति है, मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इस सुशासन में 7 बिन्दु थे । उसमें पहला बिन्दु था - सभी शहरी क्षेत्रों में कचड़ा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जायेगी, जिसका आवश्यक्तानुसार जन निजी भागीदारी का उपयोग किया जायेगा । ये सुशासन के कार्यक्रम थे अध्यक्ष महोदय । आज 5 साल बीत गये, अभी तक पूरे बिहार में जो कचड़ा प्रबंधन की स्थिति है डोर टू डोर कचड़ा उठाव अखबार के माध्यम से आज 3-4 सालों से आ रहा है, घर-घर से कचड़ा संग्रह करेंगे, कचड़ा उठायेंगे । साफ-सुथरा बिहार बनायेंगे । लेकिन आज तक कचड़ा प्रबंधन से लेकर कचड़ा उठाव की कोई सही नीति तय नहीं हुई है । अखबार में कभी भी घोषणा हो जाती है, दरभंगा में भी चार-चार लेबर दे दिये गये, डोर टू डोर कूड़ा उठाव के लिये । लेकिन पूरे बिहार में कहीं भी घर-घर कचड़ा उठाव नहीं हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, सुशासन के कार्यक्रम में यह भी था कि फूटपाथ दुकानदारों और ठेला भेंडरों की सहायता के लिये समेकित नीति तैयार कर कार्यान्वित किया जायेगा । आज चार वर्षों से हर प्रतिवेदन में भेन्डिंग जोन की

चर्चा होती है लेकिन अध्यक्ष महोदय, कहीं भी भेन्डिंग जोन नहीं बनाया गया । माननीय मंत्री जी यह को बताना चाहिए । गरीब फूटपाथ दुकानदार जो शहरों में अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उच्चतम न्यायालय का आदेश है बिना उनको बसाये हुये, कोई उसको उजाड़ नहीं सकता है ।

क्रमश :

टर्न-10/सत्येन्द्र/11-3-16

श्री संजय सरावगी(क्रमश:): गरीब की जो हालत है अध्यक्ष महोदय,वो हमेशा पुलिसिया रौब के शिकार होते रहते हैं और कहीं भी आजतक किसी को बसाया नहीं गया और हर शहर में पुलिस निकलती है और उनको उजाड़ देने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय,आजतक वेडिंग जोन कहीं भी दिया नहीं गया इन फुटफाथ दुकानदारों के लिए। अध्यक्ष महोदय,सुशासन के कार्यक्रम में यह भी था कि पटना सहित प्रदेश के सभी मुख्य शहरों में ट्रॉफिक जाम से निजात पाने के लिए समेकित अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन योजना तैयार की जायेगी, जो हालत है पूरे बिहार के सभी शहर जाम से बिलबिलाते रहते हैं अध्यक्ष महोदय। कोई ऐसा शहर नहीं है, इस योजना का क्या हुआ इस पर जरूर माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहिए। सभी शहर जाम रहते हैं, जो हालत है चाहे पटना हो ,दरभंगा हो,मुजफ्फरपुर हो या बिहारशरीफ हो। दरभंगा से लहेरियासराय तक जाने में यह 5 कि0मी0 जाने में अध्यक्ष महोदय 45-50 मिनट लगता है यह हालत जाम की है। अध्यक्ष महोदय, मुक्ति धाम योजना भी इस सुशासन के कार्यक्रम का अंग था कि हम मुक्ति धाम योजना के तहत श्मशान घाट बनायेंगे, विद्युत शवदाह गृह का निर्माण किया जायेगा लेकिन आज तक अध्यक्ष महोदय मुक्ति धाम योजना धरातल पर लागू नहीं हुई और जहां-जहां मुक्तिधाम योजना लागू हुई, वहां कार्य प्रारम्भ हुआ बने लेकिन वहां उपयोग नहीं हो रहा है। दरभंगा में भी पांच साल पहले मुक्तिधाम बनकर तैयार हुआ आजतक जो है उस मुक्तिधाम में जो है काम प्रारम्भ नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय, सुशासन के अंग में यह भी कार्यक्रम था कि प्रमुख शहर में आबादी के बढ़ते दवाब के आलोक में सेटेलाईट शहरों की स्थापना हेतु कार्रवाई की जायेगी। कितने सेटेलाईट शहर बनें,यह माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय,नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय किया था बिहार में भी 3 स्मार्ट सिटी जो है बनने का तय हुआ और पहले वर्ष में जो 20 स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय भारत सरकार ने

किया बिहार सरकार की अदूरदर्शिता नीति के तहत उस 20 में से एक भी स्मार्ट सिटी जो है बिहार को नहीं मिली। इन्होंने जो योजना बनाकर भेजी वह योजना स्मार्ट सिटी की योजना नहीं थी अध्यक्ष महोदय नाली गली का बनाकर भेज दिया स्टीमेट, इसके कारण जो है बिहार पहला वर्ष जो बीस शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया, बिहार जो है उससे बंचित रह गया। अध्यक्ष महोदय यह विभाग पिछले एक साल में जो राज्य के सभी विभाग हैं उसमें कम राशि खर्च करने वाला विभाग रहा है। 100 करोड़ रू0 इससे वापस ले लिया गया इस विभाग से इन्होंने खर्च नहीं किया पैसा। पिछली बार 250 करोड़ रू0 योजना मद में नगर विकास विभाग का वित्तीय उपबंध कम किया गया और 250 करोड़ कम देने के बाद भी जबकि शहर विकास का पैमाना होता है अध्यक्ष महोदय, तब भी यह खर्च नहीं कर सकें और जो खर्च किये वह राशि अभी बुडको में पड़ी है या नगर निकायों में पड़ी है। कहीं भी जनता के लाभ के लिए वह राशि उपयोग में नहीं आयी है अध्यक्ष महोदय । जहां भी नगर निकाय है अध्यक्ष महोदय पांच-पांच साल तक राशि पड़ी हई है खर्च नहीं हो रही है हमारे दरभंगा में भी अध्यक्ष महोदय चार साल पहले दुलाल चौक से टिन्ही पुल के लिए 8 करोड़ की योजना स्वीकृत है। मंत्री जी ने जाकर शिलान्यास किया अब समझ लीजिये अध्यक्ष महोदय तीन साल उस राशि को गये हुए हो गया लेकिन अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। कहां से कहां उसका प्राक्कलन बढ़ गया होगा। गरीबों की आवास राजीव आवास, योजना के तहत पक्का घर मिलेगा पूरे बिहार में सैंकड़ों करोड़ रू0 गरीबों के आवास के लिए दिये गये लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूॅं माननीय मंत्री जी को, दरभंगा में 2012 में राजीव आवास स्वीकृत हुए, तीन साल बीत जाने पर मात्र 100 आवास पर कार्य प्रारमभ हुआ है। साढ़े उन्नीस सौ राजीव आवास गरीबों को आजतक नहीं दिया गया अध्यक्ष महोदय, यह केवल दरभंगा की बात नहीं पूरे बिहार की बात है जो हालत है अध्यक्ष महोदय पटना की जलापूर्त्ति योजना माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पांच साल में हम घर घर पाईप से पानी पहुंचा देंगे केवल एक उदाहरण देना चाहता हूॅं इससे बड़ा असत्य कुछ नहीं हो सकता है अध्यक्ष महोदय मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूॅं दरभंगा की जलापूर्त्ति योजना का 2006 में शिलान्यास हुआ। 10 साल बीत गये 41 करोड़ की योजना है लेकिन अभी तक एक बूंद पानी प्रारम्भ नहीं हुआ,अभी 30 प्रतिशत पाईप लगना बाकी है अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री को बतलाना चाहिए उसमें इतनी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच करावें। अभी तक पानी क्यों नहीं निकला? यह माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय नुरूम के अन्तर्गत शहरों के लिए बस हेतु राशि मिली है अध्यक्ष महोदय नगर विकास नें राशि दे दी परिवहन विभाग को और परिवहन विभाग नगरीय सेवा के नाम पर दरभंगा से कुशेश्वरस्थान, दरभंगा से लौकहा, दरभंगा से लौकही इससे बड़ा शहर के साथ कोई

मजाक नहीं हो सकता है। शहर में नगरीय बस सेवा के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा चला रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से मैं मांग करना चाहता हूॅ आप पता कीजिये टाउन सर्विस के नाम पर दरभंगा कुशेश्वर के नाम पर बस चलायी जा रही है। दरभंगा लौकहा, दरभंगा लौकही अध्यक्ष महोदय शहर का पैसा दूसरे जगह उपयोग हो रहा है जो कहीं से भी उचित बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी मिथिला से आते हैं और इनके प्रतिवेदन में कहीं भी मिथिला या दरभंगा का एक शब्द नहीं है। अध्यक्ष महोदय जहां के माननीय मंत्री जी हैं, उस मिथिला का कहीं कोई शब्द नहीं है,कहीं कोई विकास की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री नगर विकास एक पैसा नहीं दिया गया। पिछली बार राशि का उपबंध नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय पिछली बार में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना में बजटीय उपबंध नहीं किया गया। हमलोगों ने हस्तक्षेप किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी विधान-सभा में कहा कि कहीं गड़बड़ी हुई होगी लेकिन इस बार भी राशि नहीं है और आगे भी यह योजना चालू रहेगी या नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यह योजना को बंद कर दिया गया अध्यक्ष महोदय, दरभंगा का डी0पी0आर0 बनाने हेतु रूसा कम्पनी को दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी तीन साल पहले दरभंगा में जाकर घोषणा करते हैं और तीन साल हो गया आज तक जो है वह डी0पी0आर0 जल जमाव की समस्या के संबंध में था पूर्ण नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हॅू। धन्यवाद।

श्री नवाज आलमः अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2016 नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट पर सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूॅ साथ ही साथ मैं कटौती का प्रस्ताव का विरोध करता हूॅ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इस सदन में बैठे हुए सदन के नेता तमाम लोग का आभार प्रकट करता हूॅ और आरा के सरजमीन के तमाम लोगों का जिन्होंने आज यहां हमें बोलने का मौका देने का काम किया है। महोदय,आपके सामने सबसे पहले हमारे संजय सरावगी जी जो कुछ बातों को रख रहे थे मैं उनके ऊपर एक शेर कहते हुए अपने बजट भाषण को शुरू करना चाहता हूॅ।

है कसमाकस मताय दिल, (मतलाये दिल का मतलब दिल की आवाज)
शुरू करूं मैं कहां से, पहले
हरेक चेहरा ये कह रहा है,
यहां से पहले, यहां से पहले।

अध्यक्ष महोदय, आपके सामने 2016-17 के बजटीय भाषण में जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बजट में राशि आवंटित की है

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में उसका मैं इस सदन के माध्यम से पुरजोर समर्थन करता हूॅ और उसकी भूरि भूरि प्रशंसा करता हूॅ इसलिए कि आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजटीय जो आवंटन राशि का प्रावधान किये उसमें सबसे पहले(क्रमशः)

टर्न-11/मधुप/11.03.16

मो0 नवाज आलम : ...क्रमशः... सबसे पहले पूरे विश्व के पैमाने पर देखा जाय अध्यक्ष महोदय, आधी आबादी शहरों में निवास करती है । एशिया में लगभग 36 परसेंट लोग शहर में निवास करते हैं, इसी तरह से यूरोप में लगभग 75 परसेंट लोग शहरों में निवास करते हैं, अमेरिका में 80 परसेंट लोग शहरों में निवास करते हैं, उत्तरी अमेरिका में 78 परसेंट लोग शहरों में निवास करते हैं । इसका कारण क्या है, महोदय? मेरा मानना है कि सरकार के द्वारा जरूर आधारभूत संरचना लोगों के लिये निर्माण किया गया होगा, वहॉ व्यवस्था की गई होगी । यही कारण है कि देहात की अपेक्षा शहर में लोग ज्यादा रहने का काम करते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण निश्चित रूप से, यह विडम्बना है कि हिन्दुस्तान में जहॉ गॉव की आबादी की अपेक्षा शहर में लोग कम निवास करते हैं ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री हरिनारायण सिंह ने आसन ग्रहण किया)

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से कुछ आग्रह प्रस्तुत करना चाहता हूॅ । माननीय मुख्यमंत्री का एक सपना है कि तमाम हिन्दुस्तान में जो बड़े-बड़े महानगर हैं, जैसे मुम्बई है, कोलकता है, दिल्ली है, चेन्नई है, उनकी तुलना में कैसे हम बिहार को नक्शा पटल पर लाने का काम करें । उसी की कड़ी में आरा नगर निकाय का गठन किया गया । नगर निकाय का गठन इसलिए किया गया, जो नगर परिषद् थे, जो नगर पालिका थे, उनमें 11 को नगर निगम का दर्जा दिया गया । यह एक सराहनीय कदम था । पटना अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखता है । यह अजीमाबाद और कभी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था । यह वही सरजमीं है जहॉ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, यह वही सरजमीं है जहॉ भगवान महावीर का जन्म हुआ, यह वही सरजमीं है जहॉ याहिया मनेरी का जन्म हुआ है । इसलिए ऐसे ऐतिहासिक भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से योजना चलाने का काम किया है ।

आज हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि पटना गंदा नजर आता है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इको पार्क बनाया गया, बुद्धा पार्क बनाया गया, अनेक पार्क बनाये गये, क्या यह सुंदरता का प्रतीक नहीं होता है ? निश्चित रूप से प्रतीक होता है । इसलिये मैं अपने इस बजट भाषण में माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोर प्रशंसा करता हूँ । सभापति महोदय, हम सदन के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि सूबे में सबके लिए आवास हो, इसके लिए सरकार ने बहुत बड़ी पहल की थी आदरणीय लालू यादव ने । लोग कहते हैं जंगलराज । जंगलराज की परिभाषा, आदरणीय लालू यादव के ऊपर मैं एक शेर अर्ज करता हूँ -

''हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में एक दीदावर पैदा ।''

सभापति महोदय, लालू यादव ने जब मलिन बस्तियों को बसाने का काम किया, अंबेदकर कॉलोनी बसाने का काम किया, जग गरीबों को शहरों में बसाने का काम किया तो ये लोग कहते हैं - जंगलराज है ।

सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री और माननीय मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, निश्चित रूप से.....

(व्यवधान)

मो0 नवाज आलम : बजट पर ही बोल रहे हैं । महोदय, घर-घर शौचालय की व्यवस्था, घर-घर में पीने के पानी की व्यवस्था, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या यह योजना सचमुच में सराहनीय योजना नहीं है ? राज्य आवास बोर्ड द्वारा सदन के तमाम सदस्यों को भी उन मकानों में आवंटित करने का काम किया जायेगा, इसके लिए मैं माननीय मंत्री की सराहना करता हूँ । बजट में प्रावधान किये गये तमाम योजनाएँ निश्चित रूप से सराहनीय हैं ।

सभापति महोदय, आरा के सरजमीं के ऊपर हम कुछ चीजों को रेखांकित करना चाहते हैं । हम जिस विधान सभा क्षेत्र आरा के सरजमीं से जीतकर आये हैं, हम जानना चाहते हैं अपने विपक्षी साथियों से, आपकी सरकार थी, आपके मंत्री थे, 9 साल आप मंत्रिमंडल में थे और लगभग 17 साल आपकी पार्टी के विधायक वहाँ के जन-प्रतिनिधि थे, आपने वहाँ कौन सी योजना सरजमीं पर उतारने का काम किया ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ । मैं सदन के माध्यम से अपने यहाँ की कुछ समस्याओं को रखना चाहता हूँ । सीवरेज की समस्या का जल्द से जल्द निदान किया जाय ताकि जल जमाव की समस्या दूर हो सके । आरा शहर में जल स्तर नीचे भाग रहा है जिसके कारण तमाम चापाकल सूख रहे हैं । अविलम्ब डायरेक्ट बोरिंग लगाने का काम किया जाय । आरा शहर में चार जल मीनार निर्मित है - पावरगंज, चन्दवा,

गौसगंज, बाजार समिति, सभी को जल्द से जल्द नगर निगम को सौंपा जाय । महोदय, 40 हजार रूपये लगते हैं चापाकल गाड़ने में । क्यों नहीं उसी राशि में सबमर्सिबुल बोरिंग गाड़कर तमाम लोगों को जलापूर्ति की व्यवस्था की जाय ! छठव्रतियों के लिए आरा का सबसे अच्छा छठ घाट होता है बघउतलख से लेकर बहिरोलख तक, जिसका सौन्दर्यीकरण कराया जाय । महोदय, आरा शहर में जाम की समस्या के बारे में कहना चाहते हैं, हमारे विपक्षी साथी जो कहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि आप सरकार में थे, हमारे आरा में 9 आउट फॉल नाले हैं, आज तक उनकी सफाई नहीं हुई है । अगर 9 आऊट फॉल नाले की सफाई हो गई होती तो निश्चित रूप से जल जमाव की समस्या पूरे बिहार में दूर हो सकती थी । आरा शहर में जेल के पास सरकारी जमीन है, वहॉ अगल-बगल गरीब लोग, मलिन लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं । अगर वहॉ उन बैक बेंचर लोगों के लिए सामुदायिक भवन बना दिया जाय तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम होगा । आरा टाउन हॉल के पीछे आरा नगर निगम की जमीन है जिसको इको पार्क की तर्ज पर चिल्ड्रेन पार्क यदि बना दिया जाय तो निश्चित रूप से सराहनीय कदम होगा । महोदय, आरा का मुख्य मार्केट जगजीवन मार्केट है जो आरा नगर निगम का है, उसे महानगर की तर्ज पर मार्केट बनाया जाय, पालिका मार्केट की तरह यदि बनाया जाय तो निश्चित रूप से वहॉ का सौन्दर्यीकरण होगा । आरा नगरपालिका स्वीकृत हुआ । माननीय मंत्री इनके थे, नगर निगम का दर्जा दिया गया, वहॉ कर्मचारी 605 थे लेकिन अभी कर्मचारी की संख्या कुल 252 है । आरा शहर में नगर निगम का दर्जा दिया गया लेकिन कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई । महोदय, नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत आरा शहर में.....

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

मो0 नवाज आलम : जो भी मार्केट है, उन तमाम मार्केट को, जैसे मछली मार्केट, तालाब मार्केट, संस्कृति भवन, यह नगर निगम के जिम्मे होना चाहिये लेकिन आज तक नहीं है । महोदय, आपने हमें समय दिया । सरकार का कदम सराहनीय है, इसका पुरजोर समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूॅ । जय हिन्द ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा, आपके लिए 25 मिनट का समय है ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : महोदय, मैं नगर विकास विभाग के बजट प्रस्ताव के पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विरूद्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूॅ । सभापति महोदय, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूॅ, सदन के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूॅ ।

महोदय, यह सर्वविदित है कि किसी भी राज्य का जिला, प्रखंड, नगर उसका चेहरा होता है । कोई भी व्यक्ति जब बाहर से आता है और उसको देखता है, उसकी सुंदरता को देखता है तो उसी से उसके व्यक्तित्व का आकलन करता है । महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शहर या नगर किसी भी राज्य के विकास का प्रतिबिम्ब होता है । शहर यदि साफ-सुथरा है, उसकी सड़कें अच्छी हैं, जल-जमाव का संकट न हो, जाम की स्थिति कम हो, आवासीय व्यवस्था अच्छी हो तो हम सब कह सकते हैं कि राज्य का विकास हुआ है । ...क्रमशः...

टर्न-12/आजाद/11.03.2016

श्री अभय कुमार सिन्हा : (क्रमशः) महोदय, इन सभी क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और नगर विकास मंत्री महोदय जी को हम धन्यवाद देते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में सरकार निष्ठापूर्वक काम कर रही है । महोदय, इन सारे कार्यों के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता होती है । बजट में और धन का प्रावधान करने की जरूरत है न कि कटौती प्रस्ताव लाने की जरूरत है । हम कहना चाहेंगे कि सभी घरों में पाईप जलापूर्त्ति की व्यवस्था सरकार के 7 निश्चयों में है । यह निश्चय कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है । सरकार की जो सोच रही है न्याय के साथ विकास का और जब यह 7 निश्चय चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, महागठबंधन की सरकार ने घोषणा की थी और उसका प्रतिफल है महोदय कि इन चार महीनों में ही 7 निश्चयों के प्रति जो कार्य करने का तरीका है सरकार का, वह बिहार की आवाम को स्पष्ट नजर आ रही है महोदय । हम कहना चाहेंगे कि सबके लिए शौचालय, हर घर में शौचालय की सुविधा सरकार ने 7 निश्चयों में रखा गया है । वैसी आबादी जो अधिकृत रूप से बांध आदि पर रह रहे हों, उनके लिए बहुमंजिले भवन निर्माण के लिए जमीन तलाशी जा रही है, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं ।

महोदय, कचड़ा प्रबंधन, जो कचड़ा शहरों मे बिखड़ा पड़ा रहता है, उसके लिए भी सरकार ने सार्थक कदम उठाने का काम किया है। शहरों की सफाई हेतु कचड़ों का उठाव एवं प्रबंधन किया जा रहा है । कचड़ों का प्रोसेसिंग करके उसका भंडारण करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि जहरीला पदार्थ वातावरण को नुकसान नहीं पहुँचा सके ।

महोदय, हम कहना चाहेंगे कि पार्क एवं हरियाली विस्तार योजना, पार्क की जब बात आती है तो वो बातें भी आपके माध्यम से स्मरण कराना चाहेंगे । बुद्धा स्मृति पार्क हो या इको पार्क हो, कंकड़बाग का पार्क हो या शास्त्रीनगर का पार्क हो,

नूरानी बाग का पार्क हो या गया के गाँधीमैदान में स्थित पार्क हो या बिहार के उन तमाम जिलों में अवस्थित पार्क हो । जब पार्क का निर्माण कराया जा रहा था, यही हमारे जो बगल में साथी बैठे हुए हैं, वे बहुत सारी बातें इसपर चर्चा करते थे, हम महोदय उसपर नहीं जाना चाहते हैं । जब पार्क का निर्माण हुआ, आज उन पार्कों में जब सुबह-शाम शहरवासी घुमने टहलने जाते हैं, स्वच्छ वातावरण में व्यायाम करने के लिए जाते हैं तो एक माहौल बनता है और वह माहौल बिहार की स्थिति को दर्शाता है। जब कोई भी पार्क एक जगह पर रहता है तो हरेक व्यक्ति को समय नहीं रहता है कि हम एक-दूसरे के यहां जाकर उनसे मिलें । लेकिन पार्क एक ऐसा साधन बना है कि लोगों को आपस में जोड़ने का भी काम करता है । आपसी भाईचारा को बढ़ाने का भी काम करता है । जब दिन भर लोग ऑफिस में या अन्य कार्यों में लगे रहते हैं और सुबह का उन्हें इन्तजार रहता है कि हम सुबह उठेंगे और पार्क में हम स्वच्छ वातावरण में व्यायाम करने के लिए जायेंगे, वहां पर लोगों से भेंट होती है, इसका इन्तजार लोगों को रहता है ।

महोदय, हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि शहरी परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, इसके लिए पटना में अन्तर्राष्ट्रीय बस स्टैंड का निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है । यह कोई मामूली कदम नहीं है, इस तरह तमाम जिलों में गया जिला हो, मुजफ्फरपुर हो, आरा हो या पटना हो, तमाम जिलों में बसस्टैंड का निर्माण कराया जा रहा है । हमारे गया जिला में भी बसस्टैंड का निर्माण हुआ है । वहां से तमाम जो क्षेत्र है, तमाम क्षेत्रों में बस का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है ।

महोदय, हम आपके माध्यम से आवास योजना के तहत आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिले मकान का निर्माण किया जा रहा है । मुख्यमंत्री आदर्श नगर विकास प्रोत्साहन योजना से शहरी स्थानीय निकायों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा पैदा करेगा । इसे भी सरकार लागू करने पर विचार कर रही है । मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उपर्युक्त कार्य बिहार सरकार अपने बूते पर कर रही है। हम कहना चाहेंगे, हमारे साथी अभी बहुत तरह की बातें बोल रहे थे । मैं समझता हूँ कि उनका ही नहीं उनके नेता का भी काम बोलना है और बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं । हम उनको स्मरण कराना चाहेंगे कि केन्द्र सरकार चुनाव के दरम्यान 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा पूरे भारत में किया था । परन्तु वादों का क्या वह तो जुमला बन जाता है । 100 में मात्र 20 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव हुआ और उसमें बिहार जहां से भाजपा गठबंधन के 32 सांसद, 7 मंत्री हैं, उसकी स्थिति पर विचार किया जाय तो उस ओर बैठे हमारे बंधु को लगना चाहिए कि ऐसा भेद-भाव क्यों ?

इसमें बिहार का क्या कसूर, जिसने 32 सांसद दिये लेकिन एक भी स्मार्ट सिटी बिहार को नहीं मिला ? मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, मैं एन0डी0ए0 के बंधुओं से खासकर के भाजपा के भाईयों से कहना चाहता हूँ कि बिहार को ठगने का काम बन्द कीजिए । वही हमारे मुख्यमंत्री महोदय एवं महागठबंधन की सरकार जिस तरह जनता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वे जो कहते हैं, उसको कर रहे हैं । उसी तरह आप अपना वादा निभाईए, नहीं तो जो बिहार की जनता ने 2015 में आपको आईना दिखाने का काम किया है । हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि आने वाला 2019 में उससे भी बड़ा आईना आपको दिखाने का काम करेगा । महोदय, मैं आपके माध्यम से नगर विकास मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो नगर विकास के लिए बजट बनाया है, वह काबिले तारीफ है । इससे राज्य के सभी नगरों का सर्वांगिण विकास होगा । चाहे जल-जमाव की समस्या हो, सड़क की समस्या हो या आवास की समस्या हो । आज भी मुझे स्मरण है कि बिहार के अन्य नगरों की स्थिति का क्या कहना, पटना जैसे राजधानी में दो-तीन माह तक जल-जमाव हो जाता था, चिड़ैयाटाड़ के पास घंटों जाम की स्थिति रहती थी । आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पहल से चिड़ैयाटाड़ पुल और एक्जीविशन रोड पर जो ओवरब्रीज का, फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया है । इस सरकार की जो सोच है, यह सरकार जिस सकारात्मक सोच के साथ काम कर रही है, उसपर सरकार अमल भी कर रही है । उस कार्य को सरकार सरजमीं पर उतारने का भी काम कर रही है । खाली बोलने का काम सरकार नहीं करती है, सरकार जो कहती है, उसको सरजमीं पर उतारने का काम कर रही है । हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज पटना जैसे शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को पास किया गया है, यह बिहार के लोगों के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है । पटना में भी बहुत जल्द मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला है । यह कोई मामूली बात नहीं है । केन्द्र सरकार जिस रूप में बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है, वह किसी बिहारवासी से छिपा हुआ नहीं है । हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि बहुत सारी बातें लोग बोलते रहते हैं, उतना ही नहीं जब चुनाव की बारी आती है तो नेता हेलीकोप्टर से उतरते हैं और गाली तक देकर चले जाते हैं और हमारे नेता उसको बर्दाश्त करते हैं । कहीं पर भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं । यह कोई मामूली बात नहीं है । इन्हीं सब कारणों के चलते बिहार के आवाम सब कुछ देख रही थी और देखते हुए 2015 के महागठबंधन के पक्ष में महाजीत और भारी मतों से जीत दिलाने का काम किया । इसके लिए हम बिहार के आवाम को, बिहार के सभी बंधुओं को मैं बहुत, बहुत धन्यवाद और उन्हें मैं नमन करना चाहता हूँ । महोदय, मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि आज महागठबंधन की सरकार

जिस मनोयोग से कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रही है, उसमें कहीं भी किन्हीं को चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि विकास की यह रफ्तार पर असर पड़ेगा, बल्कि उन्हें इसकी चिन्ता करनी चाहिए कि अच्छे काम करने वाले विभाग जो पूरे राज्य का दर्पण है, केन्द्र से कटौती की जाने वाली राशि के विरूद्ध आवाज उठाये, उनपर अधिकाधिक धन देने का दबाव बनाये, न कि निर्धारित बजट में ही कटौती का प्रस्ताव लायें ।

.... क्रमशः ....

टर्न-13/अंजनी/दि0 11.03.16

...क्रमशः...

श्री अभय कुमार सिन्हा : जिस तरह से माननीय नगर विकास मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, यह बिहार के हित का बजट है, इसलिए हम माननीय साथी से आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लें और जो केन्द्रांश तमाम विभागों में कटौती की जा रही है, उसके लिए, आपके लोग जो केन्द्र सरकार में बैठे हुए हैं, वहां जाकर आग्रह कीजिए कि बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार बंद कीजिए। नहीं तो, वर्ष 2015 में जो ह्रस आपलोगों का हुआ है, उससे ज्यादा बुरा ह्रस वर्ष 2019 के चुनाव में न हो जाय, इसलिए आप लोग जाकर केन्द्र सरकार से आग्रह कीजिए । हमारी साकारात्मक सोच से साकारात्मक भाव पैदा होता है और साकारात्मक भाव से अच्छे वातावरण का निर्माण होता है और सब को पता है कि अच्छे वातावरण में अच्छे-अच्छे गुणवत्तापूर्ण कार्य होते हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलता है। यही तो समावेशी विकास है, जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हो और सभी लोग समान रूप से लाभान्वित हों । सरकार इस दिशा में काम कर रही है और न्याय के साथ विकास कर रही है । बहुत सारे माननीय सदस्य बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं । हमलोग नये सदस्य के रूप में सदन में आये हैं और बहुत सी विषयों का अध्ययन करने का मौका मिलता है । आपके माध्यम से इस सदन में हमलोग बहुत कुछ सीखते रहते हैं और सीखना चाहते हैं लेकिन महोदय थोड़ी-थोड़ी सी बातों को लेकर और एक ही बात पर बार-बार सदन को डिस्टर्ब करना, यह सदन की मर्यादा पर, मैं समझता हूँ कि दाग लगती है । इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि इस सदन को डिस्टर्ब नहीं करते हुए बिहार सरकार जो बिहार के हित में काम कर रही है, आप उसमें साकारात्म्क साथ दें, तब बिहार का समग्र विकास होगा, इसलिए हम आपसे यह आग्रह करना चाहेंगे। सिर्फ अपनी बात कहने का प्रयास करेंगे तो समाज टूटेगा, विकास रूकेगा, वातावरण खराब होगा । महोदय, बहुत मुश्किल से, कठिन परिश्रम करके जो बिहार जिस स्थिति

में थी, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के विकास की गति पकड़ी है और यह गति रूकने वाली नहीं है महोदय । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि चाहे लोग जितना भी प्रयत्न कर लें, जो भी इल्जाम लगाना चाहें लगा लें लेकिन बिहार के विकास की गति अब रूकने वाली नहीं है महोदय, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ । महोदय, बहुत सारी बातें हैं, बहुत तरह की बातों का जिक्र होता है, जब जिक्र होता है सरकार की तो सरकार जो बोलती है, उसको करने में विश्वास रखती है और सरकार वही बोलती है, जो करती है महोदय । इसका प्रतिफल है महोदय कि सात निश्चय की घोषणा हुआ । महागठबंधन सरकार के नेतृत्व में, मात्र चार माह पूर्व और जब बिहार की जनता और आवाम ने देखा कि किस तरह से सात निश्चय को पूरा करने के लिए, सात निश्चय किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है । हर घर में पानी पहुंचाया जाय, हर गांव को गली, सड़क, नाली से जोड़ा जाय । हर दरवाजे पर स्वच्छ वातावरण पनपे तो यह कोई मामूली कार्य नहीं है महोदय । लोग बोलने वाले तो बोल देते हैं लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, माननीय नगर विकास मंत्री जी का, तथा साथ ही जो सात निश्चय से जुडे हुए तमाम् विभागों के मंत्री हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ । जिस निष्ठा से, जिस ईमानदारी से सात निश्चय को पूरा करने के लिए जो कार्य शैली बनाया गया है, वह निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है महोदय और आने-वाला समय, कुछ समय के बाद ही नहीं बल्कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सदन समाप्ति के बाद ही बिहार की धरती से सात निश्चय का कार्य लौटने लगेगा, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ महोदय । महोदय, हम कोई बड़ी बात नहीं कहना चाहते हैं, हम वही बात आपके माध्यम से रखना चाह रहे हैं जो धरातल पर काम उतर रहा है महोदय । हम कोई भाषणवाजी नहीं कर रहे हैं, हम आपसे आग्रह करना चाह रहे हैं । हम टेकारी विधान सभा क्षेत्र से आते हैं, टेकारी विधान सभा, मैं सही रूप में आ रहा हूँ और आपके विरोधी दल के माननीय जो नेता है, हमारे ही जिला से आते हैं, मैं उनको बखूबी जानता हूँ । जिस रूप में विकास धरातल पर हुआ है, आपके पास पी0एच0ई0डी0 विभाग था, पी0डब्लू0डी0 था, उस समय क्या कार्य किया गया, उस चीज को भी मैं भलीभांति जानता हूँ, लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूँ । मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि टेकारी विधान सभा, टेकारी भी एक ऐतिहासिक जगह है । जैसे गया जिला ऐतिहासिक जगह है, उसी तरह से टेकारी भी एक ऐतिहासिक जगह है । टेकारी महाराज का एक किला वहां है, उस किले के प्रांगण में एक बड़ा तालाब है । किला एवं तालाब का विकास कराया जाय एवं उसका सौन्दर्यीकारण किया जाय तो यह क्षेत्र विदेशी सेलानियों को आकृष्ट करेगा महोदय । टेकारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण

कार्य चल रहा है, पंचानपुर के पास केन्द्रीय विश्वविद्याल का निर्माण हो रहा है, इसलिए आपके माधयम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि उस किला का सौन्दर्यीकरण वृहत तरीके से किया जाय ताकि देशी-विदेशी पर्यटक जो बोध गया में विदेशी सेलानी, देशी सेलानी आते हैं, उस ओर भी कदम बढ़ायें, ताकि इस क्षेत्र के युवाओं एवं अन्य लोगों को रोजगार को अवसर मिल सके । इससे संस्कृतियों का आदान-प्रदान होगा एवं यह क्षेत्र आर्थिक रूप से भी स्मृद्ध होगा महोदय । परन्तु स्थिति आज की यह है कि टेकारी महाराज के किला की भूमि लोग अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रहे हैं, उसपर तुरंत रोक लगाने हेतु कार्रवाई की जाय, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हूँ । टेकारी में एक चिल्ड्रेन पार्क है, उसका विकास कराया जाय ताकि वहां पर स्वस्थ वातावरण में लोगों को अपनी राय आदान-प्रदान करने का मौका मिले । महोदय, गया शहर दो-तीन माइने में बहुत ही महत्वपूर्ण हे । पितृपक्ष का जब समय आता है तो गया शहर में तकरीबन 15 दिनों में 10 से 15 लाख लोगों का वहां पर आवागमन होता है । हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि 15 दिन में पितृपक्ष में 10 से 15 लाख लोग आते हैं, उनके आने से और वे यहां से ऐतिहासिक भाव लेकर जाते है । उनके आवासन की व्यवस्था वैक्लिपक की जाती है । वैक्लिपक व्यवस्था करने से हम समझते हैं कि राज्य सरकार को राशि भी बहुत ज्यादा खर्च होती है, इसलिए उसके आवासन के लिए स्थायी रूप से व्यवस्था वहां पर अगर की जाती है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा और यहां से अच्छा विचार, अच्छा सोच लेकर, जिला के प्रति ही नहीं, बल्कि बिहार के प्रति लेकर जायेंगे महोदय । महोदय, बातें और भी हैं । गया शहर के केदारनाथ मार्केट बीच शहर में बहुत ही अच्छा कम्पलेक्स है महोदय । इसके पहले भी वहां पर मार्केट कम्पलेक्स बनाने के लिए डी0पी0आर0 सरकार के पास आयी थी लेकिन उस डी0पी0आर0 में कुछ त्रुटियां थीं, हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि उस केदारनाथ मार्केट में दो फ्लोर अन्डरग्राउंड पार्किंग के साथ अगर मार्केट कम्पलेक्स बनाया जाय तो निश्चित तौर पर आनेवाले समय में जो थीड़ी बहुत जाम लगती है, उससे भी हम निजात पाने का काम करेंगे और यह जनहित में बहुत ही उपयोगी रहेगा महोदय । महोदय, हम कहना चाहेंगे, जाम की बात चल रही थी कि अनेक शहर में जाम रहता है । जाम सिर्फ व्यवस्था से ही नहीं लगती है, हम भी रोड पर चलते हैं तो हम देखते है कि जाम हमारी गलती से भी लगती है,

....क्रमश:......

टर्न–14/शंभु/11.03.16

श्री अभय कुमार सिन्हा : क्रमशः......हम अपनी गलती को अगर सुधार लें और जो विभाग का नियम कानून है कि हमें किस तरह से रोड पर चलना चाहिए, अगर हम पैदल चल रहे हैं तो किस रूप में चलना चाहिए, गाड़ी से चल रहे हैं, 4 व्हीलर से चल रहे हैं तो किस रूप में चलना चाहिए, 2 व्हीलर से चल रहे हैं तो किस रूप में चलना चाहिए। अगर हम अपनी स्थिति को सुधारते हुए रोड पर चलें तो हमारा यह मानना है कि पटना शहर ही नहीं, बल्कि बिहार के भिन्न भिन्न शहरों में जो जाम की स्थिति लगती है वह पैदा नहीं हो। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि इसका बृहत् पैमाने पर प्रचार प्रसार हो कि किस रूप में हमें चलना चाहिए। अगर हम 2 व्हीलर से चल रहे हैं तो कहां पर हमें गाड़ी ब्रेक करनी चाहिए, कहां पर हमें पार्किंग करनी चाहिए। इसकी समुचित व्यवस्था, इसका समुचित प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, तब जाकर हम समझते हैं कि जाम की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार आयेगा। महोदय, हम निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं कि जाम की स्थिति जब पैदा होती है तो हम जैसे लोग भी उसमें थोड़ा गुनहगार होते हैं। हम हों या जिला में कोई भी कद्दावर व्यक्ति रहते हैं, वह अपना प्रभाव लगाते हैं और अगर नो इंट्री रहती है तो वहां भी गाड़ी घुसा देते हैं। अगर इन चीजों परिवर्तन लाया जाय तो जाम की स्थिति में भी निश्तिच तौर पर सुधार आयेगा। हमारे गया जिले में जहां पर पिण्डदान होता है, जहां पर विष्णुपद में पिण्डदान होता है और जहां पर तीर्थयात्री आते हैं। वहां पर इलेक्ट्रीक से शवदाह गृह का निर्माण हो चुका है। हम आपके तरफ से सरकार का घ्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि उस इलेक्ट्रीक शवदाह गृह का जो निर्माण कराया गया है उसको जल्द से जल्द चालू कराया जाय ताकि वातावरण प्रदूषित नहीं हो। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ-साथ बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयहिन्द, जय बिहार। धन्यवाद महोदय।

श्री सिद्धार्थ : माननीय सभापति महोदय, सभा में उपस्थित सभी लोग और खासकर बिक्रम की जनता जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिहार में नगर विकास विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के सात निश्चयों में एक है और आशा करता हूँ कि आगे आनेवाले पांच सालों में निश्चित रूप से यह विभाग अपना सारा लक्ष्य पूरा कर पायेगा। बिक्रम और नौबतपुर दो ऐसे प्रखंड है जो बिहार में नगर पंचायत के अन्तर्गत आते हैं- आगे आनेवाले समय में माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वहां पर कुछ नयी योजनाओं को भी दिया जाय। बिक्रम एक ऐतिहासिक स्थल रहा है। वहां से स्वतंत्रता

अभियान शुरू किया गया। वहां पर एक गांधी आश्रम है, मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि उस गांधी आश्रम को पक्का किया जाय और एक पौराणिक स्थल बनाया जाय। साथ ही साथ मैं आशा करूँगा कि नगर पंचायत के माध्यम से जो भी वहां पर सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है, उसमें थोड़ी कमी है, उसको भी तेज किया और जो पिछले 5 साल में वहां विकास अवरूद्ध रहा है उसको योगदान देते हुए और कुछ ज्यादा नयी योजनाओं के साथ उस क्षेत्र का विकास किया जाय।

श्री समीर कुमार महासेठ : सभापति महोदय, मैं आज वित्तीय वर्ष 2016-17 पर नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट पर बोलने के लिए महागठबंधन की सरकार के पक्ष में खड़ा हूं साथ ही विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हूँ। महोदय, आज हमारे बीच हमारे अपोजिशन के लोग जो कटौती प्रस्ताव लाये हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि एक तरफ जहां मैक्सिमम डिपार्टमेंट शुरू से आपके पास रहा उसमें आज कौन सी परिस्थिति आयी है कि आप कटौती प्रस्ताव लाये हैं। एक तरफ कहते हैं कि नगर परिषद्, नगर पंचायत और नगर निगम की स्थिति ये है, मैं जानना चाहता हूँ और आपसे अपेक्षा भी करता हूँ कि आनेवाला भविष्य आपको बतलायेगा कि कहीं न कहीं आप साधक के रूप में रहे हैं या बाधक के रूप में रहे हैं, यह आप स्पष्ट करेंगे। जनता मानती है चूंकि माननीय मुख्यमंत्री, हमारे नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से जब पंचायती राज की परिकल्पना में और उन्होंने ग्रामीण स्तर को लेकर अरबन एरिया में भी जिस ढंग से परिवर्तन लाया, 50 प्रतिशत आरक्षण दिया उस आरक्षण के बल पर पूरे देश में बिहार का नाम हुआ और यहां पर जब लोग वोट गिराने जाते थे तो 40 प्रतिशत से ज्यादा आबादी वोट नहीं देते थे, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि कहीं पर 60 प्रतिशत, कहीं 70 प्रतिशत क्यों वोट गिराने जाते है। इसके पीछे जो परिवर्तन है उसमें इस सोच के प्रति आपको जाना होगा और उस सोच के प्रति आपको लगेगा कि जहां पर पंचायती राज व्यवस्था, नगर विकास पर जो हम कहने जा रहे हैं। पहले के बजट में ज्यादा बजट दिया गया है। पहले का जो बजट था 2016-17 के लिए 3 हजार 409 करोड़ 36 लाख रूपये आवंटित कर राज्य के सभी शहरों में विकास के लिए गठबंधन की सरकार ने सराहनीय कदम उठाने का काम किया। महोदय, 2016-17 की योजना के मद में 2 हजार 1 करोड़ 9 लाख रूपये तथा गैर योजना के मद में 1 लाख 408 करोड़ रूपये 27 लाख रूपये उपलब्ध कराने का जो काम किया। यह जो महागठबंधन की सरकार ने की है वह काबिले तारीफ है। आप, हम क्यों शहर में रहना चाहते हैं, क्या कारण है, क्या अपेक्षा है ? सरकार यह सोच रही है और आनेवाला जो सात निश्चय है उसमें स्पष्ट है। एक तरफ जहां पर हम सोच सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सात

निश्चय है, बजट पर जब हमलोग पूर्णत: मजबूती के साथ लायेंगे तो हमको लगता है कि एक ओर भारतीय जनता पार्टी यह सोच रही है कि उनके जो वोटर हैं सबसे ज्यादा वह शहर में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सात निश्चय जमीन पर उतरने के बाद वहां भी पैर लड़खड़ाने की बात हो जाय। ऐसा हमको लगता है और इसीलिए विपक्षी दल घबड़ा रहे हैं और कटौती प्रस्ताव में हम बहुत सार्थक रूप से सहभागिता देख रहे हैं। महोदय, हर घर में नल की आवश्यकता है वह बहुत ही आवश्यक है। दूसरे तरफ हरेक जो गली, नाली, नाला और नाला के साथ ढक्कन का निर्माण भी बहुत आवश्यक है। हरेक घर में शौचालय की जो परिकल्पना है निश्चित तौर पर बहुत आवश्यक है। प्रत्येक घर विहीन के लिए 2 लाख से 4 लाख का अनुदान देने जा रही है सरकार वह भी आनेवाला समय बतायेगा कि इनकी उपयोगिता किनको है और कैसे सही व्यक्ति को मिल रहा है। पूर्णत: जो सफाई का लक्ष्य रखा गया है हमको लगता है कि बजट के बाद जो बजट का प्रावधान किया गया है उसमें निश्चित तौर पर सरकार सक्षम रहेगी। पार्क के निर्माण से लेकर के घाट का निर्माण और एक तरफ पहले जो कुछ हुआ हो, लेकिन इस बार जो हमलोग जीतकर आये और छठ के कार्यक्रम में जो नगर विकास विभाग ने महत्वूपर्ण भूमिका निभायी, हरेक जगह बिजली से लेकर के सभी चीजों में उनका योगदान हुआ उसी दिन लगा कि मंदिर के साथ साथ हमलोग छठ में सभी जगह घाट का निर्माण से लेकर के हो............क्रमशः।

टर्न-15/अशोक/11.03.2016

श्री समीर कुमार महासेठ : क्रमश: जो उनका योगदान हुआ, उसी दिन लगा कि मंदिर के साथ साथ हमलोग छठ में सभी जगह घाट का निर्माण से लेकर के हो, हम आग्रह करना चाहेंगे नगर विकास विभाग के मंत्री जी से कि पूर्णत: छठ की योजना को उस रूप में मनावे जिस ढंग से लोग अपेक्षा करते हैं । पूरे बिहार का वह छठ पूरे दुनिया में जाना जाता है और आज महाराष्ट्र जैसे जगह पर जहां पर बोलने वाला कुछ और बोल रहा है, हम लोग बिहार में उनके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं । महोदय, मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय जहां पर बिहार सरकार हमेशा चाहती है कि हम बिहार को उस रूप में शहर को उस रूप में बनावें जहां पर जो अपेक्षाकृत जो शहर की जो आबादी है दिनानुदिन बढ़ती जा रही है अपेक्षा है जिस ढंग गांव का विकास हो रहा है उससे चार गुणा नगर का विकास हो। हम अपने मधुबनी की तरफ आपको ले जाना चाहेंगे चूंकि हमे अपेक्षा है कि ग्रेटर मधुबनी बने, चूंकि ग्रेटर मधुबनी बनने के साथ-साथ वहां बाईपास का निर्माण होगा, अलग अलग तरह की चीजों का डेवलपमेंट होगा चूंकि एक तरफ किंग केनाल से लेकर वाट्सन केनाल तक जो अंग्रेज का जमाना था उन लोगों की परिकल्पना थी और चारों तरफ एक बूंद पानी नहीं लगता था। सभापति महोदय, आज के दिन में हम अपेक्षा करते हैं, बार बार जो भारत सरकार नियम कानून बदलती है, नीति आयोग को बदल कर क्या किया यह देंख रहे हैं, जहां पर 2011 के सेंसस के आधार पर भारत सरकार पैसा देना चाहती -ऐसा क्यों करती है । एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री से हमने आग्रह किया, सचिव महोदय ने भारत सरकार को लिखा और भारत सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बिहार में ऐसे 14 जिले हैं जिनका काम रूका हुआ है। काम रूकने का मुख्य वजह है कि लोग अपेक्षा कर रहे हैं भारत सरकार से कि हम एक लाख आबादी वाले शहर को ही पूर्णत: ज्यादा मदद करेंगे और बिहार सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हरएक जगह पर 40 प्रतिशत से, अब हो सकता है 50 प्रतिशत हमलोगों को मार्जिन मनी लगाना पड़ेगा । आदरणीय सुशील मोदी जी भी थे और श्री प्रेम कुमार जी भी थे, और नहीं कहना चाहिए, उस समय जो परिवर्त्तन किया गया, उस परिवर्त्तन में मुख्य रूप से जो आया वह जानने योग्य बात है, नगर विकास विभाग के द्वारा जो पूरे प्रदेश में नक्शा परित कराने में जो रोक लगाई गई 2012 के पूर्व में , इन्हीं लोगों के सरकार में, ये मंत्री के रूप में थे और आज तक मास्टर प्लान के

अभाव में यह प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है फलस्वरूप तीन वर्षो से नक्शा पारित करने की प्रक्रिया रूकी हुई है । जब कि पड़ोसी राज्य झारखंड में छः माह के अन्दर मास्टर प्लान पारित किया गया और जब लागू नहीं किया गया तबतक पुराने मास्टर प्लान के आधार पर प्रक्रिया चलती रह गई । उसको रोका नहीं गया । पिछला चल रहा था, आपने लाया और उसके बाद उसको माना गया । नये भवन उपविधि 2014 में भी नगर निकायों के बाहर के भूखण्डों पर होने वाले निर्माण के विषय में कोई व्यवस्था नहीं बताई गई है जबकि सरकार चाहती है ज्यादा चौड़ी सड़कों पर और बड़े भूखण्ड पर निर्माण को बढ़ावा दिया जाय, यह तभी संभव है जब नगर निकाय क्षेत्र के बाहर के भूखण्ड पर नक्शा पारित कराने की समुचित व्यवस्था हो ।

नगर निगम द्वारा नक्शा पारित करने की शिथिल प्रक्रिया को देखते हुए जन अदालत लगा कर पारित करने का प्रबंध किया जाय ।

अगर सरकार चाहती है, जयादा से ज्यादा विकास हो, निवेश हो, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि बुनियादी क्षेत्र में विकास हो तब यह जरूरी हो जाता है कि नक्शा पारित करने की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो, और समय सीमा के अन्तर्गत किया जाय । आज इस शिथिलता की वजह से कई बड़े निर्माण जो शुरू भी हुए थे आज तीन वर्ष से बन्द हैं । इस कारण बेरोजगारी और मजदूरों का पलायन भी बढ़ा है ।

भवन उपविधि किसी भी मास्टर प्लान पर ही आधारित होती है । मास्टर प्लान के अभाव में नये क्षेत्र और पुराने क्षेत्रों का सीमांकन नहीं हो पया है जिस वजह से नक्शा पारित करना मुश्किल हो रहा है । इसलिए मास्टर प्लान का आना भवन उपविधि के पहले जरूरी होता है जो नहीं किया गया है ।

सभापति महोदय, इसलिये मेरा आग्रह होगा जहां तक भारत सरकार से, हम आज की परिस्थिति में पूरे बिहार को जहां हम ले जाना चाहते हैं, जो हमारी सोच है वह कहीं न कहीं, बिहार कम से कम भारत में 1 से 10 के बीच में आये, इसलिए आवश्यकता है, एक तरफ भारत सरकार को आप देंख लें, जो कहीं न कहीं स्मार्ट सिटी की परिकल्पना थी, हम कहां छूट गये? क्यों छूटे ? इसका मूल्यांकन उनको करना पड़ेगा । हमारे में कोई कमी नहीं है । हम से छोटा-छोटा ऐसा राज्य जहां कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना हो रही है लेकिन हमको छोड़ा जा रहा है । हमको क्यों छोड़ा जा रहा है । इसमें कहीं एक साथी ने कहा, जहां 40 लोग, लोक सभा में 40 लोग जीत

कर गये, उनका भी दायित्व बनता था कि वे भारत सरकार में अपने-अपने क्षेत्र के लिए पूर्णतः मदद लाने की परिपाटी लाते और मधुबनी में 2011 के सेंसस के अनुसार 68 हजार की आबादी है, तब अब बतावें कि कहां से हम एक लाख ले आवें ? जब तक वृहद परिकल्पना नहीं किया जायेगा, सिटी प्लान उस ढंग से नहीं बनेगा और यदि आप पटना की बात लेंगे, क्या यहां डवेलपमेंट नहीं हो रहा है ? म्यूजियम देख लीजिए, विश्व स्तर का म्यूजियम बन रहा है, जो बस स्टैण्ड की परिकल्पना है लेकिन एक तरफ आप याद करें, उस दिन जिस दिन पानी आया कंकड़बाग में, उस समय के मंत्री जी क्या बोलते थे, क्या बिहार को पेरिस बनाना चाहेंगे, क्या बिहार को सिंगापुर बनाना चाहेंगे, आज हम उनसे पूछना चाहते हैं पेरिस और सिंगापुर तो नहीं बना, आपके गलत कृत्यों की वजह से पूरा बिहार हमारा पिछड़ गया, उस पिछड़ते हुये को हम कहीं न कहीं चाहेंगे, आज हमारे जो युवा मंत्री हैं, आज पूरे तरह तन, मन, धन लगा करके पूरी तरह लगे हुये हैं कि हम बिहार को उस रूप में ले जायं, आगे बढ़ाने का काम करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ ।

सभापति(श्री हरि नारायण सिंह): माननीय सदस्य श्री तारकेश्वर प्रसाद । आपके लिए समय 12 मिनट ।

श्री तारकेश्वर प्रसाद : सभापति महोदय, नगर विकास के बजट में कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, किसी भी राज्य के विकास में उसका कितना बड़ा भूभाग क्षेत्र में शहरीकरण हुआ है उससे इसके विकास की गति का अंदाज होता है। इसके पूर्व में भारत के राष्ट्रपति डा0 कलाम ने कहा था कि जो हमारे गांव हैं, उस पर पूरा भारवर्ष आधारित है, वहां अगर शहरी सुविधायें दें तो गांव के पलायन को हम रोक भी सकते हैं और शहर का विकास भी कर सकते हैं । लेकिन परिस्थिति इस ओर जा रही है कि गांव से लोगों का पलायन हुआ है और उसके कारण शहर की भी अपनी कठिनाई बढ़ी है । सभापति महोदय, मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के द्वारा माननीय विधायकों को एक महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया था, जब हम एन.डी.ए. सरकार में थे, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक भी हुई थी, उसमें हम-आप शामिल थे और काफी जद्दोजहद के बाद यह योजना बनी और विधायकों को पहली बार यह अधिकार मिला कि नगर के विकास में अपनी अनुशंसा को बेहतर ढंग से कर सके और सड़क, नाला के अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का जो

क्षेत्र है उसके में सड़क नाला और सौन्दर्यीकरण के लिए अलग-अलग राशि भी कर्णांकित की गई और उसका आवंटन भी सुनिश्चित किया गया लेकिन शराब तो वही है सिर्फ लेबल बदला है । सरकार जो पूर्व में चल रही थी, एन.डी.ए. के बाद जो सारी परिस्थितियां बनी, वही सरकार आज भी है, कुछ जुड़े हें और कुछ हटे हैं और सात निश्चय जो पूरे बिहार को अनिश्चि की स्थिति में में लाया है सभापति महोदय । सात निश्चिय की बात सरकार कर रही है, सभापति महोदय, ये सात निश्चिय में, आप पूरे बजट भाषण को देंख लें, अभी माननीय नगर विकास विभाग के मंत्री के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन को देंख लें कहीं भी विधायकों की सहभागिता सुनिश्चित नहीं की गई है । क्रमशः

टर्न-16-11-03-2016-ज्योति

क्रमशः

श्री तारकिशोर प्रसाद : 7 निश्चयों में अभी हम माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को देख रहा था कि उसमें 3 श्चिय नगर विकास से जुड़े हुए हैं । इन्होंने कहा है लेकिन सभापति महोदय, बिहार विधान मंडल सारभौम है । पूरे बिहार राज्य को बिहार विधान मंडल प्रतिदिन प्रतिबिम्बित करता है । हम लोकतांत्रिक पद्धति में हम जीते हैं । माननीय विधायकों की क्या स्थिति है हम कोई कार्यपालिका के अंग नहीं है । लेकिन हमारी विकास में क्या भूमिका है यह कहीं भी सुनिश्चित नहीं है । हम बजट पारित करते हैं और विस्तार से चर्चा भी करते हैं लेकिन जो सरकार की विभिन्न योजनाएं 7 निश्चय के रुप में ये पूरे बजट सत्र में अलग अलग विभागों के माध्यम से देखने को मिल रहा है उसमें विधायकों की भूमिका को कहीं भी सुनिश्चित नहीं किया है । यह एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है और पूरे सदन के लिए एक शर्म की बात है । इसपर माननीय मुख्यमंत्री जी को , माननीय तमाम जो साथ मे इससे ं जुड़े हुए जितने विभाग हैं उनके माननीय मंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिए और विधायकों की भूमिका को स्पष्ट करनी चाहिए । यह मेरा आग्रह है । अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने , सत्ताधारी दल के वक्ताओं ने भी काफी प्रशंसा की है, नगर विकास विभाग की प्रशंसा में कई कसीदे काटे हैं लेकिन सभापति महोदय, शायद इनको नहीं पता है कि केन्द्र सरकार की 9 योजनाएं सिर्फ नगर विकास विभाग से जुड़ी हुई हैं । स्वच्छ भारत मीशन जिसमें शौचालय बनाना है , अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मीशन जिसमें जलापूर्ति , पार्क , फुटपाथ के निर्माण का प्रावधान है । आई0एच0एस0डी0पी0 जो पहले से चल

रही है उसमें गंदी बस्ती को विकसित करने की बहुत महत्वकांक्षी योजना है । फिर आपका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मीशन जो एक महत्वपूर्ण योजना है कि कैसे शहरी क्षेत्र के नौजवानों को आप प्रशिक्षित करें , कैसे वो वेन्डिंग जिसकी चर्चा शून्य काल के समय हम सबों ने इस सवाल को गंभीरता से उठाया भी था फिर कैसे उसको वेन्डर जोन बनाकर जो शहर में बहुत बड़ा भू-भाग है और बहुत बड़े क्षेत्र में वे अपना रोजगार करते हैं । जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं वह अपना घर और अपनी जीविका चलाते हैं । उनके लिए स्पष्ट रुप से प्रावधान है लेकिन सरकार जो केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं उसको सही रुप से जमीन पर लागू करने के प्रति वह कृतसंकल्प भी नहीं है और वह दिखता भी नहीं है । सभापति महोदय, शहर के जो हमारे वेन्डर है वह शहर के फीडर हैं । दूध वाला , सब्जी वाला, कबाड़ी वाला और ठेला वाला इसतरह का जो एक ठेला से सामान पहुंचाने वाला ये एक ऐसा वृत है , यह वृत एक दिन के लिए भी हड़ताल कर दे तो आपका पूरा जन जीवन ठप्प हो जायेगा । आपके घर की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वह कहीं न कहीं रुक जायेंगी , बंद हो जायेंगी । इसलिए वेन्डर जोन को माननीय मंत्री जी गंभीरता से लें और उसको करेंगे जिससे शहर में जो अनावश्यक जहॉं तहॉं जो लोग ठेला लगाते हैं उससे भी बचाव होगा, शहर अच्छा भी दिखेगा और जो जाम की स्थिति है उसमें यह कहीं न कहीं एक भूंमिका के रुप में है । उससे भी बचा जायेगा ।

सभापति महोदय, हम कटिहार के मुख्यालय के विधायक हैं । कटिहार नगर निगम को बनाने में हम सबों की भूमिका रही है । सभापति महोदय, 2010 में कटिहार शहरी जलापूर्ति पुनर्गठन योजना का शुभारम्भ हुआ । माननीय मंत्री जी यह एक बहुत अच्छी सलाह के रुप में है । हमारी यह पीड़ा है । कटिहार के लोगों की पीड़ा है । उसको निश्चित रुप से आप ध्यान से सुनेंगे । 8 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से दो जल मिनार तैयार किया गया । शहर को दो भाग में वर्गीकृत किया गया । अलग अलग जो लौह युक्त जल सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र में था वहॉं पाईप लाईन बिछाकर उसको जोड़ने का भी काम किया गया । लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है ? यह नगर विकास विभाग की राशि से बना , पी0एच0ई0डी0 आपकी कार्य एजेन्सी थी कार्य एजेन्सी ने कार्य को पूरा करके फिर कटिहार नगर निगम को हस्तांतरित भी किया लेकिन आजतक उसे चालू नहीं किया गया । वह एक सफेद हाथी साबित हो रहा है । इसको आप गम्भीरता से नहीं लेंगे तो माननीय मंत्री जी यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। अभी जो लम्बी लम्बी , बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि हम नल के द्वारा लोगों तक पेय जल पहुंचायेंगे । जब पूर्व से बना हुआ है, हाल के कुछ महीने पहले तक वह बन कर तैयार हुआ और वह हस्तांतरित हुआ लेकिन उसपर सरकार की कोई पहल

नहीं है । हमने कई बार प्रयास किया । पी0एच0ई0डी0 और नगर विकास एवं आवास विभाग के कितने सचिव बदल गए , कितने लोगों से हमने आग्रह किया लेकिन किसी ने इसपर ध्यान नहीं दिया और यह योजना आजतक लागू नहीं हो सकी । आप इसे गम्भीरता से लेंगे । यह मेरा आपसे आग्रह है । उसीतरह पटना जलापूर्ति योजना 2012-13 में 522 करोड़ की योजना 2014 के सितम्बर महीने से बंद है । उसको देखने का प्रयास करेंगे, यह हमारे सहयोगी नीतीन नवीन जी के क्षेत्र का मामला है इसे आप गंभीरता से लेंगे । एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न , महत्वपूर्ण समस्या नगर विकास से जुड़ी हुई है सभापति जी के माध्यम से हम मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहेंगे और पूरे सदन का भी ध्यान दिलाना चाहेंगे क्योंकि कई क्षेत्र में जहॉ नगर पंचायत है उसको नगर परिषद बनाया जा रहा है और जहॉ नगर परिषद है उसको नगर निगम बनाया जा रहा है और जहॉ पंचायत है उसको नगर पंचायत भी बनाया जा रहा है लेकिन स्थिति क्या हो रही है । आज हमारे कटिहार जिला के बारसोई में नगर पंचायत की घोषणा की गयी वहॉ पंचायती राज का चुनाव बंद कर दिया गया । वहॉ के विकास से जुड़ी हुई सारी योजनायें जो ग्रामीण सेक्टर से आती थी वह सारी बंद हो गयी और कटिहार को भी 2011-12 में कटिहार नगर निगम में उत्क्रमित कर दिया गया, उसमें हमारी भी भूमिका है लेकिन सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि मेरे कटिहार में चार वार्ड कई पंचायतों को जोड़कर बनाया गया और 1800 हेक्टेयर कृषि भूमि उससे जुड़ गयी और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि जो हमारे गरीब किसान हैं जो शहर के वृत में उनकी जमीन है , वे खेती कर रहे थे , छोटे छोटे लघु और सीमान्त कृषक हैं उन्हें अब होल्डिंग टैक्स देना पड़ रहा है । वे गेहूँ उपजा रहे हैं और होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं । उसमें धान उपजा रहे हैं और होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं । उसे गोभी उपजा रहे हैं और होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं । ये परिस्थिति बनी है और यही परिस्थिति हमारे मित्र विजय खेमका जी बैठे हुए हैं , पूर्णिया नगर परिषद को भी पूर्णिया नगर निगम में उत्क्रमित किया गया और वहॉ के कई पंचायत, पाच पंचायत मुझे ध्यान है , वहॉ के कई लोग डेलीगेशन में आए थे , हमसे मिले भी थे । पांचों पंचायत पूरा का पूरा वो नगर निगम में डाल दिया गया। आज स्थिति क्या है ? वहॉ विकास नहीं हो पा रहा है । उसमें माननीय मंत्री जी मेरा आग्रह है कि ये जो सारे टुकड़े जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं नगर निगम में वहॉ आप अलग से राशि आवंटित करें । इससे जो शहर की बुनियादी सुविधाएं हैं उनको वहॉ हम तुरत दे सकें यह एक आग्रह आपसे रहेगा । दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं उनको हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि पी0एच0ई0डी0 के द्वारा मुक्ति धाम का निर्माण 50 लाख की लागत से , पूरे बिहार में कटिहार में पहली बार किया गया । और उसके

निर्माण होने के बाद उसके रख रखाव के लिए कटिहार नगर निगम को हस्तांतरित किया गया लेकिन आज क्या परिस्थिति बनी । आज उसके सारे सामान चोरी चले गए। नगर निगम को कोई उसमें इन्टरेस्ट नहीं है । आज भी वह काफी खराब हालत में चली गयी । अगर आप पी0एच0ई0डी0 से हैण्ड ओवर ले रहे हैं तो उसपर ध्यान रखना चाहिए कि उसका मेंटीनेंस कर पायेंगे कि नहीं ? नहीं तो आपको हैण्ड ओवर लेना ही नहीं चाहिए था । इसके लिए अलग से सरकार की कोई नीति बने ं। पी0एच0ई0डी0 अगर कोई निर्माण कार्य अच्छे उद्देश्य के लिए करता है तो नगर निगम उसके मेंटीनेंस के लिए तैयार नहीं है । नगर निगम कोई अच्छा काम करता है या नगर विकास कोई अच्छा काम करता है तो पी0एच0ई0डी0 उसके मेंटीनेंस करने के लिए तैयार नहीं है ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह) **:** अब आप समाप्त करें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद **:** पूर्णिया में विद्युत शव दाह गृह आजतक नहीं चालू हो पायौ । फारबिसगंज की भी माननीय मंत्री जी वही सारी स्थिति बनी हुई है । मेरा इतना ही आपसे निवेदन है कि एक तो शहरी क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र के कृषि भूमि शामिल हुई है उसपर होल्डिंग टैक्स नहीं लिया जाय । सरकार की स्पष्ट उसमें एक नीति बने क्योंकि पूरे बिहार के लोगों के लिए वह कष्टदायक सिद्ध हो रहा है । नंबर वन और नंबर टू - अभी जो आपकी जलापूर्ति की योजनाएं हैं उस जलापूर्ति की योजना से कैसे जलापूर्ति होगी जबकि उसके लिए जल बोर्ड भी है इसलिए उसके लिए एक स्पष्ट नीति बनाईये । इन्हीं श।ब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

टर्न–17/विजय/11.03.2016

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह): कुमार सर्वजीत जी, आपके लिए दस मिनट ।

श्री कुमार सर्वजीत: माननीय सभापति महोदय, 16 वे विधान सभा के बजट सत्र के दरम्यान नगर विकास एवं नगर एवं आवास विभाग के वित्तीय वर्ष 2015-16 के द्वितीय अनुपूरक व्यय अनुदान में सम्मिलित अनुदानों पर वाद विवाद में आपने वाद विवाद में बात कहने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं ।

सभापति महोदय, हमारा जो सरकार का 7 निश्चय है वह निश्चय सभी घरों में पाइप लाइन से जलापूर्त्ति सुविधा उपलब्ध कराने और हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां इस विभाग को दी गयी है। हमें उम्मीद है कि यह जो जिम्मेवारियां इस विभाग को मिली है निश्चित तौर पर सरकार लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रही है और बढ़ेगी यह हमको उम्मीद है ।

महोदय, भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी का जो निर्णय लिया था उसमें बिहार सरकार ने यहां से तीन शहरों का नाम चिन्हित कर भेजा था । जैसा माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया कि आपने नली और गली का एस्टीमेट भेज दिया इसलिए स्मार्ट सिटी नहीं मिला । मैं जानना चाहता हूं कि इनकी मंशा क्या थी बिहार सरकार बड़े बड़े मॉल बनाकर अगर एस्टीमेट भेज देती तो शायद बिहार को कई जिलों का दर्जा स्मार्ट सिटी को हो जाता ।

सभापति महोदय, पूरा देश जानता है बिहार का इतिहास । हमारे यहां बिहार के कई ऐसे शहर हैं जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक महत्व का प्रतीक है । जैसे हमारा नालंदा, वैशाली, पटना, गया । दुनिया में सभी लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय जहां विश्व के कोने कोने से छात्रगण अध्ययन करने के लिए आते थे । फल्गु नदी के तट पर दुनिया के कोने कोने से हिन्दु धर्मावलंबी अपने मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अपने जीवन काल में तपर्ण करने के लिए निश्चित तौर पर पधारते हैं । बोध गया जो जस्ट उसके बगल में है भगावान बुद्ध को वहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पूरे देश दुनिया से वहां पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं । और हमारे विपक्ष के लोग जिनकी मंशा है कि बिहार सरकार अगर कोई भी काम करे तो उसको ये लोग हमेशा नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं । और बाहर निकलकर के टी0वी0 में प्रचार करते हैं कि हमसे महान इस दुनिया में कोई नहीं है । और यही वजह है कि इन्होंने बिहार के विकास की लड़ाई पूर्णरूप से छोड़ दिया है । जिस तरह से ये सदन के

अंदर अपना रूख अपनाते हैं अगर वही रूख अपने दल के माननीय प्रधानमंत्री के साथ अपनाये होते तो निश्चित तौर पर आज बिहार मैं समझता हूं कि इतनी उंचाई पर जाता जिसका लाभ हमको भी मिलता । हिन्दु राष्ट्र का नारा देते हैं, मंदिर भी बनाने का नारा देते हैं । और जहां पूरे भारतवर्ष एवं विश्व के हिन्दु जो हिन्दु होते हैं । (व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा: यहां स्मार्ट सिटी के लिए कौन कौन शहर है, वही बता दें ।

श्री कुमार सर्वजीत: वही बता रहा हूं । सभापति महोदय, जहां पर पूरे देश के हिन्दु मोक्ष प्राप्ति के लिए पूजा करने आते हैं गया जैसे शहर में क्या उसको श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं जानते हैं, क्या वैशाली को नहीं जानते हैं, क्या नालंदा को नहीं जानते हैं ? बनारस को जानते हैं बगल के गया और बोधगया से जुड़ा हुआ बनारस है उसको जानते हैं । बनारस स्मार्ट सिटी बन सकता है लेकिन गया स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता है । महोदय, दुर्भाग्य के साथ में यह बताना चाहता हूं कि जो पूरे विश्व में विख्यात है जिसको स्मार्ट सिटी बनना चाहिए था उसी जगह से हमारे विपक्ष के नेता भी आते हैं ।

(व्यवधान)

मै बता दूं अगर माननीय विपक्ष के नेता की इच्छा शक्ति होती और हमारे संजय भाई को इच्छा शक्ति होती कि बिहार में कई स्मार्ट सिटी बने तो निश्चित रूप से यह योजना बिहार को मिलता । महोदय, हमारे विपक्ष के लोगों को काम करने की कम आदत है और टी0वी0 के सामने प्रचार करने की इनको आदत है।

महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग के माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं । पटना, गया, दरभंगा के शहर वासियों को 25-30 कि0मी0 के दायरे में जो सरकार ने 101 सिटी बसों को दिलाया है मैं धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को ।

श्री संजय सरावगी: बसें शहर में नहीं चल रही हैं ।

श्री कुमार सर्वजीत: चलेगा, चलेगा । महोदय, मैं चूंकि बोधगया विधान सभा क्षेत्र से आता हूं मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि बोधगया काफी विश्व विख्यात जगह है और वहां पर आजकल ट्रैफिक की बहुत परेशानी हो गयी है । उनसे आग्रह करता हूं कि उसका निदान किया जाय । और मैं उनसे मांग करता हूं कि बोधगया बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है वहां पर रिंग रोड की आवश्यकता है । जो विदेशी पर्यटक आते हैं और जो नदी का भ्रमण करना चाहते हैं, मंदिर का भ्रमण करना चाहते हैं वे रिंग रोड के माध्यम से चूंकि हमेशा वहां नो इंट्री लगी रहती है और जहां पर वे चाहते हैं नहीं जा पाते हैं तो

मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से वहां पर रिंग रोड का प्रावधान हो ताकि जो पर्यटक आते हैं घंटा दो घंटा के लिए विदेशी पर्यटक आते हैं वे रिंग रोड के माध्यम से फल्गु नदी का भी दर्शन कर सकें, मंदिर को भी देखें और यहां से एक अच्छा अनुभव लेकर जायं । धन्यवाद ।

सभापति (श्री हरि नारायण सिंह): आपका समय समाप्त हुआ ।

माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार । आपके लिए 6 मिनट ।

श्री राजेश कुमार: सभापति महोदय, आज मैं सरकार के पक्ष में नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग के जो बजट योजना दी गयी है उसके पक्ष में और उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और विपक्ष द्वारा जो कटौती प्रस्ताव किया गया है उसके विरोध में बोलने क लिए खड़ा हुआ हूं ।

क्रमशः

टर्न-18/बिपिन/11.3.2016

श्री राजेश कुमार: क्रमशः सभापति महोदय, 2016 के नगर विकास एवं आवास विभाग का जो बजट में प्रावधान किया गया है, मैं समझता हूं कि महागठबंधन की सरकार का यह बहुत ही सराहनीय कार्य है । इसलिए मैं इसका तहेदिल से स्वागत करता हूं ।

महोदय, जैसा कि इस बजट अभिभाषण में मंत्री महोदय द्वारा जो सरकार का योजना मद में 3409.36 करोड़ का प्रावधान किया गया है, वह बहुत ही बिहार जैसे हमारे राज्य में यह कम है और उपर से विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव करना, हम समझते हैं कि इन लोगों द्वारा बिहार के साथ अन्याय होगा कटौती प्रस्ताव को लाकर ।

नगर पंचायत में जिस तरह से सरकार द्वारा नगर पंचायत से नगर परिषद, और नगर परिषद से नगर निगम का पुनर्गठन करने का जो प्रावधान है वह काफी काबिले-तारीफ है जिसका उपदेश सरकार को बापू द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा यह पंचायती राज और पंचायत में जो दबे-कुचले लोग हैं उनको शक्ति प्रदत्त करने का जो प्रावधान किया, हम समझते हैं कि तत्कालीन प्रधान मंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी जी का भी सपना साकार करता है ।

सभापति महोदय, सरकार द्वारा जलमिनार पेयजल आपूर्त्ति योजना के स्थान पर डायरेक्ट सप्लाई की योजना प्रारभ्भ करने का सरकार की जो योजना है, वह गरीबों के हित में है और आम जनता के पहुंच में है । इसलिए यह योजना जो सरकार द्वारा लाई गई है, इस योजना का भी मैं स्वागत करता हूं ।

सभापति महोदय, सरकार नगर विकास योजना में जो योजना समाहित की है वह मुख्यमंत्री जी का और सोनिया जी का और नीतीश कुमार जी का और लालू प्रसाद जी का सोचा हुआ यह सपना लगता है जो गरीबों के लिए जल्द-से-जल्द आएगा जिसमें पटना में वेस्ट इनर्जी, वेस्ट कंपोष्ट, सीटी मोबिलिटी प्लान, अर्बन रोड पॉलिसी, ऑनलाइन प्रोपर्टी मैंनेजमेंट एवं इ.पी.सी.मोड पर अधिक-से-अधिक फ्लैट बनाने की योजना का भी मैं आपके माध्यम से सरकार का स्वागत करना चाहता हूं जो यह नई सोच, नई दिशा और लोगों के लिए सुलभ दिशा निर्धारित करती है । सभापति महोदय, 12 जिलों में किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार सबला कार्यक्रम लाई है जो हम समझते हैं कि पीड़ित, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति-जनजाति के अबला महिलाओं को यह डायरेक्ट सहायता प्रदान करती है । इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदय, कुटुम्बा विधान सभा अनुसूचित जाति-222 से मैं नए सदस्य के रूप में यहां उपस्थित हुआ हूं और प्रथम बार इस सदन में आया हूं और बड़ा ही गौरवान्वित और रोमांचित होता हूं कि महागठबंधन के प्रतिनिधि के रूप में मैं आज आपके समक्ष सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं, इसके अतिरिक्त मैं सदन में भी आभार प्रकट करता हूं ।

सभापति महोदय, जैसा कि हमारे कुटुम्बा विधानसभा-2 के 4पंचायत और कुटुम्बा के 20पंचायत और नवीनगर के 10 पंचायत को मिलाकर हमारा कुटुम्बा विधान सभा का निर्माण हुआ है लेकिन मैं सदन में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि देव मंदिर जो आस्था के पराकाष्ठा का स्थल है, यहां पर साल में दो बार छठ व्रत का पूजा किया जाता है तो हम यह कहना चाहते हैं कि देव को पंचायत का दर्जा मिल जाता तो जो लाखों श्रद्धालु आते हैं उनको एक तरह का बहुत बड़ा सहयोग मिल जाएगा ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह): अब आप समाप्त करें ।

श्री राजेश कुमार एक मिनट महोदय । औरंगावाद के रामा बांध मोड़ पर एक नवनिर्मित पार्क है जो पूरी तरह डेवलप नहीं है, उसे डेवलप कराने के लिए सदन के माध्यम से सरकार को कहना चहाता हूं । साथ ही, बहादुरपूर हाउसिंग कौलोनी, भूतनाथ रोड में अवस्थित सेक्टर 4एच. में भूतनाथ के पूरब में अधूरा पार्क आवास बोर्ड का है, उसके बन जाने से वहां पर बच्चों और बुजुर्गों को काफी सहायता मिलेगा । महोदय, नगर निगम में होल्डिंग टैक्स को सरल और सुचारू बनाया जाए ताकि सरकार आसानी से टैक्स वसूल कर पाएगी। मेयर के चुनाव में जनता द्वारा, जैसा कि झारखंड में और अन्य राज्य में है, तो...

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य लक्ष्मेश्वर राय जी ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित।)

सभापति(श्री हरिनारायण सिंह): श्री रत्नेश सादा । 10मिनट ।

श्री रत्नेश सादा: माननीय सभापति महोदय, मैं नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट भाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और बी.जे.पी. द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

सभापति महोदय, जब ये लोग को विरासत में सत्ता के पक्ष में, सत्ता में भागीदारी मिली थी नगर विकास एवं आवास की तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उस समय आपके मंत्री ईमानदारीपूर्वक राज्य के सभी शहरों में कचरा प्रबंधन एवं नगर निकाय को सुदृढ़ करने का काम किया था ? सभापति महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं । विरासत में लिए गए जो काम मिला, उसको इन्होंने निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन नहीं किया और उलटे आज हमलोग पर दोष मढ़ रहे हैं । महोदय, मैं सरकार की जो सात निश्चय कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में तीन योजना को नगर विकास एवं आवास योजना में लिया गया है । मुख्यमंत्री शहरी पेय जल योजना, हमारी सरकार की मंशा है महोदय कि राज्य के जितने भी शहर हैं, आने वाले पांच वर्षों में सभी परिवारों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराना, यह हमारी सरकार का लक्ष्य है महोदय । महोदय, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपके जो माननीय देश के मुखिया हैं, उन्होंने जो वायदा किया हैं, क्या एक भी वायदा ढ़ाई-तीन साल में पूरा किये हैं... क्रमश:

टर्न-19/राजेश/11.3.16

श्री रत्नेश सादा, क्रमश:- उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी बनायेंगे लेकिन हमारी सरकार का सात निश्चय है, कार्यक्रम हे, तो क्या माननीय मोदी जी स्मार्ट सिटी बनाने का काम किये ? महोदय, हमारी सरकार की दूसरी योजना है सात निश्चय कार्यक्रम में शहरी नाली को पक्कीकरण करना, हमारी सरकार की मंशा है कि राज्य के जितने भी शहर हैं, सभी शहरों में जो नाली बचा हुआ है, उस नाली को पक्कीकरण करके एक स्वच्छ वातावरण देना चाहती है महोदय। सभापति महोदय, हमारी सरकार का तीसरा निश्चय है कि शहर में प्रत्येक परिवारों को शौचालय निर्माण कराना। महोदय, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत चार हजार रुपये की लागत से व्यवस्था की गयी है,वहीं हमारी सरकार ने आठ हजार रुपये दे करके पूरे नगरवासियों को, पूरे बिहारवासियों को, उनके प्रत्येक परिवारों को

शौचालय निर्माण कराने का लक्ष्य है। सभापति महोदय, जलापूर्ति योजना के तहत विगत वर्षों में 32 योजनाएँ ली गयी थी, जिसमें से 31 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, जिसमें जहानाबाद, बिहारशरीफ, सीतामढ़ी, अररिया, नवादा, गोपालगंज, मसौढ़ी, बगहा, मधेपुरा, ढ़ाका, रक्सौल, डुमरा, सुलतानगंज, केसरिया, रामनगर, शिवहर, दाउदनगर, जगदीशपुर, विक्रम, विक्रमगंज, सिमरीबख्तियारपुर, फतुहा, इस्लामपुर, दरभंगा, मखदुमपुर, अरवल, निर्मली और सुपौल शहर में 31 योजनाएँ पूर्ण कर लिया गया है महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि विगत ढ़ाई वर्षों में आपने जो वादा किया था कि प्रत्येक परिवार को 15 से 20 लाख रुपया उनके खाते में देंगे और 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किये थे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि एक भी युवा को नौकरी मिला है क्या ? क्या एक भी परिवार के बीच 15 से 20 लाख रुपया दिया गया है क्या ? मैं इनसे पूछता हूँ कि हमारे मुखिया का जो मंशा है, जो हमारे मुखिया घोषणा करते हैं, उसको वे सतह पर, जमीन पर, उतारते है लेकिन इनके मुखिया तो केवल जुमला की बात करते हैं। महोदय, हमारी सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग को सुदृढ़ करने के लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी का 130 पद सृजित किया गया है, नगर प्रबंधक का 152 पद सृजित किया गया, कार्यपालक अभियंता का 135 पद सृजित किया गया, कनीय अभियंता का 139 पद, टाउन प्लानर का 52 पद एवं एम0पी0डब्लू का 152 पदों का सृजन किया गया है महोदय और अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ढ़ाई साल में ये कितने पद को सृजित कर पाये हैं ? आपके जो सहयोगी दल हैं, जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि टेम्पो चालक जिसको मराठा का ज्ञान नहीं होगा, उसको लाईसेंस नहीं दिया जायेगा और अगर वह टेम्पो चलाता है तो उसके टेम्पू को जला दिया जायेगा, ये प्रधानमंत्री जी के दोस्त है राज ठाकरे जी, मैं आपके नेता से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने एक भी वादा को पूरा करके दिखाया ?

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह):- अब आप समाप्त करें।

श्री रत्नेश सादा:- महोदय, मैं एक बात अंत मे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि बिहार में जितने भी शहर हैं, उस शहर में धोबीघाट का निर्माण कराया जाय और बिहार में जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, जहाँ दलित, महादलित, अल्पसंख्यक जो बसे हुए हैं, वहाँ श्मशानघाट की व्यवस्था किया जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह):- माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम, आप दो मिनट में अपनी बातों को रखें।

श्री सत्यदेव राम:- सभापति महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट पर बहस चल रही है, हम कहना चाहते हैं महोदय कि मैरवा हमारे क्षेत्र में तो कोई नगरपरिषद् या नगर निगम नहीं है, मैरवा एक नगर पंचायत है, जहॉ जलमीनार बन करके तैयार है और उसका पानी सड़कों पर जा रहा है, सड़को पर बह रहा है लेकिन लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इसको तत्काल दिखवा लेंगे। दूसरी बात कहना है कि सीवान जिला मुख्यालय है, वहॉं एक बैलहट्टा जगह है और वहॉं दो से ढ़ाई सौ घर गरीब गुरुए लोग वहॉं पर बसे हुए हैं और उन लोगों को उजाड़ने के लिए लगातार नोटिस जा रहा है प्रशासन की तरफ से लेकिन हमलोगों ने आंदोलन करके यह कहा है कि जब तक गरीबों को बसने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हमलोग इनको उजड़ने नहीं देंगे, चाहे हमें इसके लिए जितना भी लड़ाई लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। महोदय, हम अभी जेल से आ रहे हैं, हम सीवान जेल में पॉच महीने से हैं और उस जेल की स्थिति को हम देख रहे हैं कि जो सफाईकर्मी हैं, सीवान जेल में सफाईकर्मी का 12 पद सृजित हैं लेकिन एक भी पदों पर नियुक्ति नहीं की गयी है और सफाईकर्मियों से काम ठेका पर लिया जा रहा है जिसके चलते उनको भर पेट भोजन भी नहीं मिल रहा है, हमलोगों को देखकर बहुत दु:ख होता है कि वे लोग कैदियों के द्वारा छोड़े गये झूठा को खाकर गुजर-बसर कर रहे हैं.........(व्यवधान)

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह):- अब आप समाप्त करिये।

श्री सत्यदेव राम:- महोदय, इसतरह की स्थिति पूरे बिहार में है, सफाईकर्मियों की कमी पूरे बिहार में है, ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, हम बड़ी-बड़ी बात करते हैं लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो सबसे निचले पैदान में खड़े हैं, उनकी बात हर विभागों में छूट जाती है, हमको मात्र दो ही मिनट का समय मिला है, हम पूरी बात कह नहीं पाते हैं लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं, आग्रह करते है, कि आज सफाईकर्मी पूरे बिहार में लगे हैं, उनकी बड़ी संख्या है, उनको अविलंब नियुक्त करने की सरकार कार्रवाई करें, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह):- माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी।

श्री राजू तिवारी:- सभापति महोदय, आपने मुझे नगर विकास एवं आवास विभाग पर पेश कटौती प्रस्ताव पर अपनी बात को रखने का मौका दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में 14 वार्ड का एक नगर पंचायत है अरेराज और अरेराज के महत्व के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरेराज में भगवान चन्द्रमा द्वारा स्थापित सोमेश्वर महादेव की शिवलिंग का मंदिर है, वहॉ पर आज तक जो भी विकास कार्य हुआ है, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूॅ कि अरेराज में जो प्राइमरी स्कूल बना है, उसका भी जमीन मंदिर के द्वारा दिया गया है, जो मिडिल स्कूल बना है, वह भी मंदिर के द्वारा दिये गये जमीन पर बना है, हाईस्कूल जो बना है, वह भी मंदिर के द्वारा दिये गये जमीन पर बना है, जो गर्ल्स हाई स्कूल बना है, वह भी मंदिर के द्वारा दिये गये जमीन पर बना है, वहॉ पर जो महाविद्यालय है,वह भी मंदिर के द्वारा दिये गये जमीन पर बना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूॅ कि जो वहॉ प्रखंड बना है वह भी मेदिर के द्वारा दिये गये जमीन पर बना है, वहॉ जो अनुमंडल बना है, वह भी मंदिर के जमीन पर ही बना है।

क्रमशः

टर्न : 20 /कृष्ण/11.03.2016

श्री राजू तिवारी (क्रमश :) मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वहां पर लाखों-लाख श्रद्धालु आते हैं, वहां पर न तो शौचालय है, न पानी की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है तो कम से कम मंदिर के द्वारा जितना मिला है, उसमें से ही मंदिर के नाम पर आप विकास कर दीजिये । वह सभी मजहबों और सभी धर्मों के लिये है । वहां पर मंदिर द्वारा दिये गये जमीन पर अस्पताल भी है । इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि सरकार विशेष रूप से अरेराज और महादेव की नगरी को विकसित करने का काम करे ताकि नेपाल और बिहार के कोने-कोन से जो श्रद्धालु लोग आते हैं, उनकी सेवा हो सके ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री ललन पासवान। आप का समय 2 मिनट है ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी अनुसूचित जाति के मुशहर, डोम, मेहतर की है, जो सिर्फ आसन का ही नहीं बल्कि सबों का मैला साफ करने का काम करता है । नशा पीकर, शराब पीकर वह सफाई का काम करता है । वह नशे की आग से पेट की आग बुझाता है और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, वे पूरे बिहार में कंट्रेक्ट पर हैं । मगर इस तरह की परम्परा है, उसके पेट की आग जो भी सरकार आयी, वह नहीं बुझा पायी और अभी तक उसकी नियुक्तियां स्थायी तौर पर नहीं होती है । वह नगर निगम में कंट्रेक्ट पर काम करता है और उसमें भी कंट्रेक्ट है । हमलोग जहां पर रहते हैं, श्री अशोक कुमार सिंह एम0एल0ए0 हैं, ये वहां रहते हैं । एक महीना पर सफाई के लिये जाता है, मैं भी वहीं रहता हूं । वहां नाला की जो स्थिति है । हमको पता चला कि वहां एक राकेश नाम का व्यक्ति इन्सपेक्टर है, एक मजदूर आया और हम से कहा, हम भी दलित है, इसलिए हम से कहा, दूसरे से वह कहता भी नहीं । उसने कहा कि सर आप के तरफ आते हैं तो एक हजार रूपया मांगता है । महोदय, कंट्रेक्ट पर वह काम करता है, इतना भ्रष्टाचार है । आजादी के 67 वर्षों के बाद भी गंगा नदी में लाश बहती है और उसका पानी लोग पी लेते हैं, हिन्दू लोग, सब लोग पी लेते हैं । लेकिन दलित जो गंदगी साफ करता है । सासाराम की गलियों में अंदर तक जाकर कूड़ा उठाने का काम करता है, उसको न्याय अभी तक नहीं मिला । माननीय मंत्री जी उसी समाज के हैं । मैं भी उसी समाज से आता हूं । लेकिन सरकार ने इस दलित समाज का कभी उद्धार नहीं किया । मैं कहना चाहता हूं कि इनका उद्धार करें, ईमानदारी के साथ इनका उद्धार करें । इनलोगों की सरकारी रूप में स्थायी रूप से नियुक्ति करें और बीच में जो बिचौलिये का काम करते हैं, जो माल लूटते हैं, उनके ऊपर नगर निगम प्रतिबंध लगायें । महोदय, एक आग्रह और करते हुये अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, इन तमाम सफाई मजदूरों को जो इंसान नहीं जानवर की भांति पशुवत् जिन्दगी जीते हैं । कोई डोमखाना और स्लम जाकर देख लीजिये, उनके पास पीने का पानी नहीं है, उनकी झोपड़ियां उजाड़ दी जाती है । नगर निगम पहले किया करती थी, नगर निगम उसको लीज पर दे, चाहे जैसे भी दे, उनको रहने की व्यवस्था करने का काम सरकार करे ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, एक मिनट दिया जाय । बड़ा ही गंभीर इसू हैं, मेरे लिये ही नहीं, सदन के लिए भी गंभीर इसू है । जब दलित की बात आती

है तो आसन को भी विशेष ध्यान देना चाहिये । इसीलिये मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे । मेरे यहां चेनारी का बनौली पंचायत है ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री व्यासदेव प्रसाद । आपका समय 12 मिनट है ।

श्री व्यासदेव प्रसाद : माननीय सभापति जी, मैं आज नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लाये गये बजट के विरोध में और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, नगरों का विकास उस प्रांत या देश की सम्पन्नता का प्रतीक है । नगरों के मौलिक आधाारभूत संरचनाओं एवं सेवाओं के विकास राज्य के आर्थिक विकास में महती भूमिका उसकी होती है । शहरी अर्थ व्यवस्था को गतिशील बनाकर समेकित रूप से राज्य के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्त्तन का कारण बनती है । साथ ही, यह स्वस्थ्य मानव संसाधन के विकास में भी अभिवृद्धि करती है। महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के अधीन 11 नगर निगम है, 42 नगर परिषद् हैं एवं 86 नगर पंचायत हैं, जिन्हें राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने एवं शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को मूल रूप से सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग को है । बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग पूर्ण रूप से उपरोक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने में पूर्ण रूप से विफल है। इसलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि नगर विकास की निम्नलिखित प्राथमिकतायें हैं । पहला है - नगर के अंदर जलापूर्त्ति करना, प्रत्येक घरों तक जल मुहैय्या कराना, सरकार ने संकल्प लिया था कि हम प्रत्येक व्यक्ति को 40 हजार लीटर पानी प्रत्येक दिन उपलब्ध करायेंगे। इस मामले में हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहां हैं, जनता के सुख-दुख के मर्म को अच्छी तरह से समझते हैं और मैं समझता हूं कि इस सरकार ने 40 लीटर क्या, एक लीटर पानी भी प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराने में असक्षम रही है और इस समय जलापूर्त्ति की कुछ योजनायें थी । पहले जल मीनार के माध्यम से जल घरों तक पहुंचाया जाता था । घरों तक मैं नहीं कहूंगा, पटना शहर में भले घरों तक पहुंचा दिया गया, घर के अंदर पहुंचा दिया गया, कुछ अन्य शहरों में पहुंचा दिया गया लेकिन जितने नगर परिषद् हैं, जितने नगर पंचायत हैं, उनमें ये जलापूर्त्ति की योजना पूर्णरूप से विफल रही है । यह मैं सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं । हम जनप्रतिनिधियों से जनता मांग करती है कि हमको पानी दो। हमको पानी पीने में बहुत दिक्कत है । हमलोगों को पानी नहीं

मिलता है । इसलिए सरकार ने सोच-समझ कर दिहाती क्षेत्र में हर पंचायत में 5 चापाकल और शहरी क्षेत्र में, हर वार्ड में 2 चापाकल लगाने की अनुशंसा करने का अधिकार दिया था । लेकिन दुख की बात है कि इस सरकार ने इस योजना को स्वयं उसने लागू किया, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, जितने भी टेंडर के माध्यम से चापाकल स्थापित किये जाते हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है । उसको जान-बूझ कर उस अधिकार से विधायकों को वंचित कर दिया गया। साथ ही, साथ एक योजना माननीय मंत्री जी लाये हैं । इन्होंने कहा है कि हम जल मीनार से नहीं, डायरेक्ट जल प्रवाहित कर घरों के अंदर जल भेजेंगे । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या पहले से बने हुये जल मीनार और उसके पाईप लाईन को बंद कर दिया जायेगा और नई यह विधि अपनायी जायेगी कि अब डायरेक्ट लोगों के घरों में पानी जायेगा और उसके लिये लोग तरसेंगे कि सुबह में चलेगा, शाम में चलेगा । लोग बाल्टियां खरीदेंगे, ड्राम खरीदेंगे, पानी भरेंगे और जमा करने लगेंगे ।

क्रमश :

टर्न-21/सत्येन्द्र/11-3-16

श्री व्यासदेव प्रसाद(क्रमशः): इसलिए यह जो पौलिसी लायी जा रही है यह स्पष्ट नहीं है मैं सरकार से मांग करूंगा कि सरकार इसको स्पष्ट करे कि आपका प्रोग्राम यह कैसा है, किस तरह से आप पानी पहुंचाने का काम करेंगे? साथ ही साथ सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से इलाके हैं जहां फ्लोराईड है,आयरन है,सल्फेट है अगर सीधे उसको घर के अन्दर भेजेंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं करायेंगे तो गंदा जल वह बीमारियों का सम्मोहक बनेगा, लोगों को बीमार बनायेगा इसलिए आपकी यह योजना जो है वह पूर्णरूप से विफल होने वाली है और पूरे बिहार को बीमार करने वाली यह आपकी नीति है। मैं निवेदन करूंगा पहले जो नीति चल रही है, उस नीति को लगातार चलने दिया जाय और ये भी उसके पैरलर चलाया जाय। चापाकल का कोई विकल्प नहीं है। मान लीजिये कि एक वोरिंग करते हैं वहां मशीन लगाते हैं पानी भेजने का और वह खराब हो गया तो आठ दिनों तक जो बिहार की स्थिति है उससे भय है हमलोगों को कि आठ दिनों तक यदि उसका निर्माण नहीं हो सका, उसको ठीक नहीं किया गया तो आठ दिनों तक जनता को कहां जाना पड़ेगा, जनता कहां से पानी लायेगी, किस तरह से उसका काम चलेगा? इसलिए चापाकल का कोई विकल्प नहीं है यदि आप विकल्प तैयार कर दें तो चापाकल योजना को समाप्त करें इसका मैं आपसे आग्रह करता हूँ और मैं समझता हूँ

कि पूरा सदन सहमत इससे निश्चित रूप से होगा कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। सभापति महोदय,नगर पालिका का काम है सफाई करना, शहरों की सफाई करना और नाला का निर्माण करना। मैं पटना शहर को ही ले लूं, पटना शहर में ही सफाई की व्यवस्था नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस शहर के अन्दर कभी प्रवेश कर गये, पक्की सड़कों से नहीं गुजरे, गलियों के अन्दर उनका प्रवेश हो गया और उन्होंने ध्यान दिया कहा कि पटना शहर इतना गंदा है कि शर्म से मेरा सर झुक जाता है। इस तरह की सफाई की स्थिति है सरकार के नाक के नीचे। जब शहर की यह स्थिति है तो दूर दराज के शहरों की स्थिति क्या होगी? आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं उस पर विस्तृत नहीं जाना चाहता हूं। जहां तक नालों के निर्माण का सवाल है, मैं तो यह कहना चाहता हूॅ कि यह सरकार नाला इसलिए बनाती है कि उस को नाला बनाने से कमाई हो सके। मैं ऐसा क्यों कहता हूॅ इसलिए मैं कहता हूॅ कि इस सरकार के पास इसके जितने भी 42 नगर परिषद है और 86 नगर पंचायत है इसका कंटूर मैप, नगर विकास विभाग के पास किसी भी शहर का कंटूर मैप नहीं है इसलिए नाला बनाना इनके द्वारा यह एकदम फाल्स है, बेकार है उसका पानी कभी निकलता नहीं है आउटलेट की चिन्ता भी करते हैं कि नहीं कि आउटलेट इस नाले का भी होना चाहिए, जल का कहीं निकासी होना चाहिए। यही कारण है कि जब बरसात आता है तो पटना शहर में जुलूस निकलने लगता है और पटना के जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं वो बेहाल हो जाते हैं, अपने मुहल्ले घरों में जाना बंद कर देते हैं, जनता उनका पीछा करती है इसलिए नालों का निर्माण कराना यदि है तो मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूॅ आपके माध्यम से कि नाले को बनाने के पहले आप पूरा सर्वे कराईए। आपके जितने नगर निगम हैं, नगर परिषद है, नगर पंचायत है सबका कंटूर मैप आप बनवाईए, तब नाला बनाने का काम आप प्रारम्भ कीजिये। ऐसा नहीं होने से नाला में जितना पैसा लगता है वह सब बेकार जाता है, उसमें जल जमाव रहता है, मच्छर पैदा होता है और इससे अनेक बीमारी पैदा होती है इसलिए मेरा यह सुझाव है। नागरिक सुविधा भी आपको प्रदान करनी चाहिए।

डॉ0 मो0 जावेद: सभापति महोदय,मैं आज नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूॅ। महोदय,हमारे बी0जे0पी0 के सदस्यों ने अपने भाषण में शुरूआत की कि पिछले कांगेस राज में और उसके राज्यों में स्थिति बिहार में बद से बदतर है। मैं बताना चाहता हूॅ सर,जब कांग्रेस का शासन था बिहार में तो बिहार के कम से कम 3-4 ऐसे टाउन और सिटीज थे जिनको पूरे हिन्दुस्तान में जाना जाता था और उसको मेट्रोपोलिटन सिटी माना जाता था। चूंकि वहां हर तरह के लोग और समाज रहते थे और पटना में खासकर मुझे बताते हुए खुशी होती है कि यहां पानी का कम्प्टीशन हुआ करता था पटना शहर में जब कांग्रेस का राज था सर,लेकिन जो पिछले

सालों में हुआ उसमें सुधार होगी यह सब का मानना है। हमारे साथी ने बतलाया और हम सब जानते हैं कि 100 स्मार्ट सिटीज हिन्दुस्तान में लेने की बात थी जिसमें से सिर्फ 20 ही लिया गया और अफसोस होता है कि बिहार में एक भी नहीं लिया इन्होंने सर,मेरा विचार कुछ अलग है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वह जलापूर्त्ति हो, नागरिक सुविधाएं, बस स्टैंड के तौर पर हो, शौचालय के तौर पर हो, सफाई अभियान हो, सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान हो या राजीव आवास योजना हो, इन सबको हम वेलकम करते हैं और साथ ही हम चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार हो। जहांतक राजीव आवास योजना की बात करते हैं, 11272 नाकाफी है सर,गुजारिश होगी कि इसकी जो क्वालिटी है वह बेहतर हों और जिन बेनिफिसरीज को आइडेंटीफाई किया जाय उसमें कोई कोताही नहीं हो, अच्छे लोगों को, गरीब लोगों को चुना जाय। उसी तरह जो कम्युनिटी शौचालय है 221 यूनिट है पूरे बिहार में, मेरा मानना है कि इसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए बिहार की आबादी को देखते हुए। मेरा सुझाव होगा सर,जिस तरह रोड मैप बनाया जा रहा है,2035 का रोड मैप बनाया जा रहा है, उसी तरह से सिटी और टाउन के लिए भी हमलोगों को सोचना पड़ेगा। आज एक तरफ जहां हिन्दुस्तान में 33 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है।(क्रमशः)

टर्न-22/मधुप/11.03.16

डॉ0 मोहम्मद जावेद : ..क्रमशः... आज एक तरफ जहॉ हिन्दुस्तान में 33 परसेंट आबादी शहरों में रहती है, हमारे यहॉ लगभग 12 परसेंट रहती है । एक तरह से हमारा सौभाग्य है कि इसका हम फायदा उठा सकें । मेरी गुजारिश होगी कि प्लानिंग के तहत जिला हेड क्र्वाटर को बेहतर टाउन बनाना होगा, ब्लॉक हेड क्र्वाटर को अच्छा टाउन बनाना होगा और यही नहीं, ब्लॉक में कम से कम 5-10 जगह हमलोग चुनें और उसके आसपास जो जमीन हैं, उसको चिन्हित करके फ्युचर के लिए प्लान करें। वहॉ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पीटल वगैरह सुविधाएँ दें ताकि सब लोग पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर न जाकर अपने-अपने इलाके में एक अच्छे शहर में जिन्दगी गुजार सकें । यह मेरा सुझाव है ।

कल बताया जा रहा था कि किशनगंज से पटना आने में 5-6 घंटे लगते हैं, मैं कभी 8 घंटे से कबल नहीं पहुँच पाया । खराब रोड है, उसकी वजह से नहीं, रोड काफी बेहतर है लेकिन जिन-जिन शहरों से हम गुजरते हैं, इनक्रोचमेंट की वजह से कहीं-कहीं पर एक घंटा - दो घंटा लग जाता है । दरभंगा और मुजफ्फरपुर में कभी-कभी एक-दो घंटा लग जाता है । मेरी गुजारिश होगी कि

हमलोग उन जगहों को चिन्हित करें । क्यों होता है ? मैं जानता हूँ कि जब स्कूल टाइमिंग होता है, उसकी वजह से हो या शाम को सब्जी मार्केट लग जाता है, मैं चाहूंगा कि शहरों में हमलोग अलग-अलग जगह चिन्हित करके वहॉ पर हाट-बाजार करें । जिस तरह एक छोर से दूसरे छोर तक हम 5-6 घंटे में आना चाहते हैं, उसी तरह शहरों में भी हमलोगों का टारगेट रहना चाहिए कि एक छोर से दूसरे छोर या एक जगह से दूसरे जगह आधे घंटे के अन्दर या 20 मिनट के अन्दर जरूर पहुॅच पायें । यह हमारा सुझाव होगा ।

महोदय, हमारे यहॉ रमजान नदी है, पार्क/प्ले-ग्राउंड की सख्त जरूरत है। हमारे यहॉ बिहार में कई ऐसे शहर हैं जहॉ नदियॉ हैं, कई ऐसे शहर हैं जहॉ बड़े-बड़े तालाब हैं, हमारी सरकार से गुजारिश होगी कि उनको आप इनक्रोचमेंट से भी बचाइये और उनका सौन्दर्यीकरण कीजिये ताकि हमारे बच्चों और सीनियर लोगों को खेलने और टहलने के लिए जगह मिले ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : अब आप समाप्त करें ।

डॉ0 मो0 जावेद : इन्हीं चन्द बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री हरिनारायण सिंह) : माननीय सदस्य श्री सैयद अबु दौजाना ।

श्री सैयद अबु दौजाना : सभापति महोदय, आज मैं वित्तीय वर्ष 2016-17 के नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट पर बोलने के लिए महागठबंधन सरकार के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ । इसमें महागठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी एवं हमारे गठबंधन के तमाम मंत्रीगण, तमाम पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यगण तथा हमलोगों को मार्गदर्शन देने वाले माननीय अध्यक्ष महोदय को मैं विशेष तौर पर अपनी ओर से मुबारकवाद देता हूँ ।

सभापति महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग के पिछले साल के मुकाबले में इस वर्ष अत्यधिक राशि की व्यवस्था कराकर राज्य के अन्य शहरों के विकास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर लाने के लिए कदम उठाये गये हैं, वह सराहनीय है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए हमारे गठबंधन के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार की अगुवाई में वित्त मंत्री एवं नगर विकास विभाग के मंत्री महोदय के अथक प्रयास से रात-दिन एक करके नगर विकास विभाग के लिए खाका तैयार कर जो बजट बनाया गया है, उसके लिए मैं तहेदिल से महागठबंधन की सरकार को धन्यवाद देता हूँ । महोदय,

वर्ष 2016-17 के लिए 3409 करोड़ 36 लाख रूपये आवंटित कर बिहार राज्य के सभी शहरों के विकास के लिए महागठबंधन की सरकार ने सराहनीय कदम उठाने का काम किया है ।

अध्यक्ष महोदय, गॉव के बनिस्पत लोगों के रहने-सहने, आने-जाने, बीमार पड़ने पर दवा और ईलाज कराने, पढ़ाई-लिखाई, रोजगार की सुविधा शहरों में ही मिलते हैं, चूँकि कल-कारखाने शहरों में ही मिलते हैं । महोदय, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हो या और भी इसी तरह की रोजमर्रा की चीजें भी, सभी शहरों में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं । अध्यक्ष महोदय, आपको पुनः वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार भारत शहरों की आबादी ग्रामीण आबादी की तुलना में लगातार बढ़ रही है, परन्तु दूसरे राज्य या केन्द्र शासित प्रदेशों की तुलना में बिहार का शहरीकरण काफी पिछड़ा हुआ है । इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं ? इसपर हम विशेष रूप से अपने विपक्षी भाइयों को जिम्मेदार मानता हूँ । महोदय, जब भाजपा के साथ जब इनकी जब गठबंधन थी, निश्चित रूप से मैं उस समय गठबंधन की सरकार को कोसना चाहता हूँ । पिछली सरकार ने ऐसे लोगों के हाथों में इतना महत्वपूर्ण विभाग कैसे दे रखा था, जो निश्चित रूप से नकारा और निकम्मा साबित हुए । महोदय, हम देख रहे हैं कि पिछले 9 वर्षो तक उनके गठबंधन की सरकार थी, इन्हीं विपक्षी भाइयों के मंत्रीगण मीडिया में, अखबारों में लम्बा-लम्बा भाषण दिया करते थे कि पटना को पेरिस से भी सुंदर बनायेंगे । इसी तरह के भाषण हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी के द्वारा, जो अब लोकसभा के सांसद हैं, टी0वी0 और पेपर में छाये रहने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना कर बक्सर के लोगों को भी सब्जबाग दिखलाने का काम कर रहे हैं । इन्हीं के कार्यकाल में कंकड़बाग कॉलोनी एवं राज्य के अनेक शहरों में तथा अभी जहॉ हमलोग सदन में बैठे हैं, वहॉ भी पानी का जमाव था ।

अध्यक्ष : दोजाना जी, अब एक मिनट में समाप्त कीजिये ।

श्री सैयद अबु दोजाना : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में हमारे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में प्रेम कुमार जी विराजमान थे, लेकिन अभी हैं नहीं । उनके राज में भी सभी शहरों को विकसित शहरों के रूप में खूब टी0वी0 चैनलों पर बैठकर प्रेस में जारी करके कि पटना को यह बना दूंगा, वह बना दूंगा, बिहार के अन्य शहरों को भी सातवें आसमान पर बैठा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये लोग भी तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, लोग अभी भी अपनी पूरी ताकत के साथ जी-जान लगाकर हमारे गठबंधन की सरकार को हर तरह से धावा बोलकर टी0वी0

और पेपर में कि फिर से जंगलराज-2 आ गया । कितनी शर्म की बात है कि छोटी-छोटी घटनाओं को बड़े से बड़ा रंग-रूप देकर गलत प्रचार कर रहे हैं । ये लोग बिहार के नहीं हैं क्या, ये लोग नागपुर के हैं ? महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग ऐसे झूठ प्रचार कर रहे हैं । बिहार कैसे तरक्की करेगा ? बाहर से आने वाले लोग झूठे प्रचार से कैसे आयेंगे ?

अध्यक्ष : दोजाना जी, अब समाप्त कर दीजिये ।

श्री सैयद अबु दौजाना : महोदय, हमारे क्षेत्र में या जहॉ-जहॉ शहर है, वहॉ-वहॉ धोबी घाट नहीं है, धोबी घाट के लिए मंत्री जी से मैं आग्रह कर रहा हूॅं कि हर जगह धोबी घाट का इंतजाम पूरे बिहार में किया जाय ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें । आपका समय समाप्त हुआ । अब बैठ जाइये ।

श्री सैयद अबु दोजाना : 1990 में बरौली में जल मीनार का जो शिलान्यास हुआ था, आज तक उसके कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूॅं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज के वाद-विवाद के क्रम में माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने हस्तक्षेप करने की अनुमति मॉगी है । मैं उन्हें अनुमति देता हूॅं । माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय..... (व्यवधान)

बैठ जाइये । मेरी बात सुनिये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोगों की भावना को देखते हुए ही हमने अनुमति दी है । चापाकल के बारे में आप उनसे सुन लीजिये । शांत रहियेगा तब न सुनियेगा !

टर्न-23/आजाद/11.03.2016

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा : हम भी आपको निराश नहीं करने वाले हैं । आपलोग हमारी बात खामोशी से सुन लीजिए ।

अध्यक्ष : देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तकरीर का आगाज अल्लामा इकबाल के उस मशहूर शेर से करना चाहता हूॅं :-

परवाज तो दोनों की है एक ही फिजां में,
करकश का जहां और है, शाहीन का जहां और ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपके पास समय 10 मिनट है ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा : महोदय, सम्पन्न विधान सभा चुनाव में जब हमलोग प्रचार में थे, हमारे नेता 7 निश्चय की बात कर रहे थे और बिहार की महान जनता ने उन्हीं 7 निश्चयों पर विशाल बहुमत दिया और हम दुबारा बिहार में सुशासन की सरकार बनाने में कामयाब हुए । हमारे नेता इन 7 निश्चयों पर कितने संवेदनशील है कि हमलोगों को कई अवसरों पर देखने को मिला है, खासकर के मंत्रिमंडल की बैठक में । मुझे पूरा यकिन और भरोसा है कि आने वाले दिनों में बिल्कुल निर्धारित समय सीमा के अन्दर हम इन 7 निश्चयों पर पहुँचने और कामयाब होने में निश्चित रूप से सफल होंगे ।

महोदय, आज से पहले 40-50-60 के दशक में गांवों की क्या स्थिति थी । गांव में मुश्किल से एक-दो कुँआ हुआ करता था और उस कुँआ का पानी पूरे गांव के लोग पीते थे । इतनी दु:खद स्थिति थी कि कोई-कोई गांव में एकाध बड़े आदमी का कुँआ होता था, जिसपर पूरा गांव निर्भर करता था । लेकिन धीरे-धीरे चापाकल का दौर आया और लोगों को चापाकल के माध्यम से और विभाग के माध्यम से चापाकल की आपूर्त्ति हुई और शुद्ध पेयजल पीने का मौका मिला । आज की परिस्थिति में माननीय श्री नीतीश कुमार ने महसूस किया कि लोगों की भावना क्या है और गांवों में जो पलायन होता है, उसमें एक कारण यह भी है कि गांव में सुविधाओं का अभाव है। पलायन होता रहा है लेकिन अब रूका है .....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बातचीत में नहीं फंसिए, आप अपनी बात कह डालिए, समय कम है ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा : महोदय, पलायन इसलिए रूका कि आज 24 घंटे गांवों में बिजली मिल रही है और गांव-गांव तक ही नहीं एक-एक दरवाजे तक, एक-एक गरीब के दरवाजे तक पाईप लाईन के माध्यम से पानी देंगे, वह पानी जो शहर में इस्तेमाल करते हैं । गांव का आदमी शहर आता था, क्या देखता था कि यहां 24 घंटा बिजली है,नल खोला तो पानी निकला,जबकि वहां पर कुँआ का पानी भरना पड़ता था । बहुत मुश्किल से चापाकल है तो चापाकल से पानी मिलता था । यहां पर सुविधायें ज्यादा थी, इसलिए गांव का गरीब शहर की तरफ भाग रहा था । अब परिस्थितियां बदली है । माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चयों में 2 निश्चय हमारे विभाग से जुड़ा हुआ है - शौचालय निर्माण और घर-घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारा विभाग और हमारे विभाग के सारे अधिकारी पूरी तरह से गंभीर है कि हम किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री का जो निश्चय है, वे जो चाहते हैं कि गांव-गांव में हर गरीब के दरवाजे तक पाईप लाईन के माध्यम से जल उपलब्ध करायेंगे और शौचालय का निर्माण करायेंगे, इसके लिए पी0एच0ई0डी0 विभाग बहुत ही गंभीर है । हमलोगों ने महसूस किया कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं, 1,10,140 बसावट है और

इस सम्पूर्ण छोटे-बड़े बसावटों में विभिन्न तरह से हमलोग जलापूर्त्ति का कार्यक्रम देने जा रहे हैं । जो बड़ा बसावट है, वहां बड़ी योजना है जलापूर्त्ति की और जो छोटा है, वहां मिनी जलापूर्त्ति के माध्यम से जल उपलब्ध कराने की हमारी इच्छा है और हम ऐसा करने जा रहे हैं । साथ ही कुछ और भी समस्यायें इस दिशा में है । कहीं-कहीं पर आर्सेनिक फ्लोराईड और आयरन की समस्या है तो हम इस समस्या से मुक्त कराने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर के शुद्ध जल आम जनता को मिले, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं । हमारे बिहार के सभी जिलों में इसकी जॉच के लिए लेबोरेटरी है, जहां जल की जॉच की जाती है और जहां दोष पाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाती है । इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है केवल जल पहुॅचाना नहीं, बल्कि शुद्ध जल पहुॅचाना । इसके साथ-साथ आज के युग में भी हमलोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे मॉ-बहने सूर्यास्त का इन्तजार करती है और सूर्योदय से पहले शौच के लिए जाती है, गांव की यह स्थिति है । गांव में अगर हमलोग शौचालय घर-घर बना देते हैं तो गांव की दशा सुधरेगी और स्वच्छता का वातावरण बनेगा । इस दिशा में भी हमारा विभाग बहुत गंभीर है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से या स्वयंसेवी संस्थानों के माध्यम से और कहीं-कहीं पर जीविका के माध्यम से हम गांव-गांव में शौचालय निर्माण का काम बड़े पैमाने पर करा रहे हैं । हमारा लक्ष्य है कि इन निर्धारित पॉच वर्षों में पूरी तरह से हर गांव में, हर घर में शौचालय का निर्माण करा दें तथा उन्हें शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध करा दें ।

श्री ललन पासवान : महोदय, हमारे क्षेत्र में पानी की काफी दिक्कत है, पहाड़ पर पानी नहीं मिल रहा है ....

अध्यक्ष : ललन जी, मंत्री जी को बोलने दीजिए । आप बोलिए मंत्री जी । मंत्री जी, आपको 3-4 मिनट में सारी योजना बता देनी है ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा : महोदय, इस संबंध में माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूॅ, आपलोग घबरा रहे हैं, हमारे विभाग में पहले मुख्यमंत्री चापाकल योजना थी, इसके लिए आप चिन्तित हैं । अब मुख्यमंत्री पेयजल योजना सरकार लागू कर रही है और मुख्यमंत्री पेयजल योजना में आपकी सहभागिता होगी और आपसे राय ली जायेगी । आपसे पूछा जायेगा कि आप अपने क्षेत्र में कैसे लागू करना चाहते हैं । इसलिए आपका इनवोल्वमेंट होगा, आप क्यों परेशान होते हैं.......

श्री संजय सरावगी : माननीय मंत्री जी, जब तक पाईप लाईन से पानी नहीं देते हैं, तब तक चापाकल को तो चालू रखिए ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप आसन की तरफ देख कर बोलिए, आप उधर देखते हैं तो डाइवर्ट हो जाते हैं ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा : महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ी योजना है और चुनौती पूर्ण कार्य है और समाज के लिए, इस राज्य के लिए बहुत चुनौती पूर्ण कार्य है और इसमें सारे माननीय विधायकों का सहयोग चाहिए । माननीय मुख्यमंत्री जी एक अच्छा काम निश्चय के माध्यम से करना चाहते हैं और इस कार्य में आप तमाम लोगों का सहयोग चाहिए और हमको विश्वास है कि आप अपने क्षेत्र की जनता की आवश्यकता को समझते हुए, उनकी भावना को समझते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नेक इरादे हैं, उसको समझते हुए आप इस कार्य में सहयोग देंगे । हमारे विभाग ने बहुत बड़ी राशि का बजट में प्रावधान किया है 17 अरब 54 करोड़ 98 लाख 54 हजार रू0 का और हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में हम अपनी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुॅंचाने में सफल होंगे । इन्हीं चन्द शब्दों के लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का शुक्र गुजार हूँ । अब आखरी में यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ -

ऐ ताहिरे लाहुती, उस रिज्क से मौत अच्छी,
जिस रिज्क से आती है, परवाज में कोताही ।

बहुत,बहुत धन्यवाद ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने चापाकल के बारे में कुछ नहीं कहा, एक तरफ चापाकल बन्द करा रहे हैं ....

अध्यक्ष : आप बैठिए । माननीय मंत्री जी ने आपलोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना दी कि जो आनेवाली मुख्यमंत्री पेयजल योजना है, उसमें विधायकों की भी सहभागिता होगी, यह आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है ।

माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

टर्न:24/अंजनी/दि0 11.03.16

सरकार का उत्तर

श्री महेश्वर हजारी : अध्यक्ष महोदय, नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से बजट भाषण में कुल 15 माननीय सदस्यों ने भााग लिया । पक्ष-विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने बहुत ही मूल्यवान सजेशन दिये और हमारे विभाग के सभी पदाधिकारियों ने जो समस्यायें बतायी, उनको नोट करने का काम किया है । प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष सरकार के अंग होते हैं और जो भी समस्यायें बताती हैं, वह सरकार के फायदे के लिए होती है । मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार प्रकट करना चाहता हूँ और मैं आशा और विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की सरकार कभी-भी किसी को, चाहे वे किसी भी दल के माननीय सदस्य हों, विकास में कभी कहीं अवरोधक नहीं रहे हैं । उसका मैं ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूँ । जब हम वर्ष 2005 में विधायक बने तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के यहां जाते थे जब वे मुख्यमंत्री थे तो मैं उनसे कैसे प्रभावित हुआ, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी विकास के मामले में एक कदम आगे रहते हैं और वे बहुत आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करते हैं । इसी के कारण हमने अपने क्षेत्र में, आप समझिए कि 90 परसेंट रोड सिर्फ वर्ष 2005 में बनाने का काम किये । तो कोई भी नेता, लीडर होता है, प्रजातंत्र में जनता जिसको वोट देती है, वह सरकार होती है और सरकार होने के बाद वोट नहीं देने वाले के बारे में भी सोचना सरकार का फर्ज होता है । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं मंत्री के नाते, बिहार सरकार के नाते पक्ष हों या विपक्ष हों, विकास में कभी-भी बेईमानी करने का काम नहीं करूँगा, सभी साथियों को मदद करने का काम करूँगा, सबको साथ लेकर चलने का काम करूँगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ । हमारा विभाग पिछले वर्ष जो काम कर रहे थे, उसमें मेन पावर की कमी थी, जिसके कारण हमारा विभाग आगे तेज गति से नहीं बढ़ पा रहा था । मैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने नगर विकास अभियंत्रण सेवा संवर्ग बनाकर और जो हमारा मेन पावर था, जो इंजीनियरों की कमी थी, कर्मचारियों की कमी थी, उसका कुछ हल किया गया है, जिससे हमारा विभाग आगे बढ़ने का काम करेगा । मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन साथियों ने जहां-जहां की समस्यायें कहीं, मैं उन समस्याओं पर बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वह बजट की बात है लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूँ विपक्ष के साथियों से कि चूंकि आप बिहार के निवासी हैं साथियों और बिहार का जो शहर हैं, उसके विकास के लिए नगर निकाय होते हैं, नगरपालिका होती है, नगरपरिषद होती है । वह आईना होता है और यह शहर जब साफ रहेगा, सुन्दर रहेगा,

अच्छा रहेगा तो इससे बिहार का इमेज पूरे देश में बनेगा और इससे आपका भी सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगाी, और हमारा भी सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी । मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र में मतदाता एज ए जज होता है । जब लोक सभा का चुनाव हो रहा था, उस समय में जनता ने उनको भारी मतों से, एन0डी0ए0 को जीताने का काम किया और इस आशा के साथ काम किया कि उनको जब हम वोट देंगे तो हमारी बेरोजगारी दूर होगी, काम मिलेगा । जब बिहार का विधान सभा का चुनाव हुआ तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, महागठबंधन को एज ए जज जनता ने फैसला लिया । तो जनता जो जनादेश देती है, उसको पक्ष और विपक्ष को मानना पड़ता है, लेकिन क्या हुआ साथियों ? आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं, जो कथनी है, वही काम भी करते हैं लेकिन आदरणाीय प्रधानमंत्री जी के कथनी और करनी में क्या फर्क हुआ ? उन्होंने जिस तरह से लोक सभा के चुनाव में लोगों को लुभावना भाषण देकर अपने पक्ष में वोट लेने का काम किया । उस तरह से साथियों मैं समझता हूँ कि यह दुर्भाग्य की बात है कि आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं ? स्मार्ट सिटी के कानून बनाने वाले कौन हैं ? स्मार्ट सिटी बनाना, कानून बनाना, वह भारत सरकार के जिम्मे है, उसको चिंहित करना भारत सरकार का काम है तो मैं समझता हूँ कि क्रेटेरिया में बिहार नहीं आ रहा है, यह कौन बात है ? जहां-जहां विपक्ष की सरकारें थीं, वहां का एक भी स्मार्ट सिटी नहीं लिया गया तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार बिहार विरोधी है । इसलिए भारत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि बिहार पिछड़ा हुआ है, यदि आप बिहार को मदद नहीं कीजियेगा तो बिहार आगे नहीं बढ़ेगा और जब बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तो भारत आगे नहीं बढ़ सकता है । इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करूँगा कि जिस तरह से आपने स्मार्ट सिटी के बारे में पूरा हल्ला करने का काम किया और स्मार्ट सिटी में आपने पैसा कितना दिया ? स्मार्ट सिटी में आपने 100 करोड़ रूपया देने का काम किया । 100 करोड़ रूपया में क्या स्मार्ट सिटी की कल्पना की जा सकती है ? यह दुर्भाग्य की बात है, किस तरह से भारत सरकार जोर-जोर से हल्ला करके पैसा देने का काम करती है ? 100 करोड़ रूपया एक वर्ष में देगी तो क्या उससे स्मार्ट सिटी बन सकता है ? कभी-भी स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती है और आप भारत सरकार की योगदान की बात करते हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांत रहिए न ।

श्री महेश्वर हजारी : आप भारत सरकार की योगदान की बात करते है ? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरावगी जी, आप कहते हैं कि इतना पैसा दिया भारत सरकार ने । हम आपको बताना चाहते हैं कि कुल योजना तथा गैर योजना मिलाकर 3409 करोड़ रूपया

का प्रावधान है, इसमें केन्द्र की प्रस्तावित सहायता मात्र 1169 करोड़ है । 3409 करोड़ में से 1169 करोड़ रूपया है, यह मात्र 33परसेंट होता है और शेष 540 करोड़ रूपया यानि 66 परसेंट स्टेट प्लान का पैसा है, राज्य सरकार का पैसा है और कहते हैं कि भारत सरकार ने दिया, भारत सरकार ने दिया । क्या दे दिया ? सुन लिजिए, सुनने की इच्छाशक्ति विकास के लिए आपको होनी चाहिए । एक नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद बिहार को कहां-कहां से पहुंचाने का काम किया, सिर्फ भाषण से राज नहीं चलता है, काम करने की नीयत होनी चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए । एक आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी रात-दिन ऋषि की तरह काम करके बिहार को बनाने का काम कर रहे हैं । नगर विकास विभाग नीतीश जी के नेतृत्व में, आप पांच वर्ष में देखियेगा कि क्या काम करेगी, यह मैं बताने का काम करूँगा । साथियों, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से.....

(व्यवधान)

मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना, जिस तरह की योजनायें हैं और आग्रह करेंगे कि हमारी सरकार जो इस बार नगर विकास एवं आवास विभाग में जिस तरह से काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि पांच वर्षों के अन्दर जिस गति से हमलोग बढ़ रहे हैं और उस गति को अब और आगे बढ़ाने का काम करेंगे । साथ-ही इसमें बिहार आवास बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका होगी । बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बिहार के विभिन्न शहरों में अर्जित संपदाओं को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की दिशा में सार्थक पहल की गयी है । इससे संपदाओं के मूल्यों का निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत राशि देकर, आवंटी संपदाओं का लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्त्तित करा सकते हैं । दलपतपुर आरा के 16.50 एकड़ भूखंड पर 1054 फ्लैटों के निर्माण हेतु माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा शिलान्यास किया जा चुका है । कार्यारम्भ की कार्रवाई अंतिम चरण में है । बरारी, भागलपुर आवासीय कॉलोनी के 3.72एकड़ भूखंड पर कुल 272 फ्लैटों के निर्माण हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । सभी के लिए आवास(शहरी) योजना के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को नोडल एजेंसी मनोनीत किया गया है । सरकार वित्तीय वर्ष 2016-17 में बोर्ड की संपदाओं के लिए आरक्षण नीति लागू किया जायेगा । जितवारपुर, समस्तीपुर में अर्जित भूखंडों को आवासीय, व्यावसायिक एवं आवासीय-सह-व्यावसायिक भूखंडों में चिंहित कर आरक्षण नीति के आधार पर आवंटित किया जायेगा । अभी हाल-फिलहाल में हमलोगों ने गरीबों के लिए भी घोषणा किया है और गरीब के लिए भी सरकार चिंतित है कि किस तरह से उनको मकान मिले । राजीव आवास योजना के तहत इस योजना में समरूप एवं समतुल्य शहरों वाले स्लम मुक्त भारत की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रत्येक नागरिक

को बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाएँ तथा समुचित आश्रय सुलभ हो । इस योजना के अधीन केवल 7 परियोजना में 11276 आवासीय इकाई स्वीकृत है, जिसका कार्य आरंभ हो चुका है । लाभुकों के बीच राशि का वितरण शिविर के माध्यम से किया जा रहा है । विभाग के द्वारा कार्यकारी अभिकरण की 9619.49 लाख (छियानवे करोड़ उन्नीस लाख उन्नचास हजार रू0)दिये जा चुके हैं । अब तक छः परियोजनाओं में कुल 3107 लाभुकों का खाता खोलकर 3536.46 लाख (पैंतीस करोड़ छत्तीस लाख छियालिस हजार रू0) राशि वितरित की जा चुकी है । स्वीकृत परियोजना की अद्यतन स्थिति निम्नवत है :-

पटना फेज-1 में कुल स्वीकृत आवासी इकाई-759, पटना फेज-2 में है 1061, पटना फेज-3 में 1073, गया फेज-1 में 1970, दरभंगा फेज-1 में 2190, कटिहार फेज-1 में 2038, पूर्णियां फेज-1 में 2185 ।

इस तरह से कुल स्वीकृत आवासीय इकाई-11,276, कुल परियोजना लागत 45465.40 लाख एवं अबतक कुल विमुक्त राशि 9619.49 लाख है ।

...क्रमशः....

टर्न-25/शंभु/11.03.16

श्री महेश्वर हजारी : क्रमशः......उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75/25 के अनुपात में है, केवल पटना के लिए 50/50 की हिस्सेदारी निर्धारित है। सबके लिए आवास योजना- इस योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जून, 2015 में दी गयी है। इस योजना के तहत चार घटकों में शहरी क्षेत्र के आवास विहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के चार घटक........व्यवधान.......भारत सरकार को शेयर हमलोग भी देते हैं, हमलोग भिखाड़ी नहीं हैं जो हाथ बढ़ायेंगे। भारत सरकार का कर्त्तव्य है हर स्टेट को पैसा देना। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण- योजना का ऋण 2015-16 में 40 नगर निकायों में पाये गये 13315 परिवार को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गयी है। आवास के निर्माण लाभुकों के द्वारा स्वयं किया जायेगा। इसके लिए 1 लाख 50 हजार भारत सरकार एवं 50 हजार राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। अन्य 45 नगर निकायों से प्राप्त प्रस्ताव को भी भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। ऋण आधारित ब्याज सबसिडी- इस घटक के तहत 7 शहरी गरीबों के द्वारा आवास के निर्माण हेतु लिये गये निर्णय

आधारित सबसिडी केन्द्र सरकार द्वारा दिया जायेगा। भागीदारी से किफायती आवास- इस घटक का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा विभिन्न भागीदारी से बनाये जा रहे पक्का आवास हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। किफायती दर पर इ0डब्लू0एस0 वर्ग के लिए आवासों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु राज्य सरकार अपनी एजेंसियों अथवा उद्योग सहित निजी क्षेत्र के साथ भागीदारों के माध्यम से किफायती आवास परियोजनाओं की योजना तैयार कर सकती है। ऐसी परियोजना में 1.50 लाख की दर से केन्द्रीय सहायता सभी इ0डब्लू0एस0 आवासों के लिए उपलब्ध होगी। समेकित आवास एवं मलिन बस्ती का विकास कार्यक्रम- यह आइ0एच0एस0डी0पी0 योजना के अधीन बिहार में 28 शहरों के लिए 32 परियोजनाओं भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत की गयी है। इन 32 परियोजनाओं में कुल 28 हजार 623 आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु कार्य चालू है। इसमें एच0पी0एल0 हिन्दुस्तान प्रीफेब लि0 द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे 14 परियोजनाओं का काम अंतिम चरण में है। शेष 16 परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नगर निकायों के माध्यम से सीधे लाभुकों के द्वारा कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। इसके लिए शिविर के माध्यम से...........

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय, लंबे समय से मैं कह रहा था कि बिहार में मुख्यमंत्री नगर विकास योजना जो चल रहा था उसकी चर्चा हम करना चाह रहे थे मंत्री जी से कि आखिर किस कारण से बंद किया जा रहा है। इससे शहरी क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम हो रहा था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसके बारे में कुछ जानकारी दें।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप अपना वक्तव्य जारी रखें और एक-एक करके सबकुछ बतायेंगे।

श्री महेश्वर हजारी : महोदय, आदरणीय हमारे विपक्ष के नेता बहुत विलंब से आये हैं। पहले मंत्री थे और उनके मंत्रित्वकाल से लेकर अभी तक जो काम हुआ है उसकी समीक्षा करेंगे कि तीन महीना में हमलोग कितना काम किये हैं।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, मेरे समय में चालू हुआ था, जब मैं मंत्री था तब हमने चालू करवाया था। ये बंद करवा रहे हैं, कैसी सरकार है ? इसमें इनको और राशि बढ़ाना चाहिए।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : प्रेम बाबू, किस तिथि को हुआ जरा बता दीजिए। आपके मंत्रित्वकाल में हुआ, किस तिथि को कैबिनेट ने डिसाइड किया यह बता दीजिए। कुछ भी बोल देते हैं, जैसे आपके मेम्बर बोल देते हैं, आप भी विरोधी दल के नेता होकर बोल देते हैं।

श्री प्रेम कुमार : विजेन्द्र बाबू, यह आपको भी जानकारी है, आप भी सरकार में थे और सरकार ने फैसला लिया था...व्यवधान.....क्या बात करते हैं। मैं जब मंत्री बना महोदय...

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : आपके समय में नहीं हुआ था।

श्री प्रेम कुमार : मैं चैलेंज देता हूँ। मेरे समय में हुआ था। पहली बार कैबिनेट की बैठक में हमने उठाया था विषय को और हमने लागू करने का काम किया था और आप बंद कर रहे है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रेम बाबू साथ थे तो किसलिये बोल रहे हैं।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, स्लम बस्तियों में सरकार ने स्लम पौलिसी बनाया गरीबों को बसाने के लिए, रेंडर पौलिसी बनाया उसके बारे में कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, सरकार प्रकाश डालने का काम करे।

अध्यक्ष : प्रेम बाबू, बैठ जाइये। सदन में सभी माननीय सदस्य शांति बनाये रखें। माननीय मंत्री जी का वक्तव्य जारी रहेगा।

श्री महेश्वर हजारी : हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता बोल रहे थे ठेला भेंडरों के बारे में- सरकार द्वारा 2012 में इस हेतु कानून बनाया। फिर 2014 में केन्द्रीय कानून आ गया। जब राज्य सरकार उस कानून को अक्षरशः लागू कर रही थी तभी भारत सरकार का कानून आ गया तो भारत सरकार के अनुसार चल दिये। भारत सरकार जो भी शेयर देती है तो कानून उसके अनुसार करना पड़ता है। जिस तरह से मैं बताना चाहता हूं नमामि गंगे में- नमामि गंगे में भारत सरकार पैसा देती है और इतना दिन से हल्ला हो रहा है नमामि गंगे और अभी तक एक रूपया बिहार सरकार को नहीं दिया गया। अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ नमामि गंगे में और इतना ही नहीं पैसा देने के पहले उसका एजेंसी भी वहीं से ठीक कर दिया गया केन्द्रीय एजेंसी और यदि कोई फोल्ट होगा तो कहेगी कि बिहार सरकार ने गलती की। हम बिहार में हैं, बिहार की बात करते हैं। यह नगर विकास का मामला है नमामि गंगे।

राज्य के 42 शहरों में बायोलोजिकल सर्वे चल रहा है, 50 हजार से अधिक भेंडरों का सर्वे हो गया है। राज्य में 200 से अधिक भेंडिंग जोन चिन्हित कर लिये गये है। मुख्य सचिव द्वारा सभी डी0एम0 एस0पी0 को आदेश दिया गया है कि भेंडरों को अनायास जहां पर हैं वहां से नहीं हटाया जाय। स्पेशल आदेश दिया गया है, जो चिंता चूंकि हमलोगों की सरकार महागठबंधन की सरकार, गरीबों की सरकार है। आपलोगों के जैसे हमलोग नहीं है, हमलोग गरीब से चुनाव जीतकर आये हैं, गरीबों की चिंता करते है। इसलिए हमलोगों ने पहले आदेश कर दिया है कि किसी भी भेंडर को हमलोग नहीं हटायेंगे। यह हमलोगों की चिंता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलिये मंत्री जी।

श्री महेश्वर हजारी : आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सात निश्चय है। उस सात निश्चय में तीन निश्चय मेरे विभाग का है और तीन निश्चय में जब हम जमीन में उतारेंगे, जब वह जगह पर उतरेगा तो देखियेगा कि जनता के साथ जो विकास पुरूष बोलता है, वह करता है। आपलोगों के जैसा भागता नहीं है।

श्री प्रेम कुमार : यह सात निश्चय नहीं धोखा है। हमलोग सदन का बहिष्कार करते हैं।

(इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्यों ने सदन से वाक आउट किया)

श्री महेश्वर हजारी : मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना- इस योजना के अन्तर्गत अगले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्र की वैसे गलियों एवं नालियों का जिसका पक्का निर्माण नहीं हो पाया है, उसको पूरा कराया जायेगा। नालों के चयन के चयन के आउटफोल एरिया को प्राथमिकता दी जायेगी। सबसे ज्यादा जल जमाव वाले स्थान पर ट्रंक चैनल बनाया जायेगा एवं उसे आउटफॉल चैनल से जोड़ा जायेगा जिससे ज्यादा पानी निकल सके। इस योजना से शहरी गलियों एवं नालियों का पक्कीकरण कर परिवारों को निवास हेतु स्वच्छ माहौल तैयार किया जायेगा......क्रमशः।

टर्न-26/अशोक/11.03.2016

श्री महेश्वर हजारी : क्रमशः मुख्यमंत्री शहरी गली एवं नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का कार्यान्वयन नगर निकाय द्वारा किया जायेगा । इसके लिए नगर निकायों के कार्य प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करना भी इस योजना का महत्वपूर्ण घटक है ।

इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की वैसी गलियां एवं नालियॉं, जिसे अभी तक पक्का नहीं किया जा सका है, उनको चिन्हित कर GIS mapपर प्रदर्शित किया जायेगा ।

ऐसी बसावटें जो कि गलियों में निवास करती है, उसे मुख्य सड़क से जोड़ते हुए पक्की सड़कों का निर्माण किया जायेगा एवं नाली का निर्माण कर गली के नाली को मुख्य नाला में जोड़ा जायेगा ।

इस योजना के चयन से लेकर निर्माण तक के लिए संबंधित नगर निकाय नोडल एजेंसी होगी । नगर निकाय अपने-अपने संबद्ध क्षेत्रों में इस योजना हेतु गली एवं नाली का प्राथमिकतावार सूची एवं डी.पी.आर. तैयार कर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात् नगर

निकाय में उपलब्ध निधि से इसका निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करायेंगे।

इस नयी योजना हेतु 140.00 करोड़(एक सौ चालीस करोड़) का बजट प्रस्ताव है ।

प्रत्येक शहरी परिवार के घरों के लिए शैचालय निर्माण :-

केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक शहरी परिवार के घरों में शैचालय के निर्माण हेतु प्रति शैचालय चार हजार रूपये स्वीकृत किये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे विपक्ष के नेता लम्बी-लम्बी बातें बोलते थे, चार हजार रूपयें में किसी गरीब का शौचालय बन सकता है ? सिर्फ बातें करना और काम में परिवर्त्तित नहीं करना भारत सरका की नीयत है । जिस तरह से लोक सभा के चुनाव में जो लम्बे-लम्बी बातें किये, लेकिन आज तक धरातल पर, जमीन पर गरीबों के लिए एक भी काम नहीं उतरा और नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं , वही करते हैं- मैं समझता हूॅ कि भारत के ये पहला मुख्यमंत्री होंगे जो चुनाव में घोषणा किये और आते-आते सबसे पहला काम शराबबन्दी का काम किये- पहला मुख्यमंत्री होगा भारत में । जो कहते हैं वे करते हैं । वह व्यक्ति एक मिशाल है, उनसे सीखने की जरूरत है, उनके गुण को जो एब्जार्ब कर लेगा, वह इंसान हो जायेगा । वह व्यक्ति जिस तरह से रात दिन सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किया और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, खाते हैं बिहार का और जपते हैं गुजरात का और जब भी गुजरात, गुंजरात, गुजरात विकास कर रहा है,- बिहार इस मामलें में जिस तरह से कोंई भी यहां उद्योग-धंधा नहीं था, जिससे कि बिहार हमारा आगे बढ़ता- सिर्फ कहता था बालू है, पानी है लेकिन उस बिहार को नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद कहां से कहां तक बढ़ाने का काम किया । उनके पास जज्वा है, विजन है, जिस व्यक्ति में जज्वा और विजन रहेगा वह व्यक्ति किसी भी संस्था को आगे ले जाने का काम करेगा तो मै अपने सदन की ओर से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूॅ कि उनके महेनत के बल पर आज बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और उन्हीं की सोंच है आज नगर विास एवं आवास विभाग भी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उनका जिस तरह से देन है, नगर विकास विभाग बहुत आगे बढ़ेगा ।

जलापूर्त्ति योजना :- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य योजना अंतर्गत विभिन्न नगरनिकायों में 32 पाईप जलापूर्त्ति योजनाओं की स्वीकृति प्रदानकी गयी है, जिसका कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद को बनाया गया है । इसके क्रियान्वयन की दिशा में कार्रवाई की गयी है । 32 स्वीकृत योजनाओं मे से 31 योजनाओं यथा जहानाबाद, बिहारशरीफ, सीतामढ़ी, अररिया, सहरसा, नावादा, गोपालगंज, बगहा, मसैढ़ी, मधेपुरा, ढाका, आरा, रक्सौल, सासाराम, डुमरॉव, सुल्तानगंज, केसरिया, रामनगर, शिवहर, दाउदनगर, जगदीशपुर, विक्रमगंज, सिमरी बख्तियारपुर, विक्रम, फतुहा, इस्लामपुर, दरभंगा, मखदुमपुर, अरवल, निर्मली एवं सुपौल की निविदायें सम्पन्न होकर कार्यादेश निर्गत किये जा चुके हैं । मुंगेर जलापूर्त्ति योजना में किसी भी संवदेक द्वारा भाग नहीं लिये जाने के कारण पुनर्निविदा की गयी है, जिन 31 जलापूर्त्ति योजनाओं के कार्यादेश निर्गत हुए हैं, उनमें सभी पर कार्य प्रगति में है ।

अभी तक 62 अद्द उच्च प्रवाही नलकूप का निर्माण किया जा चुका है। 43 अद्द जलमीनारों का निर्माण कार्य प्रगति में है तथा 3,53,177 मीटर पाईप बिछाया जा चुका है । स्वीकृत प्रावधानों के शेष कार्य पूर्ण किये जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिन्हें वर्ष 2016 में पूर्ण कर लिया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में अमृत मिशन अंतर्गत स्वीकृत कुल 14 अद्द योजनाओं यथा हाजीपुर, बक्सर, आरा, बिहारशरीफ, छपरा, जहानाबाद, बगहा, मोतिहारी, सिवान, औरंगाबाद, किशनगंज, बेगूसराय, मुंगेर एवं दभंगा का क्रियान्वयन एवं राज्य योजना अंतर्गत प्रस्तावित कुल 18 अदद योजनाओं यथा मधेपुरा, मनेर, मीरगंज, सुगौली, मेहसी, हिसुआ, वारसलीगंज, बखरी, गोगरीजमालपुर, कहलगांव, सुल्तानगंज, नवीनगर, नवगछिया, वक्सर, दलसिंहसराय, पकड़ीदयाल, समस्तीपुर एवं अरेराज का डी.पी.आर. तैयार किया जा रहा है।

पटना नगर निगम में जलापूर्त्ति : पटना नगर निगम में जलापर्ति हेतु कुल 03 अद्द अतिरिक्त उच्च प्रवाही नलकूप का निर्माण किया जा रहा है एवं 12 अद्द उच्च प्रवाही नलकूप का निविदा निस्तारित कर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

पशु विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कार्य : पटना नगर निगम क्षेत्र के रामचक बैरिया में पशु विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कार्य 357.00(तीन करोड़ संतावन लाख रू0) की राशि पर किया जा रहा है । कार्य पूर्ण हो

गया है एवं इसके लोकार्पण हेतु तिथि निर्धारण विभाग द्वारा की जा रही है ।

ड्रेनेज प्लांट का रख–रखाव : बिहार राज्य जल पर्षद के 25 अद्द एवं पटना नगर निगम के 11 अद्द कुल 36 अद्द ड्रेनेज पम्पिंग प्लान्टों के रख–रखाव एवं संचालन का कार्य बिहार राज्य जल पर्षद के द्वरा किया जा रहा है ताकि पटना शहर के जल जमाव का समाधान हो सके । एन.बी.सी. सी. द्वारा निर्मित पहाड़ी ड्रेनेज पम्पिंगप्कलांट का रख–रखाव भी बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जा रहा है । पम्पिंग प्लान्ट में ए.पी.एसफ.सी. पैनल, ऊर्जा ह्रास एवं वाटर फ्लाई भल्व्स डीजल पम्पों में उच्च क्षमता के लिए अधिष्ठापन भी किया गया है ।

सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र का रख–रखाव : बिहार राज्य जल पर्षद के द्वारा पटना शहरी क्षेत्र में बेउर, सैदपुर, पहाड़ी एवं करमलीचक में निर्मित चार अद्द सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का संचालन एवं रख–रखाव बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जाता है । वहॉ प्राप्त होने वाले सीवेज को प्रभावकारी ढंग से उपचारित कर इसे प्रवाहित किया जाता है ।

विद्युत शवदाह का जीर्णोद्धार कार्य : पटना नगर में 3 अद्द यथा बांसघाट, गुलबीघाट, खाजेकला एवं वैशाली जिले के कोन्हारा घाट में अवस्थित विद्युत शवदाहगृहों का जीर्णोद्धार कर नगर निकाय को संचालन हेतु सौप दिया गया है । इसकी मरम्मति एवं रख–रखाव का कार्य एजेन्सी द्वारा ही किया जा रहा है ।

पथ निर्माण : श्री गुरू गोविन्द सिहंजी महाराज की 350 वीं जयंती जनवरी, 2017 में मनायी जायेगी । इसमें देश–विदेश से लाखें तीर्थ यात्रियों के पटना सिटी आगमन की सम्भावना है । विभाग द्वारा इसकी तैयारियों के सिलसिले में पटना सिटी क्षेत्र की 24 सड़कों के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु कुल पचपन करोड़ निनानवे लाख बेरासी हजार आठ सौ रू0 आवंटित किया गया है । सभी पथों का निर्माण पथ निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है । इस क्षेत्र मे अन्य विकास के कार्य बिहार सरकार के अन्य विभागों द्वारा भी कराये जा रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त विभिन्न नगर निकायों में पथ निर्माण योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

38 नगर निकायों में आधुनिक बस स्टेण्ड के निर्माण हेतु एक सौ चौतिस करोड़ अड़तीस लाख तिरसठ हजार रू0 की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये कुल एकानवे करोड़ चालीस लाख तिरानवे हजार रू आंटित किया गया

है । बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य बुडकों द्वारा कराया जा रहा है । दो शहरों, जहानाबाद एवं शेखपुरा में बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । अन्य शहरों में बस स्टैड निर्माण कार्य प्रगति पर है । अगले चरण में अनुमंडल मुख्यालयों में भी आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अगले चरण में अनुमंडल मुख्यालयों में भी आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त 50 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु अड़सठ करोड़ साठ लाख पचहत्तर हजार रू0 की प्रशाससनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल 50 प्रतिशत राशि संबंधित नगर निकायों को आवंटित किया जा चुका है । पटना शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने हेतु छब्बीस करोड़ छः लाख चौहत्तर हजार रू0 की लागत से 97 स्थानों में से 51 स्थानों पर इलेक्ट्रोनिक ट्रैफिक लाईट का अधिष्ठापन कार्य बुडको द्वारा पूर्ण किया जा चुका है । पटना में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल(ISBT) के निर्माण के लिए निविदा का कार्य पूर्ण हो चुका है । राज्य सरकार की गारंटी पर हुडको से ऋण लेले की कार्रवाई बुडको द्वारा की जा रही है ।

टर्न-27 - 11-03-2016-ज्योति

श्री महेश्वर हजारी :वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रस्तावित बजट :

नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के व्यय वहन हेतु कुल 34,09,36,39,000/. रुपये (चौंतीस अरब नौ करोड़ छत्तीस लाख उनचालीस हजार रुपये) का उपबंध मांग संख्या -48 के अंतर्गत प्रस्तुत है । इसमें गैर योजना व्यय के अलावे राज्य योजना एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शामिल है । इसमें गैर योजना व्यय के लिए 14,08,27,66,000/. रुपये (चौदह अरब आठ करोड़ सत्ताईस लाख छियासठ हजार रुपये) तथा योजना व्यय के लिए 20,01,08,73,000/. रुपये (बीस अरब एक करोड़ आठ लाख तिहत्तर हजार रुपये) का प्रस्ताव है ।

2- इसमें गैर योजना व्यय के अंतर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग के मुख्यालय में बजट शीर्ष 2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं, नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत 6,24,63,000/. रुपये (छः करोंड़ चौबीस लाख तिरसठ हजार रुपये) का बजट प्रस्तावित है ।

अध्यक्ष : ठीक है, समाप्त करिये ।

श्री महेश्वर हजारी : मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में से तीन निश्चय नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है ।

अध्यक्ष : आपका सम्पूर्ण वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जायेगा । वह कार्यवाही का हिस्सा बन जायेगा ।

(माननीय मंत्री का वक्तव्य परिशिष्ट-1 पर द्रष्टव्य)

श्री महेश्वर हजारी : अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट प्रस्ताव पर विचार कर इसे मंजूरी प्रदान की जाय । साथ ही जो हमारे माननीय सदस्यय ने कटौती प्रस्ताव पेश किया है वे इसे वापस लेने की कृपा करें । बहुत बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य सदन में अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटाई जाय ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ :

प्रश्न यह है कि :

"नगर विकास एवं आवास विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 34,09,36,39,000/- (चौंतीस अरब नौ करोड़ छत्तीस लाख उनचालीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनॉक 11 मार्च 2016 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 24 है अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनॉक 14 मार्च 2016 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट-1

श्री महेश्वर हजारीः माननीय अध्यक्ष महोदय,

राज्य के आर्थिक विकास में नगरों की आधारभूत संरचनाओं एवं सेवाओं की महती भूमिका होती है। गतिशील शहरी अर्थव्यवस्था समेकित रूप से राज्य के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्त्तन का कारण बनती है, साथ ही स्वस्थ मानव संसाधन के विकास में भी अभिवृद्धि करती है।

राज्य सरकार अपने संसाधनों के अन्तर्गत राज्य के नगरीय क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए सतत् एवं निरन्तर प्रयत्नशील है। बिहार में शहरीकरण अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी कम है। विगत वर्षों में शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयत्न किये गये हैं तथा बहुआयामी विकास हेतु प्राथमिकताएँ भी निर्धारित की गई हैं।

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 11 नगर निगम, 42 नगर परिषद एवं 87 नगर पंचायत कार्यरत हैं, जिन्हें राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने एवं शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए विभाग के द्वारा विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 से आगामी 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजनाएँ लागू की जा रही हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सात निश्चयों में से तीन निश्चय शामिल हैं, जो निम्नवत् है :–

1. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना :–

- इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में सभी शहरी परिवारों को पाईप जलापूर्ति के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की सघन एवं निरंतर बसे घरों के लिए पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता आधारित सतही जल/भूगर्भीय जल का उपयोग करके योजनाएँ बनायी जायेंगी। लगभग 15–20 प्रतिशत क्षमता Overhead Tank के माध्यम से सृजित की जायेंगी एवं शेष क्षमता के लिए Direct Pumping से आपूर्ति करने का प्रावधान किया जाएगा।
- शहरी स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयोजन से छोटी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा। बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा मॉडल परियोजना तैयार करके, सक्षम तकनीकी स्वीकृति के उपरांत, नगर निकायों को उपलब्ध करायी जायेंगी। नगर निकायों द्वारा उनके पास उपलब्ध निधि से वार्ड के अंदर या अंतरवार्ड महत्त्व की छोटी योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जायेगा। इस योजना के तहत कुल ₹400.00 करोड़ (चार सौ करोड़ रु०) का बजट प्रस्ताव है।

2. मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना :–

- इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में शहरी क्षेत्र के वैसी गलियों एवं नालियों, जिनका पक्का निर्माण नही हो पाया है, उसे पूरा कराया जायेगा।
- नालों के चयन के आउटफॉल एरिया को प्राथमिकता दी जायेगी। सबसे ज्यादा जल जमाव वाले स्थान पर ट्रंक चैनल बनाया जायेगा एवं उसे आउटफॉल चैनल से जोड़ा जायेगा, जिससे ज्यादा पानी निकल सके।
- इस योजना से शहरी गलियों एवं नालियों का पक्कीकरण कर परिवारों को निवास हेतु स्वच्छ माहौल तैयार किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री शहरी गली एवं नाली पक्कीकरण निश्चय योजना का कार्यान्वयन नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। इसके लिए नगर निकायों के कार्य प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करना भी इस योजना का महत्वपूर्ण घटक है।
- इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की वैसी गलियाँ एवं नालियाँ, जिसे अभी तक पक्का नही किया जा सका है, उनको चिह्नित कर GIS Map पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- ऐसी बसावटें जो कि गलियों में निवास करती हैं, उसे मुख्य सड़क से जोड़ते हुए पक्की सड़कों का निर्माण किया जायेगा एवं नाली का निर्माण कर गली के नाली को मुख्य नाला में जोड़ा जायेगा।
- इस योजना के चयन से लेकर निर्माण तक के लिए संबंधित नगर निकाय नोडल एजेंसी होगी। नगर निकाय अपने–अपने संबद्ध क्षेत्रों में इस योजना हेतु गली एवं नाली का प्राथमिकतावार सूची एवं डी०पी०आर० तैयार कर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात् नगर निकाय में उपलब्ध निधि से इसका निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करायेंगे।
- इस नयी योजना हेतु ₹140.00 करोड़ (एक सौ चालीस करोड़ रु०) का बजट प्रस्ताव है।

3. प्रत्येक शहरी परिवार के घरों के लिए शौचालय निर्माण :–

- केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक शहरी परिवार के घरों में शौचालय निर्माण हेतु प्रति शौचालय ₹4000.00 (चार हजार रु०) स्वीकृत किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा इसे निश्चय योजना का अंग मानते हुए प्रति शौचालय ₹8000.00 (आठ हजार रु०) उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार प्रत्येक शौचालय निर्माण हेतु कुल ₹12000.00 (बारह हजार रु०) दिये जायेंगे। इस योजना के लिए राज्यांश मद में ₹160.00 करोड़ (एक सौ साठ करोड़ रु०) का बजट प्रस्ताव है।

राज्य योजना :–

4. जलापूर्ति योजना :–

- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य योजना अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों में 32 पाईप जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद को बनाया गया है। इसके क्रियान्वयन की दिशा में कार्रवाई की गयी है। 32 स्वीकृत योजनाओं में से 31 योजनाओं यथा जहानाबाद, बिहारशरीफ, सीतामढ़ी, अररिया, सहरसा, नवादा, गोपालगंज, बगहा, मसौढ़ी, मधेपुरा, ढाका, आरा, रक्सौल, सासाराम, डुमरॉव, सुलतानगंज, केसरिया, रामनगर, शिवहर, दाउदनगर, जगदीशपुर, बिक्रमगंज, सिमरी बख्तियारपुर, विक्रम, फतुहा, इस्लामपुर, दरभंगा, मखदुमपुर, अरवल, निर्मली एवं सुपौल की निविदायें सम्पन्न होकर कार्यादेश निर्गत किये जा चुके है। मुंगेर जलापूर्ति योजना में किसी भी संवेदक द्वारा भाग नहीं लिये जाने के कारण पुनर्निविदा की गयी है। जिन 31 जलापूर्ति योजनाओं के कार्यादेश निर्गत हुए हैं, उनमें सभी पर कार्य प्रगति में है।

- अभी तक 62 अद्द उच्च प्रवाही नलकूप का निर्माण किया जा चुका है। 43 अद्द जलमीनारों का निर्माण कार्य प्रगति में है तथा 3,53,177 मीटर पाईप बिछाया जा चुका है। स्वीकृत प्रावधानों के शेष कार्य पूर्ण किये जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिन्हें वर्ष 2016 में पूर्ण कर लिया जायेगा।

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में अमृत मिशन अंतर्गत स्वीकृत कुल 14 अद्द योजनाओं यथा हाजीपुर, बक्सर, आरा, बिहारशरीफ, छपरा, जहानाबाद, बगहा, मोतिहारी, सिवान, औरंगाबाद, किशनगंज, बेगूसराय, मुंगेर एवं दरभंगा का क्रियान्वयन एवं राज्य योजना अंतर्गत प्रस्तावित कुल 18 अद्द योजनाओं यथा मधेपुरा, मनेर, मीरगंज, सुगौली, मेहसी, हिसुआ, वारसलीगंज, बखरी, गोगरीजमालपुर, कहलगाँव, सुल्तानगंज, नवीनगर, नवगछिया, चकिया, दलसिंहसराय, पकड़ीदयाल, समस्तीपुर एवं अरेराज का डी०पी०आर० तैयार किया जा रहा है।

- **पटना नगर निगम में जलापूर्ति** :– पटना नगर निगम में जलापूर्ति हेतु कुल 03 अद्द अतिरिक्त उच्च प्रवाही नलकूप का निर्माण किया जा रहा है एवं 12 अद्द उच्च प्रवाही नलकूप का निविदा निस्तारित कर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

- **पशु विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कार्य** :– पटना नगर निगम क्षेत्र के रामचक बैरिया में पशु विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कार्य ₹357.00 लाख (तीन करोड़ संतावन लाख रु०) की राशि पर किया जा रहा है। कार्य पूर्ण हो गया है एवं इसके लोकार्पण हेतु तिथि निर्धारण विभाग द्वारा की जा रही है।

- **ड्रेनेज प्लांट का रख–रखाव** :– बिहार राज्य जल पर्षद के 25 अद्द एवं पटना नगर निगम के 11 अद्द कुल 36 अद्द ड्रेनेज पम्पिंग प्लान्टों के रख–रखाव एवं संचालन का कार्य बिहार राज्य जल पर्षद के द्वारा किया जा रहा है ताकि पटना शहर के जल जमाव का समाधान हो सके। एन०बी०सी०सी० द्वारा निर्मित पहाड़ी ड्रेनेज पम्पिंग प्लांट का रख–रखाव भी बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जा रहा है। पम्पिंग प्लान्ट में ए०पी०एफ०सी० पैनल, ऊर्जा ह्रास एवं वाटर फ्लाई भाल्व्स डीजल पम्पों में उच्च क्षमता के लिए अधिष्ठापन भी किया गया है।

- **सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र का रख–रखाव** :– बिहार राज्य जल पर्षद के द्वारा पटना शहरी क्षेत्र में बेउर, सैदपुर, पहाड़ी एवं करमलीचक में निर्मित चार अद्द सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का संचालन एवं रख–रखाव बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जाता है। वहाँ प्राप्त होने वाले सीवेज को प्रभावकारी ढंग से उपचारित कर इसे प्रवाहित किया जाता है।

- **विद्युत शवदाह गृह का जीर्णोद्धार कार्य** :– पटना नगर में 3 अद्द यथा बाँसघाट, गुलबीघाट, खाजेकलाँ एवं वैशाली जिले के कोन्हारा घाट में अवस्थित विद्युत शवदाह गृहों का जीर्णोद्धार कर नगर निकाय को संचालन हेतु सौंप दिया गया है। इसकी मरम्मति एवं रख–रखाव का कार्य एजेन्सी द्वारा ही किया जा रहा है।

5. पथ निर्माण :–

- श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती जनवरी, 2017 में मनायी जायेगी। इसमें देश–विदेश से लाखों तीर्थ यात्रियों के पटना सिटी आगमन की सम्भावना है। विभाग द्वारा इसकी तैयारियों के सिलसिले में पटना सिटी क्षेत्र की 24 सड़कों के निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु कुल ₹5599.828 लाख (पचपन करोड़ निनानवे लाख बेरासी हजार आठ सौ रु०) आवंटित किया गया है। सभी पथों का निर्माण पथ निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। इस क्षेत्र में अन्य विकास के कार्य बिहार सरकार के अन्य विभागों द्वारा भी कराये जा रहे हैं।

- इसके अतिरिक्त विभिन्न नगर निकायों में पथ निर्माण योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

6. नागरिक सुविधा :–

- 38 नगर निकायों में आधुनिक बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु ₹13438.63 लाख (एक सौ चौतिस करोड़ अड़तीस लाख तीरसठ हजार रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल ₹9140.93 लाख (एकानवे करोड़ चालीस लाख तिरानवे हजार रु०) आवंटित किया गया है। बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य बुडको द्वारा कराया जा रहा है। दो शहरों, जहानाबाद एवं शेखपुरा में बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अन्य शहरों में बस स्टैंड निर्माण कार्य प्रगति पर है। अगले चरण में अनुमंडल मुख्यालयों में भी आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 50 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन के निर्माण हेतु ₹6860.75 लाख (अड़सठ करोड़ साठ लाख पचहत्तर हजार रु०) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल 50 प्रतिशत राशि संबंधित नगर निकायों को आवंटित किया जा चुका है। पटना शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने हेतु ₹2606.74 लाख (छब्बीस करोड़ छः लाख चौहत्तर हजार रु०) की लागत से 97 स्थानों में से 51 स्थानों पर इलेक्ट्रोनिक ट्रैफिक लाईट का अधिष्ठापन कार्य बुडको द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। पटना में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) के निर्माण के लिए निविदा का कार्य पूर्ण हो चुका है। राज्य सरकार की गारंटी पर हुडको से ऋण लेने की कार्रवाई बुडको द्वारा की जा रही है।

केन्द्र प्रायोजित योजना :–

7. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजना :–

- राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की 150वीं जन्म दिन 02 अक्टूबर, 2019 तक देश में सम्पूर्ण स्वच्छता के संकल्प के साथ भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम जारी किया गया है। यह कार्यक्रम राज्य के सभी नगर निकाय में लागू की गई है, इसके तहत निम्नलिखित कार्य किया जाना है :–

  (i) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण।
  (ii) सामुदायिक शौचालय का निर्माण।
  (iii) सार्वजनिक शौचालय का निर्माण।
  (iv) ठोस कचरा प्रबंधन।
  (v) सूचना, शिक्षा एवं जन–जागरूकता
  (vi) क्षमतावृद्धि तथा प्रशासनिक कार्य।

8. **NGRBA(राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकार) / नमामी गंगे योजना :–** यह योजना राज्य के गंगा नदी तट पर अवस्थित शहर बक्सर, पटना, हाजीपुर, बेगूसराय एवं मुंगेर में कार्यान्वित है। इसके अंतर्गत हाजीपुर, बक्सर, बेगूसराय एवं मुंगेर में Severage Treatment Plant का निर्माण एवं Sever निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जबकि पटना में गंगा नदी तट का विकास योजना चालू है। पटना में 20 गंगा घाटों को विकसित करने का कार्य जारी है। इस योजना पर लगभग ₹262.27 करोड़ (दो सौ बासठ करोड़ सताईस लाख रु०) व्यय होने की संभावना है।

9. **ADB (एशियन डेवलपमेन्ट बैंक) संपोषित भागलपुर जलापूर्ति** योजना ₹493.00 करोड़ (चार सौ तिरानवे करोड़ रु०) लागत पर स्वीकृत है। कार्यकारी एजेंसी बुडको को ₹60.00 करोड़ (साठ करोड़ रु०) विमुक्त है। इस योजना पर अबतक ₹34.30 करोड़ (चौंतीस करोड़ तीस लाख रु०) व्यय हो चुका है। गया जलापूर्ति योजना की स्वीकृति ₹376.21 करोड़ (तीन सौ छिहत्तर करोड़ इक्कीस लाख रु०) पर प्राप्त है। इन दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को 24 × 7 दिन स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो सकेगा।

10. **पटना मेट्रो रेल परियोजना :–** इस परियोजना की सैद्धान्तिक सहमति राज्य मंत्रिपरिषद् से प्राप्त हो गयी है। भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा जा रहा है।

11. **अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना :–** यह योजना राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी 26 नगर निकायों में कार्यान्वित की जानी है। इसके अंतर्गत जलापूर्ति योजना, हरित स्थल / पार्क का विकास, फुटपाथ का निर्माण आदि कार्य किया जाना है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं 20 प्रतिशत संबंधित नगर निकाय द्वारा वहन किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 432.84 करोड़ (चार सौ बत्तीस करोड़ चौरासी लाख रु०) कर्णांकित है।

12. **राजीव आवास योजना (RAY) :–** इस योजना में समरूप एवं समतुल्य शहरों वाले स्लम मुक्त भारत की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को बुनियादी नागरिक एवं सामाजिक सेवाएँ तथा समूचित आश्रय सुलभ हो। इस योजना के अधीन केवल 07 परियोजना में 11276 आवासीय इकाई स्वीकृत है, जिसका कार्य आरंभ हो चुका है। लाभुकों के बीच राशि का वितरण शिविर के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग के द्वारा कार्यकारी अभिकरण को 9619.49 लाख (छियानवे करोड़ उन्नीस लाख उन्नचास हजार रु०) दिये जा चुके हैं। अब तक छः परियोजनाओं में कुल 3107 लाभुकों का खाता खोलकर 3536.46 लाख (पैंतीस करोड़ छत्तीस लाख छियालिस हजार रु०) राशि वितरित की जा चुकी है। स्वीकृत परियोजना की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :–

(राशि लाख में)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	कुल स्वीकृत आवासीय इकाई	कुल परियोजना लागत	अब तक कुल विमुक्त राशि
1.	पटना फेज–1	759	2815.83	452.94
2.	पटना फेज–2	1061	3857.62	622.21
3.	पटना फेज–3	1073	4909.91	791.88
4.	गया फेज–1	1970	7589.80	2253.12
5.	दरभंगा फेज–1	2190	8056.43	1329.74
6.	कटिहार फेज–1	2038	8841.84	1458.38
7.	पूर्णिया फेज–1	2185	9393.97	2711.22
	कुल	**11276**	**45465.40**	**9619.49**

उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में है, केवल पटना के लिए 50:50 की हिस्सेदारी निर्धारित है।

13. सबके लिए आवास HFA (शहरी) :–

- इस योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जून, 2015 में दी गयी है। इस योजना के तहत चार घटकों में शहरी क्षेत्र के आवास विहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। HFA योजना के चार घटक हैं :–

(i) **लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण** :– योजना के अधीन वर्ष 2015–16 में 40 नगर निकायों में पाये गये 13,315 पात्र परिवार को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। आवास का निर्माण लाभूकों के द्वारा स्वयं किया जायेगा। इसके लिए

₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रु०) भारत सरकार एवं ₹50.00 हजार (पचास हजार रु०) राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी। अन्य 45 नगर निकायों से प्राप्त प्रस्तावों को भी भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(ii) **स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास** :– इस घटक के अन्तर्गत स्लम वासियों को औपचारिक शहरी व्यवस्था में लाते हुए उनको पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए स्लमों के अन्तर्गत भूमि की उपयोग क्षमता बढ़ाना है। स्लम पुनर्विकास के लिए निजी भागीदारी का चयन खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार से 1.00 लाख (एक लाख रु०) प्रति आवास की दर से अनुदान अनुमान्य होगा।

(iii) **ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी** :– इस घटक के तहत पात्र शहरी गरीबों (EWS/LIG) द्वारा आवास के निर्माण हेतु लिए गये गृह ऋण पर ऋण आधारित सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दिया जायेगा।

(iv) **भागीदारी से किफायती आवास** :– इस घटक का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा विभिन्न भागीदारी से बनाये जा रहे पक्का आवास हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। किफायती दर पर EWS वर्ग के लिए आवासों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु राज्य सरकार अपनी एजेंसियों अथवा उद्योग सहित निजी क्षेत्र के साथ भागीदारों के माध्यम से किफायती आवास परियोजनाओं की योजना तैयार कर सकती है। ऐसी परियोजनाओं में ₹1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रु०) की दर से केन्द्रीय सहायता सभी EWS आवासों के लिए उपलब्ध होगी।

14. **IHSDP (समेकित आवास एवं मलिन बस्ती का विकास कार्यक्रम) :–** IHSDP योजना के अधीन बिहार में 28 शहरों के लिए 32 परियोजनायें भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत की गयी है। इन 32 परियोजनाओं में कुल 28623 आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु कार्य चालू है। इसमें HPL (हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड) द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे 14 परियोजनाओं का काम अंतिम चरण में है। शेष 16 परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नगर निकायों के माध्यम से सीधे लाभुकों के द्वारा कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। इसके लिए शिविर के माध्यम से लाभुकों के बीच धनराशि उपलब्ध कराया जा रहा है। अबतक नगर निकायों के द्वारा कुल ₹26870.24 लाख (दो सौ अड़सठ करोड़ सत्तर लाख चौबीस हजार रु०) का व्यय किया जा चुका है। कुल स्वीकृत 28623 आवासीय इकाईयों में से अबतक 4744 आवासीय इकाई का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

15. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना :–

- वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना (NULM) लागू किया गया है। NULM योजना हेतु 42 नगर निकायों का चयन किया गया है। योजना के अधीन EST&P घटक के अन्तर्गत शहरी गरीब युवक/युवतियों को

निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त युवक/युवतियों को नियोजित एवं अनुश्रवण भी किये जाने हैं। वर्ष 2015–16 में 17054 युवक/युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और इसके Certification की प्रक्रिया जारी है। जबकि Shelter for Urban homeless के लिए 48 नये Homeless Shelter विभिन्न नगर निकाय में निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए राशि भी विमुक्त कर दी गई है। पूर्व निर्मित रैन बसेरा को मरम्मति एवं चालू करने हेतु 6.00 लाख/प्रति रैन बसेरा की दर से 66 रैन बसेरा को राशि विमुक्त की गई है। रैन बसेरा के सुचारू रूप से संचालन हेतु उसे Area Level Organization (ALO) से जोड़ा गया है। फुटपाथ दुकानदारों का सर्वेक्षण किया जा रहा है अभी तक कुल 53807 दुकानदारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। उसके हितों की देख–रेख हेतु Town Vending Committee का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक 44 Town vending Committee (TVC) का गठन हो चुका है। सर्वेक्षित दुकानदारों को पुनर्वासित करने हेतु Vending Zone चिन्हित किये जा रहे हैं। अभी तक 311 Vending zone चिन्हित किये गये हैं। 42 शहरों में Town level federation (TLF) का गठन किया जा चुका है।

16. बिहार राज्यान्तर्गत नगर निकायों के सुदृढ़ीकरण, कार्यक्षमता में वृद्धि तथा नागरिक सुविधायें त्वरित गति से उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा निम्नांकित महत्त्वपूर्ण कार्य किये गये हैं :–

- नगर निकायों/जिला शहरी विकास अभिकरणों के बेहतर प्रशासन तथा नागरिक सुविधाओं में वृद्धि तथा आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए निम्नांकित पद सृजित किये गये हैं :–

(i)	नगर कार्यपालक पदाधिकारी	–	130
(ii)	नगर प्रबंधक	–	152
(iii)	कार्यपालक अभियंता	–	35
(iv)	कनीय अभियंता	–	139
(v)	Town Planner	–	52
(vi)	MPW	–	142

- बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती नियमावली 2015 गठित की जा चुकी है एवं कनीय अभियंता के 198 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। इन नियमावलियों के गठन के पश्चात् पदसृजन से नगर निकायों का बेहतर प्रशासन तथा नागरिक सुविधाओं में अभिवृद्धि संभव होगी।

- नगर निकायों के बेहतर प्रशासन हेतु नगर प्रबंधक के कुल 152 सृजित पदों के विरूद्ध 77 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित की जा चुकी है।

- जिला शहरी विकास अभिकरणों के कुल 68 सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई है।

- नगर निकायों को प्रोत्साहित करने तथा कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु "मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष निर्धारित मापदण्डों के आधार पर

चयनित एक नगर निगम को 5.00 करोड़ रुपये, दो नगर परिषदों को 3–3 करोड़ रुपये तथा दो नगर पंचायतों को एक–एक करोड़ रुपये पुरस्कार के रुप में दिया जायेगा, जिसका उपयोग नगर निकाय स्वविवेक से नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कर सकेगी।

- नगर निकायों में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मियों हेतु वर्दी आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।
- निविदा निष्पादन में व्यापक विकेन्द्रीकरण को ध्यान में रखते हुए शहरी स्थानीय निकायों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति देने की शक्तियों में अभिवृद्धि की गई है।
- होल्डिंग टैक्स के वन टाईम सेटलमेंट हेतु व्यापक योजना कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित है।
- होल्डिंग टैक्स संग्रहण हेतु 4 प्रतिशत कमीशन के आधार पर कर संग्राहक की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना निर्गत हो चुकी है।
- नगर निकायों के बजट प्राक्कलन को विभागीय स्तर पर सारे तकनीकी, प्रशासनिक एवं व्यवहारिक बिन्दुओं पर विचार करने हेतु बजट कोषांग का गठन किया गया है।
- नगर निकायों के संसाधनों में अभिवृद्धि हेतु विभागीय स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है।
- बिहार राज्यान्तर्गत सभी नगर निकायों के कर्मियों हेतु षष्ठम वेतन पुनरीक्षण लागू किया गया है।

17. स्पर प्रोजेक्ट की उपलब्धियाँ :–

- **ई० नगरपालिका (E. Municipality)** :– ई० नगरपालिका को प्रथम चरण में 11 नगर निगमों में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर निकायों के लिए ऑनलाइन सेवाएँ जैसे जन्म–मृत्यु पंजीकरण, संपत्ति कर, भवन निर्माण योजना की स्वीकृति और विनियम, सामान्य प्रशासन (सूचना का अधिकार अधिनियम) का आरंभ किया जा चुका है।
- द्वितीय चरण में इसे सभी नगर निकायों में लागू किया जायेगा जिसके अंतर्गत कर्मियों के प्रबंध की पद्धति, निबंधन और अनुज्ञप्ति, विज्ञापन और होर्डिंग, किराया, पट्टा और सैरात, कार्यप्रवाह और दस्तावेज प्रबंधन पद्धति एवं सामान्य प्रशासन (विधि प्रबंधन, अंकेक्षण प्रबंधन, बिहार विधान मंडल के प्रश्न और उत्तर, भण्डार/गोदाम प्रबंधन और सूचना तकनीकी की मदद) का आरंभ किया जायेगा। इसे दिसम्बर, 2016 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।
- **GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली) मैप** :– GIS मैप में प्रोपर्टी के विवरण को समाहित करने हेतु मुजफरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, भागलपुर, मुंगेर, जमालपुर, किशनगंज और सहरसा शहरों में ₹646.52 लाख (छः करोड़ छियालीस लाख बावन हजार रु०) की लागत से कार्य चल रहा है। गया, औरंगाबाद, नवादा, बेगूसराय, सासाराम, डेहरी डालमियानगर, आरा, छपरा, सिवान, राजगीर, हाजीपुर और बिहारशरीफ शहरों के लिए प्रोपर्टी सर्वे के कार्य हेतु ₹1113.00 लाख (ग्यारह करोड़ तेरह लाख रु०) की लागत की निविदा किया जा चुका है। पटना, बोधगया, खगौल और दानापुर के लिए प्रोपर्टी सर्वे के कार्य हेतु ₹666.00 लाख (छः करोड़ छियासठ लाख रु०) की लागत की निविदा किया जा चुका है, जिसका व्यय AMRUT प्रोजेक्ट के तहत् वहन किया जायेगा।

- **भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित नक्शा** :– इसके लिए गया, औरंगाबाद, नवादा, बेगूसराय, सासाराम, डेहरी डालमियानगर, आरा, छपरा, सिवान, राजगीर, हाजीपुर और बिहारशरीफ शहरों के लिए GIS का कार्य ₹443.85 लाख (चार करोड़ तैतालीस लाख पच्चासी हजार रु०) की लागत से पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 40 शहरों के लिए GIS के कार्य हेतु ₹742.45 लाख (सात करोड़ बयालीस लाख पैतालीस हजार रु०) की लागत की निविदा किया जा चुका है, जिसका व्यय विभाग के ई–गवर्नेंस बजट के तहत् वहन किया जायेगा।

- **दोहरी लेखा प्रणाली (Double Entry Accounting System)** :– राज्य के सभी नगर निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली ₹411.33 लाख (चार करोड़ ग्यारह लाख तैतीस हजार रु०) के लागत पर लागू की गयी है, जो बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली पर आधारित है। इस कार्य के लिए विस्तृत दिशा निर्देश हेतु बिहार नगरपालिका लेखा हस्तक की राज्य मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त नगर निकायों में संपत्ति कर के स्व–निर्धारण पद्धति को लागू किया गया है। सभी नगर निकायों में ₹82.90 (बेरासी लाख नब्बे हजार रु०) लाख की लागत से आंतरिक अंकेक्षण का कार्य कराया जायेगा।

- **SPUR (सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अरबन रिफॉर्म) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य योजनाएँ** :– 6 शहरों में लगभग ₹312.77 करोड़ (तीन सौ बारह करोड़ सतहत्तर लाख रु०) राशि की इंटरसेपशन एवं डाइवरजन (I&D) सीवरेज योजनाएँ एवं 4 शहरों में लगभग ₹181.90 करोड़ (एक सौ एकासी करोड़ नब्बे लाख रु०) राशि की River Front Development योजनाएँ भारत सरकार को स्वीकृति एवं वित्तपोषण हेतु भेजी गयी है। 1402 मलीन बस्तियों में आधारभूत संरचना कार्यों हेतु ₹401.74 करोड़ (चार सौ एक करोड़ चौहत्तर लाख रु०) की स्वीकृति जारी की गयी थी, जिसके अंतर्गत कुल 505 मलीन बस्तियों में आधारभूत संरचना कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है एवं ₹107.03 करोड़ (एक सौ सात करोड़ तीन लाख रु०) 27 स्पर निकायों को स्थानांतरित किया गया है। स्वीकृत कार्यों के अंतर्गत 3545 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण सामूहिक विकास समिति द्वारा कराया गया एवं अन्य 1622 व्यक्तिगत शौचालय निर्माणाधीन है। 8 नगर निकायों में मलीन बस्तियों में कराये जा रहे आधारभूत संरचना कार्यों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु ₹2.10 करोड़ (दो करोड़ दस लाख रु०) की लागत से एजेंसी नियुक्त की गयी है।

- इसके अतिरिक्त 35 शहरों में लगभग ₹2097.00 करोड़ (दो हजार सन्तानवे करोड़ रु०) राशि की ठोस कचरा प्रबंधन की योजनाएँ, 8 शहरों में लगभग ₹812.04 करोड़ (आठ सौ बारह करोड़ चार लाख रु०) राशि की इंटरसेपशन एवं डाइवरजन (I&D) सीवरेज योजनाएँ, 4 शहरों में लगभग ₹1082.38 करोड़ (एक हजार बेरासी करोड़ अड़तीस लाख रु०) राशि की River Front Development योजनाएँ, 23 शहरों में लगभग ₹5500.00 करोड़ (पाँच हजार पाँच सौ करोड़ रु०) की सीवरेज योजनाएँ एवं 12 शहरों की ₹174.29 करोड़ (एक सौ चाहत्तर करोड़ उनतीस लाख रु०) की लागत से शवदाह गृह, धोबीघाट तथा सामुदायिक शौचालयों की योजनाएँ बनायी गयी हैं। उपरोक्त सभी योजनाओं को स्वीकृति हेतु भारत सरकार की विभिन्न मिशन योजनाओं, यथा– स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, अमृत के अंतर्गत वित्तपोषण हेतु भारत सरकार को भेजा जायेगा।

18. विभाग की कई योजनाओं का कार्य बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास लि० (BUIDCO) द्वारा पूर्ण कराया जा चुका है, जो निम्नवत् है :–

- राजगीर सिवरेज सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- कंकड़बाग, शास्त्रीनगर, अनिशाबाद में पार्क का विकास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- पटना सहित 08 नगर निगमों, 01 नगर परिषद् तथा 03 नगर पंचायत में एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स, पटना का नवीनिकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- राजगीर में दो स्थानों पर बोधगया में चार स्थानों पर तथा गया में एक स्थान पर डीलक्स शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- जहानाबाद तथा शेखपुरा में बस टर्मिनल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 29 शहरों में बस टर्मिनल का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।
- पटना शहर में 117 स्थानों पर Bus Que Shelter का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
- पटना शहर में 97 स्थानो में से 51 स्थानों पर ट्रैफिक लाईट सिस्टम का कार्य पूर्ण हो चुका है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम का कार्य भी पूर्ण हो चुका है।
- पटना शहर में बुद्ध स्मृति पार्क के पास मल्टी लेवल पार्किंग तथा पार्किंग तक पहुँच पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- पटना शहर में लोहानीपुर एवं खाजेकलां पेयजल आपूर्ति योजनाओं का आरम्भ किया जा चुका है।
- बुडको के सतत् प्रयास से ऐसी आशा की जा सकती है कि शहरों के समेकित विकास से अधिकांश शहर अगले पाँच वर्षों में लाभान्वित हो जायेंगे।

19. बिहार राज्य आवास बोर्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं :–

- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा बिहार के विभिन्न शहरों में अर्जित संपदाओं को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की दिशा में सार्थक पहल की गयी है। इससे संपदाओं के मूल्यों का निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत राशि देकर, आवंटी संपदाओं का लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित करा सकते है।
- दलपतपुर आरा के 16.50 एकड़ भूखण्ड पर 1054 फ्लैटों के निर्माण हेतु माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार द्वारा शिलान्यास किया जा चुका है। कार्यारम्भ की कार्रवाई अंतिम चरण में है।
- बरारी, भागलपुर आवासीय कॉलोनी के 3.72 एकड़ भूखण्ड पर कुल 272 फ्लैटों के निर्माण हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
- सभी के लिए आवास (शहरी) योजना के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड को नोडल एजेंसी मनोनीत किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में बोर्ड की संपदाओं के आवंटन के लिए आरक्षण नीति लागू किया जायेगा। जितवारपुर, समस्तीपुर में अर्जित भूखण्डों को आवासीय, व्यावसायिक एवं आवासीय–सह–व्यावसायिक भूखण्डों में चिह्नित कर आरक्षण नीति के आधार पर आवंटित किया जायेगा।

20. वित्तीय वर्ष 2016–17 में नगर विकास एवं आवास विभाग का प्रस्तावित बजट :–

(i) नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के व्यय वहन हेतु कुल ₹34,09,36,39,000/– (चौंतीस अरब नौ करोड़ छत्तीस लाख उनचालीस हजार रुपये) का उपबंध माँग संख्या– 48 के अंतर्गत प्रस्तुत है। इसमें गैर योजना व्यय के अलावे राज्य योजना एवं केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शामिल है। इसमें गैर योजना व्यय के लिए ₹14,08,27,66,000/– (चौदह अरब आठ करोड़ सताईस लाख छियासठ हजार रुपये) तथा योजना व्यय के लिए ₹20,01,08,73,000/– (बीस अरब एक करोड़ आठ लाख तिहत्तर हजार रुपये) का प्रस्ताव है।

(ii) इसमें गैर योजना व्यय के अंतर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग के मुख्यालय में बजट शीर्ष 2251–सचिवालय सामाजिक सेवाएँ, नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत ₹6,24,63,000/– (छः करोड़ चौबीस लाख तिरसठ हजार रुपये) का बजट प्रस्तावित है।

(iii) मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में से तीन निश्चय नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है। राज्य योजना व्यय के तहत "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" के लिए ₹400.00 करोड़ (चार सौ करोड़ रु०), "मुख्यमंत्री शहरी नाली–गली पक्कीकरण निश्चय योजना" के लिए ₹140.00 करोड़ (एक सौ चालीस करोड़ रु०) तथा प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण योजना हेतु राज्यांश के रूप में ₹160.00 करोड़ (एक सौ साठ करोड़ रु०) अर्थात् कुल ₹ 700.00 करोड़ (सात सौ करोड़ रु०) का बजट प्रस्तावित है।

(iv) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि सहित NULM योजना में ₹7500.00 लाख (पचहत्तर करोड़ रु०), सबके लिए आवास योजना में ₹20961.00 लाख (दो सौ नौ करोड़ एकसठ लाख रु०), AMRUT योजना में ₹43284.00 लाख (चार सौ बत्तीस करोड़ चौरासी लाख रु०) तथा राजीव आवास योजना में ₹14725.00 लाख (एक सौ सैंतालीस करोड़ पच्चीस लाख रु०) का प्रस्ताव है।

मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट प्रस्ताव पर विचार कर इसे मंजूरी प्रदान की जाय।